# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 14 जुलाई, 2023

आषाढ़ 23, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग–1

संख्या 1044 / सत्तर-1–2023-20(29)-2020

लखनऊ, 14 जुलाई, 2023

### अधिसूचना

प०आ०–542

चूँकि, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2023) द्वारा यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) के माध्यम से श्री जगदीश जनकल्याण एजूकेशनल ट्रस्ट, शिकोहाबाद–फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित अग्रवन हेरीटेज यूनिवर्सिटी, आगरा, उत्तर प्रदेश नामक एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।

अतएव, अब पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल पूर्वोक्त विश्वविद्यालय को आगरा, उत्तर प्रदेश में अग्रवन हेरीटेज यूनिवर्सिटी, आगरा, उत्तर प्रदेश के नाम से चलाने की अनुज्ञा देती हैं।

आज्ञा से,

एम० पी० अग्रवाल,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1044/LXX-1-2023-20(29)-2020, dated July 14, 2023.

No. 1044/LXX-1-2023-20(29)-2020

*Dated Lucknow, July 14, 2023*

WHEREAS a private University with the name of Agrawan Heritage University, Agra, Uttar Pradesh sponsored by Shri Jagdish Jankalyan Educational Trust, Shikohabad, Firozabad, Uttar Pradesh has been established *vide* the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019), as amended by the Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 6 of 2023).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 7 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to permit the aforesaid University to operate with the name Agrawan Heritage University, Agra, Uttar Pradesh in Agra, Uttar Pradesh.

By order,
M. P. AGRAWAL,
*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 654 राजपत्र–2023–(1975)–599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 6 सा० शिक्षा–2023–(1976)–200 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
654 RPH 2023 (Shiksha anu. 1) Data Je

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली – 110 002
Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi – 110 002
Phone : 011-2360 4407, 011-2360 4424

By Speed-Post

No.F.8-34/2023(CPP-I/PU)

October, 2023

27 OCT 2023

The Chief Trustee
Shri Jagdish Jan Kalyan Educational Trust
Behind Roadways Mehra Colony
Shikohabad-Firozabad, Uttar Pradesh.

Subject - Establishment of Agrawan Heritage University, Agra, Uttar Pradesh – regarding.

Sir,

Kindly refer to your letter dated 05.07.2023 on the subject cited above. In this regard it has been noticed that Agrawan Heritage University, Agra, Uttar Pradesh has been established by the Government of Uttar Pradesh under Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act No.12 of 2019), as amended by the Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance No.6 of 2023).

It is to inform you that Section 2(f) of the UGC Act, 1956 stipulates *"a University means a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, and includes any such institutions as may, in consultation with the University concerned, be recognized by the Commission in accordance with the regulations made in this behalf under this Act"*.

Since the university has been established through an Ordinance and not through an Act, the following document/information is required:

1. Copy of Act passed by the State Legislature for establishment of University duly attested by the Vice Chancellor/Registrar of the University;
2. Attested copy of Notification issued by the Government of Uttar Pradesh in respect of Act passed by the State Legislature for establishment of University;
3. Contact details including official email IDs and mobile numbers of Vice Chancellor and Registrar of the University.
4. Official email ID of University and web address of the website of University.
5. Complete postal address of the main campus of the University
6. *The documents/information* should be sent by the Vice Chancellor/Registrar of the *University on the official letter head of university.*

Yours faithfully,

26/X/23

(R.I.S. Bhardwaj)
Under Secretary

06 DEC. 2023

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–1
सख्या-231/सत्तर–1–2021–20(3)/2021
लखनऊः दिनांकः 25 सितम्बर, 2023

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2023) के द्वारा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधायी अनुभाग–1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–423/79–वि–1–2023–1–(क)–9–2023 (छायाप्रति संलग्न) दिनांक 21.08.2023 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियां निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली–11001
2– अपर मुख्य सचिव, मा0 राज्यपाल, राजभवन, उ0प्र0।
3– अपर मुख्य सचिव, वित्त/कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4– प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5– प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6– सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
7– सचिव, एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज, फिरोजशाह कोटला मार्ग, नई दिल्ली–110002।
8– सचिव, बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, 21 राउज एवेन्यू उर्दूघर मार्ग, नई दिल्ली–110002।
9– क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
10– सचिव, नेशनल मेडिकल काउन्सिल, नई दिल्ली।
11– सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली।
12– सचिव, इंडियन नर्सिंग काउन्सिल, नई दिल्ली।
13– सचिव, फार्मेसी काउन्सिल आफ इंडिया।
14– रजिस्ट्रार, जनरल, उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।
15– रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।
16– कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
17– कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
18– निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
19– अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सम्बन्धित को अधिसूचना परिचालित करें तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
20– निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
21– निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
22– समस्त अधिकारी/अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
23– गार्ड फाइल।

**संलग्नक–यथोक्त**

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 21 अगस्त, 2023

श्रावण 30, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

---

संख्या 423/79-वि-1–2023-1-(क)-8-2023

लखनऊ, 21 अगस्त, 2023

---

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2023 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 17 अगस्त, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2023 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2023)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 27 जून, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की अनुसूची–2 में क्रम संख्या 30 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भों को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा और क्रम संख्या 30 के पश्चात् नव स्थापित विश्वविद्यालय के लिये निम्नलिखित क्रम संख्यायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

| क्र० सं० | विश्वविद्यालय का नाम | प्रायोजक निकाय का नाम |
|---|---|---|
| 31 | अग्रवन हेरीटेज विश्वविद्यालय, आगरा, उत्तर प्रदेश | श्री जगदीश जन कल्याण एजूकेशनल ट्रस्ट, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश |
| 32 | महावीर विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश | न्यू ट्यूप्लस एजूकेशनल सोसाइटी, मेरठ, उत्तर |
| 33 | एस०डी०जी०आई० ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश | सुन्दर दीप एजूकेशनल सोसाइटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश |

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

3–(1) राज्य सरकार अग्रवन हेरीटेज विश्वविद्यालय, आगरा, उत्तर प्रदेश अथवा महावीर विश्वविद्यालय, मेरठ उत्तर प्रदेश अथवा एस०डी०जी०आई० ग्लोबल, विश्वविद्यालय, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश देती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा;

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

4–(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2023 उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 तथा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2023, 7 सन् 2023 तथा 8 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

## उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने एवं उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 ) अधिनियमित किया गया है।

तीन नये निजी विश्वविद्यालयों, अर्थात (एक) अग्रवन हेरीटेज विश्वविद्यालय, आगरा, उत्तर प्रदेश (दो) महावीर विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश और (तीन) एस०डी०जी०आई० ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की स्थापना का उपबंध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कारवाई आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 जून, 2023 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2023), उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2023) एवं उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2023 ) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 423 (2)/LXXIX-V-1–2023-1(ka)-8-2023
*Dated Lucknow, August* 21, 2023

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 2023) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 17, 2023. The Uccha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

# THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2023

(U.P. Act No. 8 of 2023)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act,* 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy Fourth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and Commencement

1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from June 27, 2023.

Amendment of Schedule 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

2. In Schedule 2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter referred to as the "principal Act") *after* serial no. 30, the Columns of the said Schedule shall be amended as below and after serial no. 30 for the newly established Universities the following serial numbers shall be *inserted*, namely :-

| Sl. no. | Name of the University | Name of the Sponsoring Body |
|---|---|---|
| 31 | Agrawan Heritage University, Agra, Uttar Pradesh | Shri Jagdish Jankalyan Educational Trust, Shikohabad, Firozabad, Uttar Pradesh |
| 32 | Mahaveer University, Meerut, Uttar Pradesh | New Tuples Educational Society, Meerut, Uttar Pradesh |
| 33 | SDGI Global University, Ghaziabad, Uttar Pradesh | Sunder Deep Educational Society, Ghaziabad, Uttar Pradesh |

Power to remove difficulties

3. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of Agrawan Heritage University, Agra, Uttar Pradesh or Mahaveer University, Meerut, Uttar Pradesh or SDGI Global University, Ghaziabad, Uttar Pradesh by order published in the *Gazette* direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of State Legislature as soon as may be after it is made.

Repeal and Saving

U.P. Ordinance no. 6 of 2023, 7 of 2023 and 8 of 2023

4. (1) The Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Ordinance, 2023, The Uttar Pradesh Private Universities (Second Amendment) Ordinance, 2023 and the Uttar Pradesh Private Universities (Third Amendment) Ordinance, 2023 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing Private Universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to Provide for the establishment of three new Private Universities namely:- (i) Agrawan Heritage University, Agra, Uttar Pradesh ; (ii) Mahaveer University, Meerut, Uttar Pradesh; and (iii) SDGI Global University, Ghaziabad, Uttar Pradesh it was decided to amend Schedule-2 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 6 of 2023), the Uttar Pradesh Private Universities (Second Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 7 of 2023) and the Uttar Pradesh Private Universities (Third Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 8 of 2023) were promulgated by the Governor on June 27, 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
*Pramukh Sachiv.*

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019

Act 12 of 2019

Keyword(s):
Academic Council, AICTE, CSIR, DST, Employee, Executive Council, Faculty, ICAR, Records and Publications, UGC

Amendments appended: 17 of 2021, 18 of 2021, 3 of 2022, 4 of 2022, 8 of 2023, 9 of 2023, 10 of 2023, 20 of 2023, 1 of 2024, 11 of 2024, 12 of 2024, 13 of 2024 18 of 2024, 19 of 2024, 20 of 2024, 21 of 2024

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on acc□□□ □□ □nor not taken on the basis of this document.

क्रम संख्या–151 (ख-2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

**भाग–1, खण्ड (क)**

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, मंगलवार, 6 अगस्त, 2019**

**श्रावण 15, 1941 शक सम्वत्**

**उत्तर प्रदेश शासन**

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1451/79-वि-1–19-1(क)11-19

लखनऊ, 6 अगस्त, 2019

अधिसूचना

**विविध**

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 5 अगस्त, 2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने तथा उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

### अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2019 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2–जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में.–

(क) "विद्यापरिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् से है;

(ख) "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्" (ए0आई0सी0टी0ई0) का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से है;

(ग) "बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय बोर्ड और नियोजन बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से है;

(घ) "वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्" (सी0एस0आई0आर0) का तात्पर्य वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली से है जो केन्द्र सरकार की एक निधि प्रदानकर्ता अभिकरण है ;

(ङ) "विभाग" का तात्पर्य किसी अध्ययन विभाग से है जिसमें अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र सम्मिलित है;

(च) "निदेशक" का तात्पर्य किसी संस्था, केन्द्र या विद्यालय के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजनार्थ नियुक्त व्यक्ति से है;

(छ) "विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग" का तात्पर्य केन्द्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से हैं;

(ज) "कर्मचारी" में विश्वविद्यालय के अध्ययन तथा अध्यापनेतर कर्मचारिवृन्द सम्मिलित हैं;

(झ) "कार्यपरिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् से है;

(ञ) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(ट) ""शासी निकाय" का तात्पर्य प्रायोजक निकाय द्वारा गठित किसी समिति से है;

(ठ) "छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थियों/छात्रों के छात्रावास से है;

(ड) "भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्" (आई0सी0ए0आर0) का तात्पर्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से है;

(ढ) "संस्थान/स्कूल" का तात्पर्य इस अधिनियम तथा परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी संस्थान या स्कूल से है;

(ण) "भारतीय चिकित्सा परिषद्" (एम0सी0आई0) का तात्पर्य भारतीय चिकित्सा परिषद्, 1956 के अन्तर्गत गठित भारतीय चिकित्सा परिषद से है;

(त) "अल्पसंख्यक निजी विश्वविद्यालय" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के किसी धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित किसी निजी विश्वविद्यालय से है;

(थ) "राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्"(एन0ए0ए0सी0) का तात्पर्य राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद से है ;

(द) "राष्ट्रीय कैडेट कोर" (एन0सी0सी0) का तात्पर्य राष्ट्रीय कैडेट कोर से है;

(ध) "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्" (एन0सी0टी0ई0) का तात्पर्य राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से है ;

(न) "राष्ट्रीय सेवा योजना" (एन0एस0एस0) का तात्पर्य राष्ट्रीय सेवा योजना से है ;

(प) "भारतीय भेषजी परिषद्" (पी0सी0टी0) का तात्पर्य भारतीय भेषजी परिषद अधिनियम, 1948 की धारा 4 के अधीन गठित भारतीय भेषजी परिषद् से है ;

(फ) "कुलाधिपति या अध्यक्ष", "प्रति कुलाधिपति या उपाध्यक्ष", "कुलपति और "प्रति कुलपति" का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के "कुलाधिपति" या "अध्यक्ष", "प्रति कुलाधिपति या उपाध्यक्ष", "कुलपति" और "प्रति कुलपति" से है ;

(ब) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है ;

(भ) "अभिलेखों और प्रकाशनों" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;

(म) "विनियामक निकाय" का तात्पर्य समय–समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित सांविधिक निकायों से है, यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय बार काउंसिल, दूरस्थ शिक्षा परिषद्, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्, भारतीय परिचर्या परिषद्, भारतीय चिकित्सा परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् तथा भारतीय भेषजी परिषद् सम्मिलित हैं ;

(य) "अनुसूची" का तात्पर्य इस अधिनियम से संलग्न "अनुसूची" से है;

(कक) इस अधिनियम के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित "प्रायोजक निकाय" का तात्पर्य :-

(एक) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी से है ;

(दो) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1882) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सार्वजनिक न्यास से है ;

(तीन) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 8 सन् 2013) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कम्पनी से है ;

(कख) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" और "विनियमों" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः "परिनियमों", "अध्यादेशों" और "विनियमों" से है;

(कग) "छात्र" का तात्पर्य विश्वविद्यालय में नामांकित किसी छात्र से है;

(कघ) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" का तात्पर्य आचार्यों, सह आचार्यों, सहायक आचार्यों और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है, जिन्हें विश्वविद्यालय में शिक्षा सम्बंधी अनुदेश प्रदान करने या शोध संचालित करने के लिए नियुक्त किया जाय और अध्यादेशों द्वारा अध्यापकों के रूप में पदाभिहित किया जाय;

(कङ) "कोषाध्यक्ष", "कुलसचिव", "वित्त अधिकारी", "परीक्षा नियन्त्रक", "पुस्तकालयाध्यक्ष" या "कुलानुशासक" का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियन्त्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है;

(कच) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित या निगमित किसी निजी विश्वविद्यालय से है;

(कछ) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा–4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है;

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

3–इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों के लिये प्रायोजक निकाय को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :–

(क) न्यूनतम 5 (पाँच) करोड़ रूपये की स्थायी विन्यास निधि सृजित करना ;

(ख) विश्वविद्यालय के लिए चिह्नित नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम बीस एकड़ अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम पचास एकड़ की संलग्न भूमि सम्यक् रूप से धारित करना :

परन्तु यह कि प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली हेतु ऐसी भूमि अथवा उसके किसी आंशिक भाग का विक्रय, अन्तरण अथवा पट्टा नहीं करेगा और न ही इस अधिनियम में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये इसका उपयोग करेगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऋण प्राप्त करने से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये स्थापित बैंक एवं वित्तीय संस्था से भिन्न किसी व्यक्ति को बंधक नहीं रखा जायेगा।

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम चौबीस हजार वर्ग मीटर के फर्शी क्षेत्रफल में भवन का निर्माण करना, जिसमें से कम से कम पचास प्रतिशत क्षेत्रफल का उपयोग शैक्षणिक तथा प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये किया जायेगा;

(घ) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भवन के कार्यालयों और प्रयोगशालाओं में न्यूनतम 2 (दो) करोड़ रूपये के उपस्कर, कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां, खण्ड (ख) में उल्लिखित भवनों से भिन्न अवसंरचनात्मक सुविधायें तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां प्रतिष्ठापित करना तथा आगामी पाँच वर्षों में न्यूनतम 6 (छः) करोड़ रूपये के कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां तथा अवसंरचनात्मक सुविधायें [उपरोक्त (ख) में उल्लिखित भवन को छोड़कर] तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां उपाप्त करने के लिए उपक्रम प्रतिष्ठापित करना;

(ङ) प्रत्येक विभाग या शाखा में विनियामक निकायों द्वारा यथाविहित आचार्यों, सह–आचार्यों तथा सहायक आचार्यों और सहायक कर्मचारिवृन्द के सदस्यों की नियुक्ति करना। प्रत्येक विभाग/शाखा में कम से कम पचहत्तर प्रतिशत नियमित अध्यापक विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारी होंगे ;

(च) पुस्तकालय हेतु प्रत्येक वर्ष दस लाख रूपये मूल्य की पुस्तकें व पत्रिकाओं तथा ऑनलाइन संसाधनों को क्रय करना :

परन्तु यह कि दस लाख रूपये के व्यय में कमी होने की स्थिति में इसकी प्रतिपर्ति अगले वर्ष में की जायेगी:

(छ) विनियामक निकायों के मानकों के अनुसार छात्रों के लिए पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों, पाठ्यचर्या से भिन्न गतिविधियों, वाद–विवाद प्रतियोगिताओं, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों, खेल–कूदों, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर की व्यवस्था करना;

(ज) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय बार काउंसिल और केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों और विनियमों के अनुरूप होना;

(झ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों तथा अध्यापकों के लिए भविष्य निधि स्थापित करना तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ करना;

(ञ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और कार्यप्रणाली के लिये परिनियम, अध्यादेश और विनियम बनाना ;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा की गई कोई व्यवस्था इस अधिनियम तथा विनियामक निकायों के उपबन्धों से असंगत नहीं होगी;

(ठ) विश्वविद्यालय की पारदर्शी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना और विनियामक निकायों से प्राप्त अनापत्तियों को सार्वजनिक करना;

(ड) राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित प्रारूप और समय पर राज्य सरकार को सूचना उपलब्ध कराना ;

(ढ) सामान्य शैक्षणिक कैलेण्डर, नकल रोकने के उपायों, प्रवेशों, परीक्षाओं, उपाधियों एवं प्रमाण–पत्रों आदि के लिये राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रतिमानों का अनुपालन करना;

(ण) विश्वविद्यालय में प्रवेश तथा फीस संरचना की पारदर्शी प्रक्रिया तथा मानक का विनिश्चय प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व किया जायेगा तथा सार्वजनिक किया जायेगा। प्रवेश का अंतिम दिनांक, सामान्य शैक्षणिक कैलेण्डर के अनुसार होगा।

विदेशी छात्रों की प्रवेश नीति का विनिश्चय विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् द्वारा किया जायेगा जो राज्य सरकार तथा विनियामक निकायों द्वारा अधिकथित मानकों के अनुरूप होगी;

(त) यथाविहित सामान्य शैक्षणिक कैलेण्डर का अनुसरण करना ; और

(थ) इस अधिनियम के अनुरूप ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करने का दायित्व ग्रहण करना, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व अधिकथित किया जाय ;

(द) विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर अथवा विश्वविद्यालय के नाम से राष्ट्रविरोधी क्रियाकलाप करने या उनका सम्वर्द्धन करने में किसी व्यक्ति को न तो संलिप्त होने और न ही उसकी अनुज्ञा देने का वचन देना। विश्वविद्यालय में पाये गये ऐसे किसी क्रियाकलाप के मामले में, इसे विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की शर्तों का महा उल्लंघन माना जायेगा और सरकार इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही कर सकती है :

किसी नये विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना

4–(1) कोई विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु प्रस्ताव और परियोजना रिपोर्ट से अन्तर्विष्ट आवेदन, प्रायोजक निकाय द्वारा, समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) परियोजना रिपोर्ट में निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात् :–

(क) प्रायोजक निकाय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र तथा उपविधियों की प्रतियों सहित प्रायोजक निकाय का विवरण;

(ख) प्रायोजक निकाय से वित्तीय संसाधनों से सम्बन्धि सूचना तथा पिछले तीन वर्षों की लेखा परीक्षित लेखा;

(ग) प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम व स्थान;

(घ) विश्वविद्यालय के उद्देश्य;

(ङ) भूमि की उपलब्धता और भवनों तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विवरण और भूमि, भवन तथा स्वामित्व प्राप्त करने तथा सृजन किये जाने हेतु प्रस्तावित अन्य अवसंरचना का विवरण;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा उपक्रमित किये जाने हेतु प्रस्तावित अध्ययन तथा अनुसंधान के कार्यक्रमों की प्रकृति तथा उनका प्रकार और राज्य के विकास सम्बन्धी लक्ष्यों तथा नियोजन सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु उनकी प्रासंगिकता और पाठ्यक्रमवार नामांकन लक्ष्यों सहित प्रथम पांच वर्षों से अधिक के ऐसे कार्यक्रमों को चरणबद्ध किया जाना ;

(छ) अध्यापन तथा अध्यापनेत्तर कर्मचारियों सहित प्रस्तावित शैक्षणिक सुविधाओं का विवरण ;

(ज) प्रारंभ किये जाने हेतु प्रस्तावित सुविधाएं, पाठ्यक्रम तथा अनुसंधान;

(झ) प्रायोजक निकाय को उपलब्ध सम्बन्धित शाखाओं में अनुभव तथा विशेषज्ञता ;

(ञ) विश्वविद्यालय को क्रियाशील होने से पूर्व दायित्व ग्रहण किये जाने वाले परिसर के विकास हेतु योजनाओं का विवरण यथा–भवन निर्माण, संरचनात्मक सुख सुविधाओं का विकास, अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा उपकरणों आदि का उपापन और प्रथम पांच वर्षों के लिये चरणबद्ध कार्यक्रम;

(ट) आगामी पांच वर्षों के लिये प्रस्तावित पूंजीगत व्यय के लिये चरणबद्ध परिव्यय ;

(ठ) साधन जुटाने की योजना सहित निधियों के स्रोत तथा उनकी पूँजीगत लागत तथा ऐसे स्रोतों के प्रतिसंदाय की रीति;

(ड) प्रथम संचालन वर्ष में विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छात्रों का चयन करने हेतु अपनायी जाने वाली प्रस्तावित प्रणाली;

(ढ) विश्वविद्यालय में अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अपनायी जाने वाली प्रस्तावित प्रणाली ;

(ण) क्या विश्वविद्यालय का स्थानीय आवश्यकताओं से सम्बन्धित कोई कार्यक्रम उपक्रमित करने का प्रस्ताव है, यदि ऐसा है तो ऐसे उद्देश्य की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय द्वारा उपक्रमित किये जाने वाले विशिष्ट अध्यापन, प्रशिक्षण या अनुसंधान सम्बन्धी गतिविधियों की प्रकृति ;

(त) क्या विश्वविद्यालय का कृषकों, महिलाओं तथा स्थानीय उद्योगों की प्रसुविधा के लिए कोई कार्यक्रम प्रस्तावित करने का प्रस्ताव है, यदि ऐसा है तो उसका विवरण प्रस्तुत किया जाय ;

(थ) खेल–कूद एवं क्रीड़ा तथा पाठ्येत्तर क्रियाकलाप यथा एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, रोवर एण्ड रेंजर आदि हेतु उपलब्ध तथा सृजित किये जाने हेतु प्रस्तावित क्रीड़ा स्थलों तथा अन्य सुविधाओं का विवरण;

(द) शैक्षिणक उत्कृष्टता, यदि कोई हो, के लिये प्रस्तावित व्यवस्था;

(ध) ऐसे अन्य विवरण, जिसे प्रायोजक निकाय देना चाहे;

(न) ऐसे अन्य विवरण, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिश्चित किया जाय।

मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जाना

5–(1) किसी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु परियोजना रिपोर्ट सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार का उच्च शिक्षा विभाग एक समिति गठित करेगा, जो निम्नवत् होगी :–

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन स्थापित किसी राज्य विश्वविद्यालय का एक कुलपति;

(ख) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य विश्वविद्यालय का एक आचार्य ;

(ग) उत्तर प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव से अनिम्न श्रेणी का एक अधिकारी ;

(घ) उत्तर प्रदेश शासन के वित्त एवं लेखा-सेवा के संयुक्त निदेशक की श्रेणी से अनिम्न एक अधिकारी;

(ङ) सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट परगना मजिस्ट्रेट की श्रेणी से अनिम्न एक अधिकारी ;

(च) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय का एक कुलसचिव।

(2) समिति प्रायोजक निकाय की वित्तीय सबलता और आस्तियों तथा प्रस्तावित विश्वविद्यालय स्थापित करने की उसकी सम्पूर्ण योग्यता सहित प्रस्ताव एवं परियोजना रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(3) समिति प्रस्ताव तथा परियोजना रिपोर्ट पर विचार करते समय प्रायोजक निकाय से ऐसी अन्य सूचनाएं, जिन्हें वह इस प्रयोजन के लिये उचित समझे, मांग कर सकती है।

(4) समिति, अपने गठन के दिनांक से 03 माह की अवधि के भीतर राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी:

परन्तु यह कि यदि समिति, लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले किन्ही पर्याप्त कारणों से उक्त 03 माह की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत न कर सके तो वह अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को अग्रतर 01 माह या ऐसी अवधि जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञात की जाय, के भीतर प्रस्तुत कर सकती है:

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व राज्य सरकार के आदेशों के अधीन गठित किसी समिति द्वारा किये गये निरीक्षण, उपधारा (1) के अधीन गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किये गये निरीक्षण समझे जायेंगे।

आशय–पत्र का जारी किया जाना और प्रायोजक निकाय द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना

6–(1) धारा 5 के अधीन गठित समिति की आख्या प्राप्त होने के पश्चात यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना औचित्यपूर्ण है तो वह आशय–पत्र जारी कर सकती है।

(2) प्रायोजक निकाय धारा 3 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं और शर्तों को पूर्ण करेगा और राज्य सरकार को उसकी अनुपालन आख्या प्रतिशपथ–पत्र के साथ आशय–पत्र जारी किये जाने के दिनांक से अधिकतम दो वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।

(3) यदि प्रायोजक निकाय धारा 3 के उपबन्धों का अनुपालन करने में विफल रहता है तो, राज्य सरकार प्रायोजक निकाय को जारी किये गये आशय–पत्र को वापस लेने की शक्ति प्राप्त होगी।

नये विश्वविद्यालय की स्थापना अथवा निगमन

7–(1) धारा 3 के अधीन प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचार करने के पश्चात यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि प्रायोजक निकाय ने धारा 6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का अनुपालन किया है तो वह गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा आशय–पत्र के अनुसार नाम और स्थान से संचालित करने की विश्वविद्यालय को अनुज्ञा दे सकता है।

(2) इस अधिनियम के अधीन स्थापित किये जाने वाले नये विश्वविद्यालयों के नाम, इस अधिनियम में संशोधन करके अनुसूची में सम्मिलित किये जायेंगे।

(3) विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के पश्चात नव स्थापित विश्वविद्यालय के नाम राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची 2 में उल्लिखित अंतिम विश्वविद्यालय के नीचे अगले क्रमांक पर रखे जायेंगे।

(4) इस अधिनियम के अधीन स्थापित या निगमित प्रत्येक विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

विद्यमान विश्वविद्यालयों का निगमन

8–अनुसूची 1 में संख्यांकित विद्यमान विश्वविद्यालय, इस अधिनियम के अधीन निगमित हुए माने जायेंगे।

सम्बद्धता के लिये प्रतिषेध

9–विश्वविद्यालय, किसी महाविद्यालय अथवा संस्था को सम्बद्धता के विशेषाधिकार के निमित्त ग्रहण नहीं करेगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

10–विश्वविद्यालय के उद्देश्य, विद्या की ऐसी शाखाओं, जिन्हें वह उचित समझे, में अनुदेश, शोध और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करके, ज्ञान एवं कौशल का प्रसार और अभिवृद्धि करना होंगे और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित के संवर्द्धन के लिए आवश्यक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगा:–

(क) शिक्षा में अभिनवीकरण जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन, जिसमें ऑनलाइन ज्ञानार्जन, मिश्रित ज्ञानार्जन, निरन्तर शिक्षा और ऐसे अन्य ढंग भी सम्मिलित हैं, की नवीन पद्धतियों और व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके;

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन;

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन ;

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, देशभक्ति, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता समेकन।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

11–विनियामक निकायों और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविहित किये जाने वाले दिशा–निर्देशों तथा प्रतिमानों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:–

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं, जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करे, में शिक्षण का उपबन्ध करना और शोध के लिये तथा ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त उपबन्ध करना;

(ख) विद्या की ऐसी शाखाओं, जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे, में शिक्षण का उपबन्ध करना और शोध तथा ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त उपबन्ध करना;

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर ऐमिरिट्स के अलंकरण से सम्मानित करना;

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों की परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र एवम् उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण–पत्रों उपाधियों और शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(ङ) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से मानद उपाधियाँ या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(च) विनियामक प्राधिकरणों और राज्य सरकार के प्रतिमानों के अनुसार निदेशक पदों, आचार्य पदों, सह आचार्य पदों, सहायक आचार्य पदों और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अन्य अध्यापन तथा शैक्षणिक पदों को संस्थित करना और तद्निमित्त नियुक्तियां करना ;

(छ) प्रशासकीय, लिपिकवर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना;

(ज) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्त करना या काम पर लगाना;

(झ) देश और विदेश के किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार्य करना, सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(ञ) शोध और शिक्षा के लिए स्कूलों, केन्द्रों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना और अनुरक्षण करना, जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो;

(ट) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ठ) आवासों, छात्रावासों की स्थापना, अनुरक्षण तथा उनका पर्यवेक्षण करना तथा छात्रों एवं कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और सामान्य कल्याणकारी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना;

(ड) शोध और परामर्शी सेवाओं के लिए उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या इकाइयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(ढ) अधिनियम तथा परिनियमों के अनुसार यथा स्थिति संकाय, विभाग, केन्द्र या स्कूल स्थापित करना;

(ण) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए राज्य सरकार और अन्य विनियामक निकायों के अनुसार मानक अवधारित करना जिनके अर्न्तगत परीक्षा, मूल्यांकन या गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु परीक्षण की कोई अन्य पद्धति सम्मिलित हो सकती है;

(त) फीस और अन्य प्रभारों की मॉग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;

(थ) महिलाओं एवं अन्य वंचित छात्रों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करना जैसा कि विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(द) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों के मध्य अनुशासन विनियमित करना और प्रवर्तित कराना और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय ;

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के सम्बर्द्धन के लिए व्यवस्था करना;

(न) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन, धारण और प्रबन्ध करना;

(प) यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किसी अचल सम्पत्ति का निस्तारण या उसमें उसका कोई अधिकार या हक होने या उस पर सृजित किसी देनदारी से उसे पृथक नहीं किया जायेगा;

(फ) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसे अभ्यागत आचार्यो, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम निदेशकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकें;

(ब) वाह्य अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोजन करना और दायित्व ग्रहण करना; और

(भ) ऐसे अन्य समस्त कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

प्रवेश और शैक्षणिक मानक

12–(1) विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश, अधिनियम, तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार प्रवेश समिति द्वारा अवधारित किये जाने वाले प्रतिमानों के अनुसार किया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षणिक मानक, विनियामक निकायों के दिशा–निर्देशों के अनुसार हों।

(3) अध्यापक–छात्र अनुपात विनियामक निकायों के दिशा–निर्देशों के अनुसार होगा।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा

13–विश्वविद्यालय सभी लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारिवृन्द सदस्य, छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिए या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या वहॉ से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करे:

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों तथा सामान्य श्रेणी के नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती और किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश में आरक्षण, समय–समय पर राज्य सरकार के आदेशों तथा दिशा–निर्देशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

14–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:–

(1) कुलाधिपति या अध्यक्ष;

(2) प्रति कुलाधिपति या उपाध्यक्ष;

(3) कुलपति;

(4) प्रतिकुलपति;

(5) कुल सचिव;

(6) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(7) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(8) निदेशक;

(9) परीक्षा नियंत्रक;

(10) मुख्य कुलानुशासक;

(11) वित्त अधिकारी; और

(12) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा घोषित किये जायें, विश्वविद्यालय के अधिकारी, होंगे।

कुलाधिपति/अध्यक्ष

15–(1) कुलाधिपति/अध्यक्ष की नियुक्ति यथा विहित प्रक्रिया तथा निबन्धन एवं शर्तों का अनुसरण करते हुये पाँच वर्ष की अवधि के लिये शासी निकाय द्वारा की जायेगी।

(2) कुलाधिपति/अध्यक्ष विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा।

(3) कुलाधिपति/अध्यक्ष शासी निकाय की बैठकों तथा विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(4) यदि किसी समय, प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने या अन्यथा, और ऐसी जाँच, जो आवश्यक समझी जाय, करने के पश्चात ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि कुलाधिपति/अध्यक्ष का बना रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो शासी निकाय बहुमत के विनिश्चय से तद्निमित्त कारणों को अभिलिखित करते हुए लिखित आदेश द्वारा कुलाधिपति/अध्यक्ष से आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक से कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ने के लिये कह सकता है, ऐसे मामलों में शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष करेगा :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कार्यवाही करने के पूर्व कुलाधिपति/अध्यक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(5) कुलाधिपति/अध्यक्ष के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय की कोई सूचना या अभिलेख की मांग करना ;

(ख) इस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन कुलपति की नियुक्ति करना ;

(ग) इस अधिनियम एवं तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार कुलपति को हटाना;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियां, जैसा कि परिनियमावली द्वारा विहित किया जाय।

(6) कुलाधिपति/अध्यक्ष विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति/उपाध्यक्ष के वेतन की धनराशि से अनधिक दोगुनी धनराशि आहरित करेंगे।

प्रति–कुलपति या उपाध्यक्ष

16–(1) प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष की नियुक्ति, शासी निकाय के अनुमोदन से कुलाधिपति/अध्यक्ष द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिये की जायेगी।

(2) कर्तव्यों के निर्वहन में प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष, क्रमशः कुलाधिपति/अध्यक्ष का सहयोग करेगा तथा उनकी अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(3) कुलाधिपति/अध्यक्ष को सम्बोधित लिखित रूप में हस्ताक्षर द्वारा प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष अपने पद से त्याग–पत्र दे सकता है।

(4) यदि किसी समय, प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने या अन्यथा रूप में और ऐसी जाँच, जो आवश्यक समझी जाय, करने के पश्चात ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, कि प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष का बना रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो कुलाधिपति/अध्यक्ष शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से तद्निमित्त कारणों को उल्लिखित करते हुए, लिखित आदेश द्वारा प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष से आदेश में यथाविनिर्दिष्ट दिनांक से अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ने के लिये कह सकता है:

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कार्यवाही करने के पूर्व प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(5) प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष ऐसा वेतन आहरित करेगा जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति/अध्यक्ष से कम होगा।

कुलपति

17–(1) कुलपति की नियुक्ति शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से कुलाधिपति/अध्यक्ष द्वारा की जायेगी:

परन्तु यह कि कुलपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगा।

(2) कुलपति पांच वर्ष की अवधि के लिये या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

(3) यदि किसी समय, प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने या अन्यथा रूप में और ऐसी जॉच, जैसा आवश्यक समझी जाय, करने के पश्चात ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, कि उसका कुलपति बना रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो शासी निकाय, तद्निमित्त कारणों को उल्लिखित करते हुये कुलपति से आदेश में यथाविनिर्दिष्ट दिनांक से लिखित आदेश द्वारा अपना पद छोड़ने के लिये कह सकता है :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व कुलपति को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और वह विश्वविद्यालय के क्रिया कलापों का सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण करेगा और वह कार्यपरिषद् का अध्यक्ष होगा तथा अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के उपबन्धों के अधीन किये गये कार्यपरिषद् तथा अन्य सक्षम निकायों तथा राज्य सरकार के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(5) कुलाधिपति/अध्यक्ष और प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कुलपति विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(6) यदि कुलपति की राय में किसी ऐसे मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो जिसके लिये इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किसी अन्य प्राधिकारी को शक्तियां प्रदत्त हों तो वह ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जिसे वह आवश्यक समझे तथा तत्पश्चात अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को शीघ्रातिशीघ्र देगा, जो साधारण प्रक्रम में तीस दिनों की अवधि के भीतर मामलों का निस्तारण करेगा:

परन्तु यह कि यदि सम्बन्धित अधिकारी या प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्यवाही कुलपति द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी तो ऐसा मामला अध्यक्ष को विनिर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

(7) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का संपादन करेगा जैसा कि अधिनियम और तद्धीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा उपबंधित किया जाय।

प्रति कुलपति

18–(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाय और अध्यादेशों और विनियमों में उपबंधित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन–प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन करने में कुलपति की सहायता करेगा।

(4) प्रतिकुलपति उतनी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जैसा कि प्रायोजक निकाय द्वारा अवधारित किया जाय।

कुलसचिव

19–(1) कुलसचिव की अर्हताएं, पदावधि, सेवा शर्तें और नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसे होंगे जैसा कि विहित किया जाय।

(2) कुलसचिव के पास विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(3) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मोहर की समुचित अभिरक्षा हेतु उत्तरदायी होगा। वह शासी निकाय, कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् और प्रवेश समिति तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा और वह समस्त ऐसी सूचना इन अधिकारियों के समक्ष रखने के लिये बाध्य होगा जो उनके संव्यवहार के लिये आवश्यक हो। वह परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा यथा विहित कार्यपरिषद या कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित अन्य कर्तव्यों का भी निष्पादन करेगा किन्तु उसे इस उपधारा के आधार पर मत देने का हक नहीं होगा।

संकायाध्यक्ष

20–प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा कि विहित किया जाय।

वित्त अधिकारी

21–(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति, ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा कि विहित किया जाय।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

अन्य अधिकारी

22–छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा कि विहित किये जाएं।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

23–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे:–

(1) शासी निकाय;
(2) कार्यपरिषद्;
(3) विद्या परिषद्;
(4) वित्त समिति;
(5) नियोजन बोर्ड;
(6) संकाय बोर्ड,
(7) अध्ययन बोर्ड,
(8) प्रवेश समिति
(9) परीक्षा समिति; और
(10) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किये जायं।

शासी निकाय

24–(1) शासी निकाय के गठन और सदस्यों का कार्यकाल ऐसा होगा, जैसा विहित किया जाय।

(2) कुलाधिपति/अध्यक्ष द्वारा नियत दिनांक को शासी निकाय वर्ष में एक बार बैठक करेगा और ऐसी बैठक शासी निकाय की वार्षिक बैठक कही जायेगी :

परन्तु यह कि कुलाधिपति/अध्यक्ष, जैसा उचित समझे, शासी निकाय के कुल सदस्यों के अन्यून एक चौथाई सदस्यों द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षरित अध्यपेक्षा पर शासी निकाय की विशेष बैठक आयोजित कर सकता है।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, शासी निकाय विश्वविद्यालय की परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करेगी तथा उसके पास निम्नांकित शक्तियां और कृत्य होगें, अर्थात :–

(क) विश्वविद्यालय की वृहद नीतियों और कार्यक्रमों की समय–समय पर समीक्षा करना और विश्वविद्यालय की कार्यपद्धति, सुधार और विकास हेतु उपाय सुझाना,

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं और ऐसे लेखाओं की लेखा परीक्षा पर विचार करना और संकल्प पारित करना तथा अपना मत कार्यपरिषद् को उपलब्ध कराना ;

(ग) परामर्श हेतु सौंपे गये किसी मामले में अध्यक्ष को परामर्श देना;

(घ) अन्य कार्यों, जो विहित किये जायें, का निष्पादन करना।

कार्य परिषद

25–(1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगी।

(2) कार्यपरिषद् की बैठक उस प्रकार आयोजित की जायेगी जैसा कि विहित किया जाय।

(3) विश्वविद्यालय के प्रशासन, प्रबंध और नियंत्रण तथा उसकी आय, कार्यपरिषद में निहित होंगे, जो विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों और निधियों को नियंत्रित और शासित करेगी।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन कार्यपरिषद के पास निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे :–

(एक) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारित और नियंत्रित करना;

(दो) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम अथवा स्थावर सम्पत्ति को अर्जित करना ;

(तीन) परिनियमों एवं अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना अथवा उन्हें निरसित करना;

(चार) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के निस्तारण पर रखी गयी किन्हीं निधियों को प्रशासित करना;

(पांच) विश्वविद्यालय के बजट को अनुमोदित करना;

(छः) परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियां, अधिछात्रवृत्तियां, निर्धन छात्रवृत्तियां, पदक और अन्य पारितोषिक संस्थित करना ;

(सात) विश्वविद्यालय के कुलसचिव, अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों को नियुक्त करना तथा उनकी सेवा के कर्तव्यों एवं शर्तों को परिभाषित करना ;

(आठ) परीक्षकों के मानदेय, परिलब्धियां और यात्रा तथा अन्य भत्ते नियत करना ;

(नौ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर के निर्माण एवं प्रयोग का निदेश करना;

(दस) विश्वविद्यालय के अध्यापन, प्रशासनिक एवं अन्य कर्मचारिवृन्द के मध्य परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार अनुशासन विनियमित तथा प्रवर्तित करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था, लेखाओं, विनिधानों, सम्पत्ति तथा अन्य समस्त प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध करना तथा उन्हें विनियमित करना;

(बारह) विश्वविद्यालय के किसी धन, जिसमें विन्यासित सम्पत्ति सम्मिलित है, का विनिधान करना;

(तेरह) विश्वविद्यालय के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर, उपस्कर, उपकरण और अन्य वांछित साधित्र प्रदान करना;

(चौदह) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उसमें फेरबदल करना, उसे कार्यान्वित करना और रद्द करना;

(पन्द्रह) इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अन्य समस्त मामलों को विनियमित तथा अवधारित करना;

(5) कार्यपरिषद् का प्रत्येक विनिश्चय उसके कारणों सहित सूचित किया जायेगा।

(6) कुलपति कार्यपरिषद् का अध्यक्ष होगा, जो निम्नलिखित अन्य सदस्यों से गठित होगी अर्थात् :–

(एक) शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन सदस्य;

(दो) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट दो प्रख्यात शिक्षा शास्त्री;

(तीन) राज्य सरकार का एक अधिकारी, जो संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की श्रेणी से नीचे का न हो;

(चार) एक वर्ष की अवधि के लिये ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में विश्वविद्यालय का एक आचार्य और एक सह आचार्य;

(पांच) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले तीन नामों के पैनल से सह आचार्य की श्रेणी से अनिम्न एक शिक्षा शास्त्री, जिसके लिये विश्वविद्यालय प्रख्यात शिक्षा शास्त्रीयों के तीन नामों की सूची प्रस्तुत करेगा;

(छः) कुलसचिव पदेन सदस्य सचिव होगा;

(सात) वित्त अधिकारी को कार्यपरिषद् की कार्यवाहियों में भाग लेने हेतु पक्ष में तथा अन्यथा रूप में बोलने का अधिकार होगा किन्तु उसे मत देने का हक नहीं होगा;

(7) कार्यपरिषद् की बैठक की गणपूर्ति छः सदस्यों से कम नहीं होगी।

(8) कार्यपरिषद् की किसी बैठक में विनिश्चय, उस बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किये जाएंगे :

परन्तु यह कि किसी प्रस्ताव के बराबर होने की स्थिति में कुलपति के समर्थन वाला प्रस्ताव अभिभावी होगा;

विद्या परिषद्

26–(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगी और उसका प्रयोग करेगी।

(2) विद्या परिषद् का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

वित्त समिति

27–(1) वित्त समिति, वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिए विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी।

(2) वित्त समिति का गठन, उसकी शक्तियॉ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि विहित किया जाय।

नियोजन बोर्ड

28–(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवसंरचना और शैक्षणिक सहायता प्रणाली, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य विनियामक निकायों के प्रतिमानों को पूरा करे।

(2) नियोजन बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि विहित किया जाय।

संकाय बोर्ड, अध्ययन बोर्ड, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण

29–संकाय परिषद, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किये जाये, का गठन शक्तियॉ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायं।

किसी निकाय की सदस्यता के लिए अनर्हता

30–कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न होने से अनर्ह हो जायेगा, यदि वह :–

(1) मानसिक रूप से अस्वस्थ हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो/की गयी हो।

(2) अनन्मुक्त दिवालिया हो।

(3) नैतिक अद्यमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिये सिद्ध दोष ठहराया गया हो/गयी हो।

(4) किसी परीक्षा के संचालन में किसी रूप में कहीं भी अनुचित आचरण का बढ़ावा देने में अथवा उसमें लिप्त होने, उसका संवर्द्धन करने के लिए दण्डित किया गया हो/की गयी हो।

(5) वेतन या किन्हीं अन्य प्राधिकृत परिलब्धियों के सिवाय विश्वविद्यालय से किसी लाभ का हेतुक हो।

(6) विश्वविद्यालय की निधि, अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयोजित करता/करती हो।

रिक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

31–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का कोई विनिश्चय, कार्य या कार्यवाही उसमें कोई रिक्ति होने या उसके गठन में कोई त्रुटि होने के कारण ही अविधिमान्य नहीं होगी।

आपात रिक्तियों का भरा जाना

32–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण अथवा निकाय के किसी सदस्य की मृत्यु, त्याग–पत्र या उसे हटाये जाने के कारण अथवा हैसियत, जिसमें वह नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया था, में परिवर्तन किये जाने के कारण हुई किसी रिक्ति को यथाशीघ्र उस व्यक्ति अथवा निकाय द्वारा जो ऐसे सदस्य को नियुक्ति या नामनिर्दिष्ट किया हो :

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा निकाय के सदस्य के रूप में कोई आपात रिक्ति होने पर नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, ऐसे प्राधिकरण अथवा निकाय का सदस्य केवल अवशेष अवधि तक के लिये बना रहेगा जिसके स्थान पर वह नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया हो।

समितियाँ

33–विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के अनुरूप ऐसी समितियों या उप समिति का गठन, ऐसे निर्देश–निबन्धों के साथ, जैसा कि ऐसी समितियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों हेतु आवश्यक हो, कर सकते हैं। ऐसी समिति या उप समिति का गठन तथा उनके कर्तव्य वही होंगे जैसा कि समिति या उप समिति का गठन करने वाले प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा विनिश्चय किया जाय।

परिनियमावली बनाने की शक्ति

34–(1)इस अधिनियम के अधीन स्थापित अथवा निगमित विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावलियां कार्यपरिषद् द्वारा बनायी जायेंगी और राज्य सरकार को उनका अनुमोदन किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) सरकार विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रथम परिनियमावली पर विचार करेगी और इसकी प्राप्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर अनुमोदित करेगी। यदि राज्य सरकार उपरोक्त उल्लिखित समय के भीतर तत्सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों को अनुमोदित नहीं करती है अथवा उन्हें विश्वविद्यालय को संसूचित नहीं करती है, तो इस प्रकार प्रस्तुत की गयी परिनियमावली अनुमोदित समझी जायेगी।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियमावली में निम्नलिखित सभी या कोई विषय उपबन्धित किये जा सकते हैं/किया जा सकता है, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों, जैसा कि समय–समय पर गठित किया जाय, का गठन उनकी शक्तियाँ और कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति और उनका पद पर निरन्तर बना रहना उक्त प्राधिकरणों के सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकरणों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामलें, जिनके लिए उपबन्ध किया जाना आवश्यक हो ;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कृत्य उनकी परिलब्धियाँ ;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक तथा प्रशासनिक कर्मचारिवृंद की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियाँ;

(ङ) विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारिवृंद की, एक संयुक्त परियोजना का दायित्व ग्रहण करने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें, जिनमें सेवानैवृत्तिक प्रसुविधाएं, बीमा और भविष्य निधि, उनकी सेवा समाप्ति की रीति और अनुशासनात्मक मामलें सम्मिलित हैं;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;

(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों या छात्रों के मध्य विवादों के निस्तारण की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य प्राधिकारी के किसी कार्यवाही के विरूद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लेना;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावत्तियों. पदकों और परस्कारों को संस्थित करना;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखना;

(ढ) विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर विभागों, केन्द्रों और अन्य संस्थाओं आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करना;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(त) अन्य सभी विषय, जो इस अधिनियम के अनुसार हों या विहित किये जायं।

(4) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की शक्तियों या उसके गठन को प्रभावित करने वाला कोई परिनियम न तो बनायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में राय व्यक्त करने का अवसर न दिया जाय और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

35–इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेश, कार्य परिषद द्वारा बनाये जायेंगे, जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण–पत्रों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधियाँ, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र तथा शैक्षणिक विशिष्टियाँ प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों हेतु तथा परीक्षाओं में प्रवेश, उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण–पत्रों हेतु प्रभार्य शुल्क का निर्धारण;

(च) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हों, और उनके लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियमों में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियॉं;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों, जिसके अर्न्तगत व्यावसायिक निकाय या संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति;

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक महत्ता में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाय, का सृजन, उसकी संरचना और उसके कृत्य;

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक;

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित न हों।

वार्षिक रिपोर्ट

36–(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनॉक को जैसा विहित किया जाय, शासी निकाय को प्रस्तुत किया जायेगा और शासी निकाय अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगा ;

(2) शासी निकाय वार्षिक रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियॉं कार्य परिषद को उसके विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

वार्षिक लेखा

37–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन–पत्र, कार्य परिषद के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी लेखा–परीक्षा, प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेंट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार, अनधिक पन्द्रह माह के अन्तराल पर करायी जायेगी।

(2) लेखा–परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक/लेखाओं की प्रति, कार्य परिषद के प्रेक्षणों के साथ शासी निकाय और कुलाधिपति/अध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) कुलाधिपति/अध्यक्ष द्वारा वार्षिक लेखाओं पर किये गये कोई प्रेक्षण, शासी निकाय और कार्य परिषद के संज्ञान में लाये जायेंगे और ऐसे प्रेक्षणों, यदि कोई हों, पर कार्य परिषद द्वारा पुनरीक्षण किये जाने के पश्चात उन्हें कुलाधिपति/अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा तथा उन्हें सार्वजनिक कर दिया जायेगा।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

38–(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा/काम पर लगाया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय और किसी नियमित कर्मचारी के मध्य उठने वाला कोई विवाद कुलपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जो इसके निर्देश की प्राप्ति के दिनॉक से तीन माह के भीतर कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात् विवाद पर विनिश्चय करेगा।

(3) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उस पर उसका विनिश्चय, कुलपति द्वारा किया जायेगा।

अपील करने का अधिकार

39–(1)कोई व्यथित व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी विनिश्चय के विरूद्ध अपील ऐसे विनिश्चय की प्राप्ति के दिनांक से तीन माह की अवधि के भीतर, कुलाधिपति/अध्यक्ष को कर सकता है :

परन्तु यह कि कुलाधिपति/अध्यक्ष के पास विलम्ब के लिये माफी देने की शक्ति होगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पर्याप्त कारणों से अपीलार्थी नियत समय के भीतर अपनी अपील नही कर सका था।

(2) ऐसी किसी अपील में कुलाधिपति/अध्यक्ष द्वारा किया गया कोई विनिश्चय अंतिम होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन

40–विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसा कि कार्य परिषद द्वारा विनिश्चत किया जाये, ऐसी पेंशन या कल्याणकारी योजनायें या भविष्य निधि का गठन करेगा या ऐसी बीमा योजनाओं का उपबन्ध करेगा, जैसा वह उचित समझे।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की रीति

41–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज, जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हों, को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के रुप में ग्रहण किया जायेगा और उसमे अभिलिखित विषय और संव्यहरण उसी रूप में साक्ष्य के रुप में ग्रहण किये जायेंगे जहां वे यदि मूल रूप में प्रस्तुत किये जाते तो साक्ष्य के रूप में ग्रहण होते।

परिनियमों, अध्यादेशो और विनियमों का प्रकाशन

42–इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किये जायेंगे।

स्थायी विन्यास निधि

43–(1) प्रायोजक निकाय कम से कम 5 (पांच) करोड़ रूपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगी।

(2) स्थायी विन्यास निधि का उपयोग, प्रतिभूति धनराशि के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिये किया जायेगा कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन कर रहा है तथा इस अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय अथवा प्रायोजक निकाय द्वारा इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या तद्धीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करने की दशा में राज्य सरकार के पास विन्यास निधि के किसी भाग अथवा सम्पूर्ण भाग को समपहृत करने की शक्ति निहित होगी।

(3) विश्वविद्यालय विन्यास निधि से होने वाली आय का उपयोग विश्वविद्यालय के अवसंरचनाओं के विकास हेतु अथवा विश्वविद्यालय के आवर्तक व्यय की पूर्ति हेतु कर सकता है।

(4) विन्यास निधि की धनराशि को ऐसी लिखतों जैसा कि राज्य सरकार नियमावली द्वारा विहित करे, में विनिधानित की जायेगी और विश्वविद्यालय के विघटन तक विनिधानित रखी जायेगी।

(5) दीर्घ अवधि की प्रतिभूति में विनिधान किये जाने के मामले में और राजकीय कोषागार के वैयक्तिक जमा लेखों में ब्याज जमा किये जाने के मामले में जमा इस शर्त के साथ किया जायेगा कि राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना उक्त धनराशि का आहरण या उपयोग नहीं किया जायेगा।

सामान्य निधि

44–(1) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी अर्थात :–

(क) समस्त शुल्क जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किये जा सकते हैं ;

(ख) किन्हीं अन्य स्रोतों से प्राप्त समस्त धनराशियां;

(ग) सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकायों जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रतिषिद्ध न हों, द्वारा इस निमित्त किये गये सभी अंशदान ;

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग, विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों की पूर्ति के लिये किया जायेगा।

विकास निधि

45–(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :–

(क) विकास शुल्क, जो छात्रों से प्रभारित किये जा सकते हैं ;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए अन्य स्रोतों से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकायों, जो तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा प्रतिषिद्ध न हों, द्वारा इस निमित्त किये गये सभी अंशदान; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय–समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

निधियों का अनुरक्षण

46–इस अधिनियम के अधीन स्थापित सभी निधियॉ कार्य परिषद के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन यथा विहित रीति से विनियमित और अनुरक्षित की जायेंगी।

विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित होगा

47–विश्वविद्यालय, राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिये पात्र नहीं होगा।

शुल्क

48–समस्त प्रयोजनों के लिये शुल्क संरचना का विनिश्चय कार्य परिषद द्वारा किया जायेगा परन्तु यह कि विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के किसी विद्यमान विधि के अधीन अपेक्षित अथवा विनियामक निकायों द्वारा यथा नियत शुल्क से अधिक शुल्क अपने छात्रों से प्रभारित नहीं करेगा और शुल्क संरचना सार्वजनिक रूप में रखी जायेगी।

विश्वविद्यालय का प्रत्यायन

49–प्रोग्रामों के प्रारंभ होने के पाँच वर्षों की अवधि के भीतर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद का प्रत्यायन तथा ऐसे अन्य प्रत्यायन, जो सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किये जायें, प्राप्त करेगा। वह ऐसे अन्य विनियामक निकायों जो विश्वविद्यालय द्वारा ग्रहण किये गये पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित हो, से भी प्रमाणन/प्रत्यायन प्राप्त करेगा। वह विश्वविद्यालयों को प्रदान किये गये ग्रेड के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सूचित करेगा। विश्वविद्यालय समय–समय पर ऐसे प्रत्यायन का नवीकरण सुनिश्चित करेगा।

दीक्षान्त समारोह

50–उपाधियां, डिप्लोमा प्रदत्त करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिये विनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों द्वारा यथा विहित रीति से प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह का आयोजन किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, निजी विश्वविद्यालयों के लिये नोडल अभिकरण होगी

51–(1) इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये परिनियमों तथा विनियमों के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, नोडल अभिकरण होगी।

(2) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट छात्रों के अभिलेख, उनके परिणाम और परीक्षा में सम्मिलित न होने वाले छात्रो के अभिलेख, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद् को उपलब्ध कराये जायेंगे। छात्रों को अंतिम उपाधि उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद् के अनुमोदन से प्रदत्त की जायेगी। उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम दीक्षान्त समारोह के दिनांक से 30 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद को प्रस्तुत किये जायेंगे और परिषद उक्त सूची को अनुमोदित करेगी। यदि 20 दिन के भीतर परिषद के अनुमोदन की संसूचना, विश्वविद्यालय को नहीं दी जाती है तो सूची अनुमोदित की गयी समझी जायेगी।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारी से विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी सूचना या अभिलेखों को विनिर्दिष्ट दिनांक एवं समय के भीतर उपलब्ध कराने के लिये कह सकता है, जिससे विफल होने पर उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, समुचित कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रेषित कर सकती है।

(4) उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालयों का कम से कम एक वार्षिक निरीक्षण करेगी और विनिर्दिष्ट रूप से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन दी गयी वचनबद्धता के अनुपालन के सम्बन्ध में अपनी वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

सूचना और अभिलेखों की माँग करने के लिए राज्य सरकार की शक्तियाँ

52–(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्त व्यवस्था और अन्य मामलों या क्रियाकलापों आदि से सम्बन्धित सूचना या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा मांग की जाय।

(2) यदि राज्य सरकार का यह विचार हो कि अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या तद्धीन बनाये गये परिनियमों का उल्लंघन हुआ है तो वह इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश जारी कर सकती है जैसा कि वह आवश्यक समझे और विश्वविद्यालय निर्धारित समय के भीतर ऐसे निदेशों का अनपालन करेगा।

विश्वविद्यालय का विघटन

53–(1) यदि विश्वविद्यालय अपने गठन या निगमन को शासित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम एक वर्ष की लिखित नोटिस देगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस की प्राप्ति पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित पाठयक्रमों में छात्रों के अन्तिम बैच द्वारा अपने पाठयक्रमों को पूरा करने तक विश्वविद्यालय ऐसी प्रशासनिक व्यवस्थाएं करेगा जैसा कि विहित किया जाय।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

54–(1) अधिनियम की धारा 53 के अधीन विश्वविद्यालय के देनदारियों को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये व्यय की पूर्ति स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि से की जायेगी।

(2) यदि इस प्रक्रिया के दौरान उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियाँ, विश्वविद्यालय के व्यय और देनदारियों को पूरा करने के लिये पर्याप्त न हो तो राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों तथा आस्तियों का निस्तारण करके की जा सकती है।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय का परिसमापन

55–(1) यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या तद्धीन बनाये गये विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किसी निदेश का उल्लंघन किया है या धारा 3 के अधीन प्रदत्त किसी वचनबद्धता को क्रियान्वित करने से प्रविरत हो गया है या निधियों का कपट या दुर्विनियोग या गंभीर दुरूपयोग किया गया हो तो वह उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् को प्रारंभिक जाँच संचालित करने के लिये निर्देश जारी कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन निर्गत निदेश पर विश्वविद्यालय की जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि प्रथम दृष्टया इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों या विनियमों के समस्त या किसी उपबन्ध का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी निदेशों का अतिक्रमण हुआ है या धारा 3 के अधीन प्रदत्त वचनबद्धता क्रियान्वित नहीं की जा रही है या निधियों का कपट या दुर्विनियोग या गंभीर दुरूपयोग किया गया हो तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिये, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की सिफारिश पर जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या समिति को, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के अभिकथनों की जांच करने के लिये, नियुक्त करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जांच प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का, विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों में, विचारण के दौरान सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां होगी, अर्थात् :–

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(घ) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना; और

(ङ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाय।

(5) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है तथा तद्निमित्त सुधारात्मक कार्यवाही की आवश्यकता है, तो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट समय के भीतर, इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने के लिये, आवश्यक सुधार करने के निदेश विश्वविद्यालय को देगी। यदि विश्वविद्यालय विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे निदेशों का अनुपालन करने में विफल रहता है तो राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के ऐसे निदेश जारी करने के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर आवश्यक सुधार या उपान्तरण करने हेतु पुनः निदेश दे सकती है;

(6) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त जाँच अधिकारी अथवा जाँच समिति से जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों या विनियमों के सभी अथवा किसी उपबंध का अतिक्रमण किया है अथवा उपर्युक्त उपधारा (5) के अधीन जारी निदेशों सहित इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किये गये किसी निदेश का उल्लंघन किया है अथवा धारा 3 के अधीन उसके द्वारा दी गयी वचनबद्धताओं का पालन करने से प्रविरत हो गया है या विश्वविद्यालय में निधियों का कपट या दुर्विनियोग या गंभीर दुरूपयोग किया गया हो, जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मानक पर संकट उत्पन्न हो गया हो तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय के परिसमापन हेतु उक्त अवधि में विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों को संचालित करने हेतु त्रिसदस्यीय अन्तरिम समिति नियुक्त करेगी।

(7) (एक) उपधारा (6) के अधीन नियुक्त अन्तरिम समिति को विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों को तब तक प्रशासित करने की समस्त शक्तियां होंगी जब तक कि नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों का अंतिम बैच अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता है और उस बैच के छात्रों को यथा स्थिति डिग्रियां, डिप्लोमा या पुरस्कार नहीं प्रदान कर दिये जाते हैं ;

(दो) नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों के अंतिम बैच को यथा स्थिति उपाधि, डिप्लोमा एवं पुरस्कार, प्रदान कर दिये जाने के पश्चात अन्तरिम समिति राज्य सरकार को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी;

(तीन) उपधारा (7) (दो) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, शासकीय गजट में, अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय के विघटन का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से विश्वविद्यालय विघटित हुआ माना जायेगा और विश्वविद्यालय की समस्त शेष आस्तियां एवं देनदारियां उक्त दिनांक से प्रायोजक निकाय में निहित हो जायेंगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निर्देश देने की शक्ति

56–राज्य सरकार समय–समय पर विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक मामलों में निदेश जारी कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबंधो से असंगत न हों, जैसा वह आवश्यक समझे। ऐसे निदेश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा, जिसमें विफल होने पर राज्य सरकार इस अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय के विरुद्ध युक्तियुक्त कार्यवाही कर सकती है।

विघटन / मान्यता रद्द होने पर परिसम्पत्तियाँ/ देनदारियों की प्रास्थिति

57–अधिनियम में ऊपर उल्लिखित किसी उपबन्ध के अधीन विश्वविद्यालय के विघटन की स्थिति में विश्वविद्यालय की समस्त अवशिष्ट आस्तियाँ और सम्पत्तियाँ, जिनमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि तथा देनदारियां सम्मिलित हैं, प्रायोजक निकाय से संबंधित हो जायेंगे।

नियमावली बनाने की शक्ति

58–(1) इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकती है।

(2) पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली में निम्नलिखित समस्त या कोई उपबन्ध हो सकता है/हो सकते हैं :–

(क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना करने और संदेय आवेदन शुल्क का प्रस्ताव बनाने की रीति ;

(ख) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन परियोजना रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट किये जाने वाले अन्य विवरण;

(ग) अन्य मामले, जो इस अधिनियम के अधीन नियमावली द्वारा विहित किये जायं या हो सकते हैं।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

59–(1) राज्य सरकार ऐसी किसी कठिनाई को, विशिष्टतः वैक्तिक निजी विश्वविद्यालय अधिनियमों के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रति संक्रमण के संबंध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध आदेश में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रुप मे हो जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के आरम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, उसके दिये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

विवादों का निपटारा उत्तर प्रदेश के किसी न्यायालय में किया जायेगा

60–अधिनियम में किये गये उपबन्धों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले समस्त विवादों का निपटारा उत्तर प्रदेश राज्य के किसी न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा

61–इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबन्ध विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त राज्य विधान मण्डल द्वारा बनायी गयी किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल बात होते हुये भी प्रभावी होंगे।

निरसन और व्यावृत्तियां

62–(1) इस अधिनियम की अनुसूची 1 में पुनर्संख्यांकित समस्त अधिनियम इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर निरसित समझे जायेंगे।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित अनुसूची 1 में पुनर्संख्यांकित अधिनियमों के निरसित होते हुये भी निरसित अधिनियमों के अधीन स्थापित विश्वविद्यालयों द्वारा किये गये समस्त विनिश्चय निष्पादित अधिनियम, सृजित तथा समाप्तकृत अधिकार तथा दायित्व इस अधिनियम के अधीन विधिमान समझे जायेंगे।

(3) इस अधिनियम में निगमित किये गये विश्वविद्यालय अपने सम्बन्धित निरसित अधिनियमों के अधीन अपने परिनियमों, अध्यादेशों और तद्निमित्त प्रयोज्य विनियमों में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप उन्हें संगत बनाये जाने हेतु इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर उपान्तर करेंगे।

अल्पसंख्यक निजी विश्वविद्यालय

63–इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी उत्तर प्रदेश राज्य के धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 द्वारा यथा प्रत्याभूत विशेषाधिकार प्राप्त करते रहेंगे।

## अनुसूची–1

(धारा 8 देखें)

| क्र0 | अधिनियम का विवरण | विश्वविद्यालय का नाम |
|---|---|---|
| 1– | इंटीग्रल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2004), अधिसूचना दिनांक 27.02.2004 | इन्टीग्रल विश्वविद्यालय, लखनऊ। |
| 2– | द एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2005), अधिसूचना दिनांक 24.3.2005 | एमिटी विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश। |
| 3– | मंगलायतन विश्वविद्यालय , उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2006, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2006) अधिसूचना दिनांक 30.10.2006 | मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। |
| 4– | स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय , उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2008), अधिसूचना दिनांक 05.9.2008 | स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश। |
| 5– | तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय , उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2008), अधिसूचना दिनांक 05.9.2008 | तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। |
| 6– | शारदा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2009), अधिसूचना दिनांक 24.3.2009 | शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। |
| 7– | जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 01.9.2010 | जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश। |
| 8– | इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 01.9.2010 | इन्वर्टिस विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश। |
| 9– | मोनाड़ विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010 | मोनाड़ विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। |
| 10– | नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010 | नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश। |
| 11– | आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010 | आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय, ओंकार धाम लोधीपुर राजपूत, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। |
| 12– | श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010 | श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, गजरौला जे0पी0 नगर। |
| 13– | बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010 | बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, लखनऊ। |
| 14– | गलगोटियाज विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2011), अधिसूचना दिनांक 07.4.2011 | गलगोटियाज विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर। |
| 15– | शिवनाडर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2011) अधिसूचना दिनांक 21.6.2011 | शिवनाडर विश्वविद्यालय, दादरी, गौतमबुद्धनगर। |
| 16– | श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2012), अधिसूचना दिनांक 04.7.2012 | श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, बाराबंकी। |
| 17– | मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2006), अधिसूचना दिनांक 19.6.2006 | मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर। |
| 18– | द ग्लोकल यूनिवर्सिटी , उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2012), अधिसूचना दिनांक 05.7.2012 | द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, अली अकबरपुर, सहारनपुर। |
| 19– | रामा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2014), अधिसूचना दिनांक 10.01.2014 | रामा विश्वविद्यालय, कानपुर। |
| 20– | शोभित विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2012), अधिसूचना दिनांक 05.07.2012 | शोभित विश्वविद्यालय गंगोह, सहारनपुर। |
| 21– | जेपी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2014, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2014), अधिसूचना दिनांक 04.3.2014 | जेपी विश्वविद्यालय, अनूपशहर उत्तर प्रदेश। |
| 22– | जे0एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2015 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2015), अधिसूचना दिनांक 24.6.2015 | जे0एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद। |
| 23– | आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 03.10.2016 | आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश। |
| 24– | बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.9.2016 | बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर |
| 25– | बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2016) अधिसूचना दिनांक 16.9.2016 | बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, बरेली। |
| 26– | संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता, मथुरा उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.9.2016 | संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता, मथुरा। |
| 27– | एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.9.2016 | एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। |

# अनुसूची–2

(धारा 7 देखें)

| क्र0 | अधिनियम का विवरण | विश्वविद्यालय का नाम |
|---|---|---|
| 1– | इंटीग्रल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2004), अधिसूचना दिनांक 27.02.2004 | इन्टीग्रल विश्वविद्यालय, लखनऊ। |
| 2– | द एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2005), अधिसूचना दिनांक 24.3.2005 | एमिटी विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश। |
| 3– | मंगलायतन विश्वविद्यालय , उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2006, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2006) अधिसूचना दिनांक 30.10.2006 | मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ, उत्तर प्रदेश। |
| 4– | स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय , उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2008), अधिसूचना दिनांक 05.9.2008 | स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश। |
| 5– | तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय , उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2008), अधिसूचना दिनांक 05.9.2008 | तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। |
| 6– | शारदा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2009), अधिसूचना दिनांक 24.3.2009 | शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। |
| 7– | जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 01.9.2010 | जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश। |
| 8– | इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 01.9.2010 | इन्वर्टिस विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश। |
| 9– | मोनाड़ विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010 | मोनाड़ विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। |
| 10– | नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010 | नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश। |
| 11– | आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010 | आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय, ओंकार धाम लोधीपुर राजपूत, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। |
| 12– | श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010 | श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, गजरौला जे0पी0 नगर। |
| 13– | बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010 | बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, लखनऊ। |
| 14– | गलगोटियाज विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2011), अधिसूचना दिनांक 07.4.2011 | गलगोटियाज विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर। |
| 15– | शिवनाडर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2011) अधिसूचना दिनांक 21.6.2011 | शिवनाडर विश्वविद्यालय, दादरी, गौतमबुद्धनगर। |
| 16– | श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2012), अधिसूचना दिनांक 04.7.2012 | श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, बाराबंकी। |
| 17– | मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2006), अधिसूचना दिनांक 19.6.2006 | मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर। |
| 18– | द ग्लोकल यूनिवर्सिटी , उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2012), अधिसूचना दिनांक 05.7.2012 | द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, अली अकबरपुर, सहारनपुर। |
| 19– | रामा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2014), अधिसूचना दिनांक 10.01.2014 | रामा विश्वविद्यालय, कानपुर। |
| 20– | शोभित विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2012), अधिसूचना दिनांक 05.07.2012 | शोभित विश्वविद्यालय गंगोह, सहारनपुर। |
| 21– | जेपी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2014, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2014), अधिसूचना दिनांक 04.3.2014 | जेपी विश्वविद्यालय, अनूपशहर उत्तर प्रदेश। |
| 22– | जे0एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2015 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2015), अधिसूचना दिनांक 24.6.2015 | जे0एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद। |
| 23– | आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 03.10.2016 | आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश। |
| 24– | बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.9.2016 | बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर |
| 25– | बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2016) अधिसूचना दिनांक 16.9.2016 | बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, बरेली। |
| 26– | संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता, मथुरा उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.9.2016 | संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता, मथुरा। |
| 27– | एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.9.2016 | एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। |

## उद्देश्य और कारण

शासनादेश, दिनांक 06 फरवरी, 2008 के अधीन मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार विभिन्न राज्य अधिनियमों द्वारा सत्ताइस निजी विश्वविद्यालय स्थापित एवं निगमित किये गये हैं। चूंकि विभिन्न विश्वविद्यालयों के विभिन्न अधिनियमों में विभिन्न उपबंध हैं और ऐसे निजी विश्वविद्यालयों के अनुश्रवण हेतु कोई समान उपबन्ध नहीं हैं। अतः सूचना तथा अभिलेख संग्रहीत करने और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के मानकों को क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करना तथा उन्हें प्रवृत्त करना कठिन हो गया है।

अतएव किसी एक ही विधि के अधीन समस्त निजी विश्वविद्यालयों को शासित करने हेतु एक अम्ब्रेला अधिनियम बनाये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

---

No. 1451(2)/LXXIX-V-1–19-1(Ka)11-19
*Dated Lucknow, August* 6, 2019

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2019 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 2019) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 5, 2019. The Uchcha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

## THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES ACT, 2019

(U.P. Act no. 12 of 2019)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

*to provide for establishment of new Private Universities and incorporation of existing Private Universities in the State of Uttar Pradesh under this Act for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.*

IT IS HEREBY enacted in the Seventieth Year of the Republic of India as follows: -

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.

(2) It shall extend to whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the *Gazette*, appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,- Definitions

(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;

(b) "AICTE" means All India Council for Technical Education established under section 3 of the all India Council for Technical Education Act, 1987;

(c) "Board" means the Board of Faculties, Board of Studies and the Planning Board, or any other Board of the University;

(d) "CSIR" means the Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi, a funding agency of Central Government;

(e) "Department" means a Department of Studies and includes a Centre of Studies and Research;

(f) "Director" means the Head of an "Institute", "Centre" or "School", or the person appointed for the purpose to act as such in his absence;

(g) "DST" means the Department of Science and Technology of the Central Government;

(h) "Employee" shall include teaching and non teaching staff of the University;

(i) "Executive Council" means the Executive Council of the University;

(j) "Faculty" means a Faculty of the University;

(k) "Governing Body " means a committee constituted by the sponsoring body;

(l) "Hostel" means "Scholars/Students" Hostel of the University;

(m) "ICAR" means the Indian Council of Agricultural Research;

(n) "Institute/School" means an Institute or School established by the University in accordance with this Act and the Statutes;

(o) "MCI" means Medical Council of India constituted under the Medical Council Act, 1956;

(p) "Minority Private University" means a Private University established by a religious or linguistic minority of the State of Uttar Pradesh;

(q) "NAAC" means the National Assessment and Accreditation Council;

(r) "NCC" means National Cadet Corps;

(s) "NCTE" means the National Council for Teacher Education under the National Council for Teacher Education Act, 1993;

(t) "NSS" means National Service Scheme;

(u) "PCT" means Pharmacy Council of India constituted under section 4 of the Pharmacy Act, 1948;

(v) "Chancellor or President", "Pro-Chancellor or Vice-President", "Vice-Chancellor" and "Pro-Vice-Chancellor" means respectively the "Chancellor" or "President", the "Pro-Chancellor or Vice-President" the "Vice-Chancellor" the "Pro-Vice-Chancellor" of the University;

(w) "Prescribed" means prescribed by Statutes;

(x) "Records and Publications" means the Records and Publications of the University;

(y) "Regulatory Body" means the statutory bodies established by the Central Government from time to time such as University Grants Commission and includes the All India Council for Technical Education, the Bar Council of India, the Distance Education Council, the Dental Council of India, the Indian Nursing Council, the Medical Council of India, the National Council for Teacher Education, Central Council for Indian Medicine, the Pharmacy Council of India;

(z) "Schedule" means schedule appended to this Act;

(aa) "Sponsoring body" in relation to a University established under this Act means :–

(i) a Society registered under the Societies Registration Act, 1860 (Act no. 21 of 1860);

(ii) any public trust registered under the Indian Trusts Act, 1882 (Act no. 2 of 1882);

**or**

(iii) a company registered under the Companies Act, 2013 (Act no. 8 of 2013);

(ab) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations" means respectively, the Statutes, the Ordinances and the Regulations of the University for the time being in force;

(ac) "Student" means a student enrolled with the University;

(ad) "Teacher of the University" means Professors, Associate Professors, Assistant Professors, and such other persons as may be appointed for imparting education instructions, or conducting research in the University and are designated as Teachers by the Ordinances;

(ae) "Treasurer", "Registrar", "Finance Officer", "Controller of Examinations", "Librarian" or, "Proctor" means respectively the Treasurer, the Registrar, the Finance Officer, the Controller of Examinations, the Librarian or the Proctor of the University;

(af) "UGC" means University Grants Commission established under section 4 of the University Grant Commission Act, 1956;

(ag) "University" means a Private University established or incorporated under this Act.

Conditions for the establishment of the University

3. The sponsoring body shall, for the purposes of establishing the University under this Act, fulfill the following conditions, namely:-

(a) create a Permanent Endowment fund with minimum of Rs. 05 (five) crore;

(b) duly possess contiguous land of minimum twenty acres in urban areas or fifty acres in rural areas earmarked for the University:

Provided that, the sponsoring body shall not sell, transfer or lease out such land or any part thereof and also shall not use it for any purpose other than the purposes mentioned in this Act for the functioning of the University:

Provided further that such land shall not be mortgaged to any person other than a bank or financial institution established under any law for the time being in force for any purpose other than availing loan for establishing the University;

(c) construct on land referred to in clause (b) buildings of at least twenty four thousand sq. metres carpet area, out of which minimum fifty per cent shall be utilized for academic and administrative purposes;

(d) install equipments, computers, furniture, assets, infrastructural facilities other than building mentioned in clause (b) and other consumables and non consumables of minimum Rs. 2 (two) crore in offices and laboratories in the building referred to in clause (b); and an undertaking of procuring the computers, furniture, assets, infrastructural facilities [other than building mentioned in (b) above] and other consumables and non consumables of minimum Rs 6 (Six) crore in the next 5 years;

(e) appoint Professors, Associate Professors and Assistant Professors as prescribed by the regulatory bodies and supporting staff members in every department or discipline. At least seventy five per cent of the regular teachers in each department/discipline shall be regular employees of the University;

(f) purchase of books, periodicals and online resources worth Rs. ten lakh every year in the library:

Provided that in case of shortfall of expenditure to Rs ten lakh it shall be met in the next year;

(g) arrange co-curricular Activities, extracurricular Activities, debates, competitions, quiz programs, sports, NSS and NCC for the students as per the standards of regulatory bodies;

(h) conform to standards, conditions and Regulations set by UGC, AICTE, NCTE, BCI and other regulatory bodies established by the State Government or Central Government;

(i) establish a provident fund for the employees and teachers of the University and to introduce other welfare schemes;

(j) make the Statutes, Ordinances and Regulations for the administration and functioning of the University;

(k) any arrangements made by the University shall not be inconsistent to the provisions of this Act and regulations of the regulatory bodies;

(l) to ensure transparent functioning of the University and shall put the clearances obtained from the Regulatory Bodies in the public domain;

(m) furnish information to the State Government as per format and periodicity required by the State Government;

(n) comply with the norms set up by the State Government for common academic calendar, anti copying measures, admissions, examinations, degrees and certificates *etc.* ;

(o) the transparent procedure and standard of admissions and fee structure in the University shall be decided and placed in the public domain before the start of the admission process. The last date of admission shall be as per the common academic calendar ;

Admission policy of foreign students shall be decided by the Executive Council of the University and shall be consistent with the standards laid down by the State Government and Regulatory Bodies ;

(p) follow the Common academic calendar as may be prescribed ; and

(q) to undertake to fulfill such other conditions consistent with this Act as may be laid down by the State Government before the establishment of the University;

(r) to undertake neither to be involved nor to permit anyone to cause or promote anti-national activities inside the campus of the University or under the name of the University. In case of any such activity found in the University, it shall be considered as a major violation of the conditions of setting up the University and the Government may take action according to the provisions under this Act or any law for the time being in force.

Submission of proposal for establishment of a new University

4. (1) An application containing the proposal and the project report to establish a University shall be made by the sponsoring body to the State Government along with application fee as may be fixed by the State Government from time to time.

(2) The project report must contain the following particulars, namely:-

(a) the details of the sponsoring body along with copies of its registration certificate and bye-laws duly certified by its competent authority;

(b) the information regarding financial resources of the sponsoring body along with audited accounts for the past three years;

(c) the name and location of the proposed University;

(d) the objectives of the University;

(e) the availability of land and details of buildings and infrastructure facilities, if the same already exists, and details of land, building and other infrastructure proposed to be owned or created;

(f) the nature and the type of programmes of study and research proposed to be undertaken by the University and their relevance to the development goals and employment needs of the State and phasing of such programmes over the first five years with course-wise enrolment targets;

(g) details of proposed academic facilities including teaching and non-teaching staff;

(h) facilities, courses of study and research proposed to be started;

(i) the experience and expertise in the concerned disciplines available with the sponsoring body;

(j) the details of plans for campus development such as construction of buildings, development of structural amenities and infrastructure facilities and procurement of equipment *etc.* to be undertaken before the University starts functioning and phased programmes for the first five years;

(k) the phased outlays of capital expenditure proposed for the next five years;

(l) the sources of funds along with the scheme for mobilizing resources, the cost of capital thereto and the manner of repayment to such sources;

(m) the system proposed to be followed for selecting students for admission to the courses of study at the University in the first year of operation;

(n) the system proposed to be followed for appointment of teachers and other employees in the University;

(o) whether the University proposes to undertake some programmes related to local needs. If so, the nature of specialized teaching, training or research Activities to be undertaken by the University so as to fulfil this objective;

(p) whether the University proposes to start some programmes for the benefit of farmers, women and local industries, if so, details thereof may be given;

(q) details of play grounds and other facilities available or proposed to be created for games and sports and extra curricular activities like National Cadet Corps, National Service Scheme, Rover and Rangers *etc*;

(r) the arrangements proposed to be made for academic excellence, if any;

(s) such other details as the sponsoring body may like to give;

(t) such other details as may be decided by the State Government from time to time.

Evaluation of proposals by evaluation committee

5. (1) The Higher Education Department of the State Government on receipt of the proposal along with the project report for establishment of a University shall constitute a committee consisting of :–

(a) one Vice-Chancellor of any of the State Universities established under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973;

(b) one Professor of a State University nominated by the State Government;

(c) one officer to the Government of Uttar Pradesh not below the rank of Joint Secretary;

(d) one Officer of Finance and Account Services of Uttar Pradesh not below the rank of Joint Director;

(e) one officer nominated by the District Magistrate of the District concerned not below the rank of Sub-divisional Magistrate;

(f) one Registrar of a University established under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 to be nominated by the State Government.

(2) The committee shall consider the proposal and the project report together with the financial soundness and assets of the sponsoring body and its overall ability to set up the proposed University.

(3) The committee, while considering the proposal and the project report may call for such other information from the sponsoring body as it thinks proper for the purpose.

(4) The committee shall submit its report to the Higher Education Department of the State Government within a period of three months from the date of its constitution:

Provided that if the Committee could not submit its report within the said three months period for any sufficient reasons to be recorded in writing, it may submit its report to the Higher Education Department of the State Government within further one month or such period as may be permitted by the State Government:

Provided further that the inspections carried out by any committee constituted under the orders of the State Government before the commencement of this Act shall be deemed to be the inspection carried out by the evaluation committee constituted under sub-section (1) above.

Issuance of letter of intent and submission of compliance report by sponsoring body

6. (1) After the receipt of the report of the committee constituted under section 5, if the State Government is satisfied that it is proper to establish the University, it may issue a 'Letter of Intent'.

(2) The sponsoring body shall fulfill the requirements and conditions specified in section 3 and shall submit to the State Government compliance report thereof supported by an affidavit within a maximum period of two years from the date of issue of the letter of intent.

(3) If the sponsoring body fails to comply with the provisions of section 3, the State Government shall have power to withdraw the letter of intent issued to the sponsoring body.

Establishment or incorporation of a new University

7. (1) The State Government, if satisfied, after considering the compliance report submitted under section 3 that the sponsoring body has complied with the provisions of sub-section (1) of section 6, may, by a notification published in the *Gazette* permit the University to operate with such name and location as per the letter of Intent.

(2) Names of the new Universities to be established under this Act shall be included in Schedule-2 by amending this Act.

(3) After its establishment, the name of the newly established University shall be mentioned by the State Government at the next serial number below the last University mentioned in the Scheduled-2 appended this Act.

(4) Every University established or incorporated under this Act shall be a body corporate.

Incorporation of the existing Universities

8. On the commencement of this Act the existing Universities enumerated in Schedule-1 shall stand incorporated under this Act.

Prohibition for affiliation

9. The University shall not admit any college or institution to the privilege of affiliation.

Objects of the University

10. The objects of the University shall be to disseminate and ensure advancement of knowledge and skill for providing instructional, research and extension facilities in such branches of learning as it may deem fit and the University shall endeavour to provide to students and teachers the necessary atmosphere and facilities for the promotion of :-

(a) innovations in education, leading to restructuring of courses, new methods of teaching, training and learning including online learning, blended learning, continuing education and such other modes and integrated and wholesome development of personality;

(b) studies in various disciplines;

(c) interdisciplinary studies;

(d) national integration, patriotism, secularism, social equity and inculcation of international understanding and ethics.

Powers of the University

11. Subject to the guidelines and norms as prescribed by the Regulatory Bodies and the State Government from time to time the University shall have the powers, -

(a) to provide for instruction in such branches of learning as the University may, from time to time, determine and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge and skills;

(b) to provide for instruction in such branches of learning as the University may think fit and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge;

(c) to honour educational stalwarts and persons of academic eminence with designation of professor Emeritus;

(d) to grant, subject to such conditions as the University may determine, diplomas or certificates to, and confer degrees or other academic distinctions on the basis of examinations, evaluation or any other method of testing of persons, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

(e) to confer honorary degrees or other distinctions with prior approval of the State Government;

(f) to institute as per norms of Regulatory Authorities and State Government Directorships, Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships, and other teaching or academic posts required by the University and to make appointments for the same;

(g) to create administrative, ministerial and other posts and to make appointments thereto;

(h) to appoint/engage persons of eminence, working in any other University or organization permanently or for a specified period;

(i) to co-operate, collaborate or associate with any other University or Authority or Institution in India and abroad in such manner and for such purpose as the University may determine;

(j) to establish and maintain schools, centres, specialized laboratories in other units for research and instructions as are in the opinion of the University, necessary for the furtherance of its objects;

(k) to institute and award fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(l) to establish, maintain and supervise residences, hostels and promote the health and general welfare Activities for students and staff;

(m) to make provisions for research and consultancy, and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;

(n) to establish a faculty, a department, a centre, or school, as the case may be, in accordance with the Act and Statutes;

(o) to determine standards in accordance with the State Government and other Regulatory Bodies for admissions into the University, which may include examination, evaluation or any other method of testing to ensure quality;

(p) to demand and receive payment of fees and other charges;

(q) to make special arrangements in respect of women and other disadvantaged students as the University may consider desirable;

(r) to regulate and enforce discipline among the employees and students of the University and take such disciplinary measures in this regards as may be deemed necessary by the University;

(s) to make arrangements for promoting the health and general welfare of the employees of the University;

(t) to receive donations and to acquire, hold and manage any property, movable or immovable for the welfare of the University;

(u) to ensure that no immovable property shall be disposed off or rights or title therein parted with or any liability created thereon, by any of the officers or authorities of the University, except after prior approval of the State Government;

(v) to appoint either on contract or otherwise, visiting professors emeritus professors, consultants, fellows, scholars, artists, course directors and such other persons who may contribute to the advancement of the objects of the University;

(w) to organize and to undertake extramural studies and extension service; and

(x) to do all such other acts and things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University.

Admission and Standards

12. (1) Admissions to the different academic programmes shall be made in accordance with the norms to be determined by the admissions committee in accordance with the provisions of the Act, the Statutes, Ordinances made thereunder.

(2) The University shall ensure that the academic standards of the courses offered by the University are in accordance with the guidelines of the Regulatory Bodies.

(3) The teacher-student ratio shall be in accordance with the guidelines of the Regulatory Bodies.

University open to all classes and creeds

13. The University shall be open to persons of all sex and of whatever race, creed, caste or class, and it shall not be lawful for the University to adopt to impose on any person any test whatsoever of his religious belief or profession in order to entitle him to be admitted therein as an officer, a teacher, staff member, student, or to hold any office therein or to graduate thereat :

Provided that reservation in the posts and recruitment of the employees and reservation of seats for admission in any course of study in the University for the students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Sections of General Category of citizens shall be regulated by the orders and guidelines of the State Government issued from time to time.

Officers of the University

14. The following shall be the Officers of the University:-

(1) the Chancellor or the President;
(2) the Pro-Chancellor or Vice-President;
(3) the Vice-Chancellor;
(4) the Pro-Vice-Chancellor;
(5) the Registrar;
(6) the Dean of Faculty;
(7) the Dean of Students' Welfare;
(8) the Director;
(9) the Controller of Examinations;
(10) the Chief Proctor;
(11) the Finance Officer; and
(12) such other Officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.

The Chancellor or the President

15. (1) The Chancellor/President shall be appointed by the Governing Body for a period of five years by following such procedure and on such terms and conditions as may be prescribed.

(2) The Chancellor/ President shall be the head of the University.

(3) The Chancellor/President shall preside over the meetings of the Governing Body and convocation of the University.

(4) If, at any time, upon representation made or otherwise, and after making such inquiry, as may be deemed necessary, the situation so warrants that the continuance of the Chancellor/President is not in the interest of the University, Governing Body, may, by majority decision ask the Chancellor/ President by an order in writing stating the reasons therefor, to relinquish his office before expiration of his tenure from such date as may be specified in the order. In such case the Pro-Chancellor/Vice-President shall preside over the meeting of the Governing Body:

Provided that before taking an action under this sub-section, the Chancellor/President shall be given an opportunity of being heard.

(5) The Chancellor/the President shall have the following powers, namely:-

(a) to call for any information or record of the University;

(b) to appoint the Vice-Chancellor under sub-section (1) of section 17 of this Act ;

(c) to remove the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of this Act and Statutes made thereunder;

(d) such other powers as may be prescribed.

(6) The Chancellor/President shall draw salary not exceeding double the amount of salary of the Pro-Chancellor/the Vice-President of the University.

The Pro-Chancellor or Vice-President

16. (1) The Pro-Chancellor/Vice-President shall be appointed by the Chancellor/President with the approval of the Governing Body for a period of five years.

(2) The Pro-Chancellor/Vice-President shall assist the Chancellor, President, respectively in discharging his/her duties and preside at the convocation in his/her absence.

(3) The Pro-Chancellor/Vice-President may in writing under his hand addressed to the Chancellor/President resign from his office.

(4) If, at any time, upon representation made or otherwise, and after making such inquiry, as may be deemed necessary, the situation so warrants that the continuance of the Pro-Chancellor/Vice-President is not in the interest of the University, the Pro-Chancellor/Vice-President with the prior approval of the Governing Body, may, by an order in writing stating the reasons therefor, ask the Pro-Chancellor/Vice-President to relinquish his office before expiration of his tenure from such date as may be specified in the order:

Provided that before taking an action under this sub-section, the Pro-Chancellor/Vice-President shall be given an opportunity of being heard.

(5) The Pro-Chancellor/Vice-President shall draw salary which shall be less than that of the Chancellor/President of the University.

The Vice-Chancellor

17. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor/President with prior approval of the Governing Body:

Provided that a Vice-Chancellor shall be eligible for reappointment after the expiry his/her term.

(2) The Vice-Chancellor shall hold office for a period of five years or until he/she attains the age of seventy years whichever is earlier.

(3) If, at any time, upon representation made or otherwise, and after making such inquiry, as may be deemed necessary, the situation so warrants that the continuance of the Vice-Chancellor is not in the interest of the University, the Governing Body may, by an order in writing stating the reasons therefor, ask the Vice-Chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order:

Provided that before taking an action under this sub-section, the Vice-Chancellor shall be given an opportunity of being heard.

(4) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall exercise general superintendence and control over the affairs of the University and shall be the chairperson of the Executive Council and execute the decisions of the Executive Council and other competent bodies and the State Government made under the provisions of the Act and the Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder.

(5) The Vice-Chancellor shall preside over the convocation of the University in the absence of the Chancellor/President and the Pro-Chancellor/Vice-President.

(6) If in the opinion of the Vice-Chancellor, it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under this Act, he may take such action as he deems necessary and shall at the earliest opportunity thereafter report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter within a period of thirty days :

Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the Vice- Chancellor, then such case shall be referred to the Chancellor/President, whose decision thereon shall be final.

(7) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such duties as may be provided under this Act and the Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder.

The Pro-Vice-Chancellor

18. (1) The Pro-Vice- Chancellor shall be appointed by the Vice- Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed by the Statutes and provided in the Ordinances and regulations.

(2) The Pro-Vice Chancellor appointed under sub-section (1) shall discharge his duties in addition to his duties as a Professor.

(3) The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in discharging day to day duties as and when required by the Vice- Chancellor.

(4) The Pro-Vice-Chancellor shall get honorarium of such amount as may be determined by the Sponsoring Body.

The Registrar

19. (1) The qualifications, term of office, conditions of service and procedure of appointment of the Registrar shall be such as may be prescribed.

(2) The Registrar shall have the power to authenticate records on behalf of the University.

(3) The Registrar shall be responsible for the due custody of records and the common seal of the University. He shall be the *ex-officio* Secretary of the Governing Body, the Executive Council, the Academic Council and the Admissions Committee and every Selection Committee for appointment of teachers of the University, and shall be bound to place before these authorities all such information as may be necessary for transaction of their business. He shall also perform such other duties as may be prescribed by the Statutes, Ordinances and Regulations, and required, from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor but he shall not by virtue of this sub-section, be entitled to vote.

Dean of Faculty

20. Every Dean shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

Finance Officer

21. (1) The Finance Officer shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

(2) The Finance Officer shall be the *ex-officio* Secretary of the Finance Committee.

Other Officers

22. The manner of appointment and powers and duties of the other officers of the University including the Dean of Students' Welfare, Controller of Examinations and Chief Proctor shall be such as may be prescribed.

Authorities of the University

23. The following shall be the Authorities of the University:-

(1) the Governing Body ;

(2) the Executive Council ;

(3) the Academic Council;

(4) the Finance Committee ;

(5) the Planning Board;

(6) the Board of Faculties;

(7) the Board of Studies;

(8) the Admissions Committee;

(9) the Examinations Committee; and

(10) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

The Governing Body

24. (1) The constitution of the Governing Body and the term of office of its members shall be such as may be prescribed.

(2) The Governing Body shall meet once a year on the date to be fixed by the Chancellor/President and such meeting shall be called the annual meeting of the Governing Body:

Provided that the Chancellor/President may, whenever he thinks fit, and shall, upon a requisition in writing signed by not less than one fourth of the total membership of the Governing Body, convene a special meeting of the Governing Body.

(3) Subject to provisions of this Act, the Governing Body shall Act as an advisory Body of the University and have the following powers and functions, namely:-

(a) to review from time to time, the broad policies and programmes of the University and suggest measures for the working, improvement and development of the University;

(b) to consider and pass resolutions on the Annual Report and Annual accounts of the University and Audit Report of such accounts and furnish their views to the Executive Council;

(c) to advise the President in respect of any matter which may be referred to it for advice;

(d) to perform such other functions as may be prescribed.

The Executive Council

25. (1) The Executive Council shall be the principal executive body of the University.

(2) The meeting of the Executive Council may be convened as may be prescribed.

(3) The administration, management and control of the University and the income thereof shall be vested with the Executive Council which shall control and administer the property and funds of the University.

(4) The Executive Council, subject to the provisions of this Act, have the following powers and duties:–

(i) to hold and control the property and funds of the University;

(ii) to acquire any movable or immovable property on behalf of the University;

(iii) to make, amend or repeal Statutes and Ordinances;

(iv) to administer any funds placed at the disposal of the University for specific purposes;

(v) to approve the budget of the University;

(vi) to institute scholarships, fellowships, bursaries, medals and other rewards in accordance with the Statutes and Ordinances;

(vii) to appoint Registrar, officers, teachers and employees of the University and define the duties and conditions of their service;

(viii) to fix the honorarium, emoluments, traveling and other allowances of the examiners;

(ix) to direct the form and use of the common seal of the University;

(x) to regulate and enforce discipline among members of the teaching, administrative and other staff of the University in accordance with the Statutes and Ordinances;

(xi) to manage and regulate the finances, accounts, investments, property and all other administrative affairs of the University;

(xii) to invest any money belonging to the University including endowed property;

(xiii) to provide the buildings, premises, furniture, equipments, apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;

(xiv) to enter into, vary, carry out, and cancel contract on behalf of the University;

(xv) to regulate and determine all other matters concerning the University in accordance with this Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations.

(5) Every decision of the Executive Council shall be informed by the reasons therefor.

(6) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Executive Council, which shall consist of the following other members, namely :–

(i) three members to be nominated by the Governing Body;

(ii) two eminent educationists nominated by the President;

(iii) one officer of the State Government not below the rank of Joint Secretary to the Government of Uttar Pradesh;

(iv) one Professor and one Associate Professor of the University in order of seniority on rotation basis for a period of one year;

(v) one educationist not below the rank of Associate Professor from a panel of three names to be approved by the State Government, for which the University shall submit a list of three names of eminent educationists;

(vi) the Registrar who shall be *ex-officio* Member Secretary;

(vii) the Finance Officer shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Executive Council but shall not be entitled to vote;

(7) Quorum of the meeting of the Executive Council shall not be less than six members.

(8) Decisions at any meeting of the Executive Council shall be taken by majority of the members present at such meeting:

Provided that, in case of tie in any proposal, the proposal having support of the Vice-Chancellor shall prevail.

The Academic Council

26. (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall subject to the provisions of the Statutes, the Ordinances and Regulations, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

(2) The constitution of the Academic Council, the term of office of its members and its powers and functions shall be such as may be prescribed.

The Finance Committee

27. (1) The Finance Committee shall be the principal financial body of the University to take care of the financial matters.

(2) The constitution, powers and functions of the Finance Committee shall be such, as may be prescribed.

The Planning Board

28. (1) The Planning Board shall be the principal planning body of the University. The Board shall ensure that the infrastructure and academic support system meets the norms of the University Grants Commission and other Regulatory Bodies.

(2) The constitution, of the Planning Board, term of office of its members and its powers and functions shall be such as may be prescribed.

Board of Faculty, Board of Studies, Admissions Committee, Examinations Committee and other Authorities of the University

29. The constitution, powers and functions of the Board of Faculties, the Admissions Committee, the Examinations Committee and of such other authorities of the University which may be declared by the Statutes to be authorities of the University, shall be such as may be prescribed.

Disqualification for membership of a body

30. A person shall be disqualified for being a member of any of the authorities or bodies of the University, if he/she–

(1) is of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(2) is an undischarged insolvent;

(3) has been convicted of any offence involving moral turpitude;

(4) has been punished for indulging in or promoting unfair practice in the conduct of any examination, in any form, anywhere;

(5) has any profit motive from University except salary or any other authorised emoluments;

(6) applies University fund for his personal use.

Vacancies not to invalidate the proceedings of any authority or body of the University

31. No decision, Act or proceeding of any authority or body of the University shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution thereof.

Filling up of emergent vacancies

32. Any vacancy occurred in the membership of any authority or body of the University due to death, resignation or removal of a member or due to change of capacity in which he was appointed or nominated, shall be filled up as early as possible by the person or the body who had appointed or nominated such a member:

Provided that the person appointed or nominated as a member of an authority or body of the University on an emergent vacancy, shall remain member of such authority or body, for only the remaining period of the member, in whose place he is appointed or nominated.

Committees

33. The authorities or officers of the University may constitute such committees or sub-committee with such terms of reference, in conformity with the Act, Statutes, Ordinances and Regulations, as may be necessary for specific tasks to be performed by such committees. The constitution of such committees or sub-committee and their duties shall be such as may be determined by the authority or officer constituting the Committee or sub-committee.

Power to make statutes

34. (1) The first Statutes of the Universities established or incorporated under this Act shall be made by the Executive Council and shall be submitted to the State Government for its approval.

(2) The Government shall consider the First Statutes submitted by the University and shall approve it within three months from the date of its receipt. If the State Government does not approve or communicate to the University the objections thereon within the time mentioned above, statutes so submitted shall be deemed to be approved.

(3) Subject to the provisions of this Act the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the constitution, powers and functions of the authorities of the University, as may be constituted from time to time;

(b) the appointment and continuance in office of the members of the said authorities, filling of vacancies of members of the said authorities, filling of vacancies of members and all other matters relating to those authorities for which it may be necessary to provide;

(c) the appointment, powers and functions of the officers of the University and their emoluments;

(d) the appointment of teachers of the University and other academic and administrative staff and their emoluments;

(e) the appointment of teachers and other academic and administrative staff working in the University or Institution for specific period for undertaking a joint project;

(f) the conditions of service of employees including provisions for retirement benefits, insurance and provident fund, the manner of termination of their service and the disciplinary matters;

(g) the principles governing seniority of service of employees;

(h) the procedure for settlement of disputes between employees or students and the University;

(i) the procedure for appeal to the Executive Council by any employee or student against the action of any officer or other authority of the University;

(j) the conferment of honorary degrees;

(k) the withdrawal of degree, diploma, certificate and other academic distinctions;

(l) the institution of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(m) the maintenance of discipline among the students;

(n) the establishment and abolition of Departments, Centers and other institutions *etc.* within the campus of the University;

(o) the delegation of powers vested in the authorities or officers of the University; and

(p) all other matters, as per this Act or as may be prescribed.

(4) The Executive Council shall not make, amend or repeal any Statute affecting the powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion in writing on the proposed changes and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council.

Power to make Ordinances

35. Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances shall be made by the Executive Council which may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the admission of students to the University and their enrolment as such;

(b) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University;

(c) the medium of instruction and examinations;

(d) the award of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the qualifications for the same and the measures to be taken relating to the granting and obtaining of the same;

(e) the fees to be charged for courses of study in the University and for admissions to the examinations, degrees, diplomas and certificates of the University;

(f) the conditions for the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(g) the conduct of examinations, including the term of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(h) the conditions of residence of the students of the University;

(i) the special arrangements, if any, which may be made for the residence, discipline and teaching of women students and prescribing of special courses of studies for them within the University;

(j) the appointment and emoluments of employees other than those for whom provision has been made in the Statutes;

(k) the establishment of Centre of Studies, Board of Studies, Interdisciplinary Studies, Special Centers, Specialized Laboratories and other Committees;

(l) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and authorities including professional bodies or associations;

(m) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic stature of the University;

(n) the remuneration to be paid to the examiners, moderators, invigilators and tabulators; and

(o) such other terms and conditions of service of teachers and other academic staff as are not prescribed by the Statutes.

Annual Report

36. (1) The Annual Report of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall be submitted to the Governing Body on such date as may be prescribed and the Governing Body shall consider the report in its annual meeting.

(2) The Governing Body shall submit its comments on the Annual Report to the Executive Council for its considerations.

Annual Accounts

37. (1) The Annual Accounts and Balance Sheet of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council and shall, once at least every year and at intervals of not more than fifteen months, be audited by an experienced and qualified firm of Chartered Accountants of repute.

(2) A copy of the Annual Accounts, together with the audit report thereon, shall be submitted to the Governing Body and the Chancellor/President along with the observations of the Executive Council.

(3) Any observations made by the President on the annual accounts shall be brought to the notice of the Governing Body and the Executive Council and the observations, if any, shall, after review by the Executive Council, be submitted to the Chancellor/President and shall be put in the public domain.

Conditions of service of employees

38. (1) Every employee of the University shall be appointed/engaged as per the provisions of this Act and Statutes made thereunder.

(2) Any dispute arising between the University and any of the regular employees, shall be referred to the Vice-Chancellor who shall decide the dispute after affording an opportunity to the employee within three months from the date of receipt of its reference.

(3) Any dispute in respect of any employee engaged temporarily or on *ad-hoc* or part time or casual basis shall be heard and decided by the Vice-Chancellor.

Right to Appeal

39. (1) An aggrieved person may prefer an appeal to the Chancellor/President against any decision of an officer or authority of the University within a period of three months from the date of receipt of such decision:

Provided that the Chancellor/President shall have power to condone the delay if he is satisfied that the appellant for sufficient reasons could not have preferred his appeal within the stipulated time.

(2) Any decision taken by the Chancellor/President in such an appeal shall be final.

Employees Provident Fund and Pensions

40. The University shall constitute for the benefit of its employees such pension or welfare schemes or Provident Fund or provide such insurance schemes as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be decided by the Executive Council.

Mode of proof of University records

41. A copy of any receipt, application, notice, proceeding, resolution of any authority or Committee of the University or other documents in possession of the University, if certified by the Registrar, shall be received as *prima-facie* evidence of the such receipt, applications, notice, order, proceeding or resolution, documents or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein where the original would, if produced, have been admissible in evidence.

Publication of Statues, Ordinances and Regulations

42. Every Statute, Ordinances and Regulations made under this Act shall be published by the University.

Permanent Endowment Fund

43. (1) The Sponsoring body shall establish a permanent Endowment Fund of at least Rs. 5 (five) crore.

(2) The Endowment fund shall be used as security deposit to ensure that the University complies with the provisions of this Act and functions as per provisions of this Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations. The State Government shall have the powers to forfeit, a part or whole of the Endowment Fund, in case the University or the Sponsoring Body contravenes the provisions of this Act, the Statutes, the Ordinances or the Regulations made thereunder.

(3) The University may utilize the income from Endowment Fund for the development of infrastructures of the University or for meeting the recurring expenditure of the University.

(4) The amount of Endowment Fund shall be invested in such instruments as the State Government may prescribe by rules and shall be kept invested until the dissolution of the University.

(5) In case of investment in long term security, and in case of deposit in the interest bearing Personal Deposit Account in the Government Treasury, deposit shall be made with the condition that the amount shall not be withdrawn or utilized without the prior permission of the State Government.

General Fund

44. (1) The University shall establish a general fund to which the following amount shall be credited, namely:-

(a) all fees which may be charged by the University;
(b) all sums received from any other sources;
(c) all contributions made by the Society ; and
(d) all contributions made in this behalf by any other person or bodies which are not prohibited by any law for the time being in force.

(2) The money credited to the general fund shall be applied to meet all the recurring expenditures of the University.

Development Fund

45. (1) The University shall also establish a development fund to which the following moneys shall be credited, namely:–

(a) development fees, which may be charged from students;
(b) all sums received from other sources for the purpose of the development of the University;
(c) all contributions made by the Sponsoring Body;
(d) all contributions made in this behalf by any other person or bodies which are not prohibited by any law for the time being in force; and
(e) all incomes received from the permanent endowment fund.

(2) The moneys credited to the development fund from time to time shall be utilized for the development of the University.

Maintenance of Funds

46. All funds established under this Act shall subject to general supervision and control of the Executive Council and be regulated and maintained in such manner as may be prescribed.

The University shall be self financed

47. The University shall not be eligible for any grants in aid or any financial assistance from the State Government or any other body or Corporation owned and controlled by the State Government.

Fees

48. The fee structure for all purposes shall be decided by the Executive Council provided that the University shall not charge any fee from its students in excess of what is required under any law of the State Government at the time being in force or as fixed by the Regulatory Bodies and the fees structure shall be put in public domain.

Accreditation of the University

49. Within a period of five years from commencement of programmes, the University shall obtain NAAC and other such accreditations as may be prescribed by the State Government from time to time. It shall also obtain certification/accreditation from such other Regulating Bodies which are connected with the courses taken up by the University. It shall inform the State Government about the grade provided to the University. The University shall ensure renewal of such accreditation from time to time.

Convocation

50. The convocation of the University shall be held in every academic year in the manner as may be prescribed by the Statutes, the Ordinances and the Regulations for conferring degrees, diplomas or for any other purpose.

The Uttar Pradesh Higher Education Council shall be the nodal agency for Private Universities

51. (1) To ensure the compliance of the provisions of this Act, Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder, the Uttar Pradesh State Higher Education Council shall be the nodal agency.

(2) The records of the students admitted to the different courses of the University and their results and the records of the students not appearing in the examinations shall be provided to the Uttar Pradesh Higher Education Council. The final degree shall be conferred to the students with approval of the Uttar Pradesh Higher Education Council. The names of the persons to be awarded the degrees shall be submitted to The Uttar Pradesh Higher Education Council before 30 days of the date of convocation and the Council shall approve the list. In case approval of the Council is not communicated to the University within 20 days, the list shall be deemed to be approved.

(3) The Uttar Pradesh Higher Education Council may call from the University or any authority or officer of the University to furnish any information or records of the University within specified date and time failing which the Uttar Pradesh Higher Education Council may send the report to the State Government for appropriate action.

(4) The Uttar Pradesh Higher Education Council shall conduct atleast one annual inspection of the Universities established under this Act for the purpose of compliance of the provisions of this Act and to ensure imparting of quality education and submit its annual inspection report to the State Government specifically regarding the compliance of the undertaking given under section 3 of this Act.

Power of State Government to call for information and records

52. (1) It shall be the duty of the University or any authority or officer of the University to furnish such information or records relating to the administration or finances and other affairs or activities *etc.* of the University as the State Government may call for.

(2) The State Government, if it is of the view that there is a violation of the Act, the Statutes, the Ordinances or the Regulations made thereunder may issue such directions to the University under this Act as it may deem necessary, and the University shall comply with such directions within the stipulated time.

Dissolution of University

53. (1) If the University proposes its dissolution in accordance with the law governing its constitution or incorporation, it shall give at least one year's written notice to the State Government.

(2) On receipt of notice referred to in sub-section (1), the State Government shall make such arrangements for administration of the University from the date of dissolution of the University and until the last batch of students in regular courses of studies of the University complete their courses or studies in such manner as may be prescribed.

Expenditure of the University during dissolution

54. (1) The expenditure for administration of the University during the taking over of the liabilities of the University under section 53 of the Act shall be met out of the Permanent Endowment Fund, the general fund and the development fund.

(2) During this process, if the funds referred to in sub-section (1) are not sufficient to meet the expenditure and the liabilities of the University, such expenditure may be met by disposing off the properties and assets of the University by the State Government.

Winding up of the University by the State Government

55. (1) If it appears to the State Government that the University has contravened any of the provisions of this Act, Statutes, Ordinances or Regulations made thereunder or has violated any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out any of the undertakings given under section 3 or there is fraud or misappropriation or serious misuse of funds, it may issue direction to the Uttar Pradesh Higher Education Council to conduct preliminary inquiry.

(2) If the State Government, on receipt of inquiry report of the University on the direction issued under sub-section (1), is satisfied that there is a *prima facie* case of contravention of all or any of the provisions of this Act or the Statutes or Ordinances or Regulations made thereunder or of violation of directions issued by it under this Act or of ceasing to carry out the undertaking given under section 3, or there is fraud or misappropriation or serious misuse of funds, it shall make an order of such enquiry as it may consider necessary.

(3) For the purposes of an inquiry under sub-section (2), the State Government shall, by notification, appoint an officer or a committee on the recommendation of the Uttar Pradesh Higher Education Council as the inquiring authority to inquire into the allegations of violation of the provisions of this Act.

(4) Every inquiring authority appointed under sub-section (3) shall while performing its functions under this Act have all the powers of Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 while trying a suit and in particular in respect of the following matters, namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) requisitioning any public record or copy thereof from any office;

(d) receiving evidence on affidavit; and

(e) any other matter which may be prescribed.

(5) If, upon receipt of the inquiry report, the State Government is satisfied that the University has violated any provisions of this Act and there is a need for corrective action, the State Government shall direct the University to make necessary improvements within the specified time, in order to comply with the provisions of this Act. If the University fails to comply with such directions within specified time, the State Government may again direct the University to make necessary improvements or modifications within a period of 15 days from the issuance of such directions.

(6) On receipt of the enquiry report from the enquiry officer or the enquiry committee appointed under sub-section (3), if the State Government is satisfied that the University has contravened all or any of the provisions of this Act or the Statutes or Ordinances or Regulations made thereunder or has violated any of the directions issued by it under this Act including directions issued under sub-section(5) above or has ceased to carry out the undertakings given by it under section 3 or there is fraud or misappropriation or serious misuse of funds in the University which threatens the academic standard of the University, the State Government for liquidation of the University, shall appoint a interim committee consisting of three members to run the affairs of the University during the period.

(7) (i) The interim committee appointed under sub-section (6) shall have all the powers to administer the affairs of the University until the last batch of the students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards as the case may be;

(ii) After having been awarded the degrees, diplomas or awards, as the case may be, to the last batches of the students of the regular courses, the interim committee shall make a report to the effect to the State Government;

(iii) On receipt of the report under sub-section (7) (ii), the State Government shall, by a notification in the Official *Gazette*, issue an order dissolving the University and from the date of publication of such notification, the University shall stand dissolved and all the remaining assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body from such date.

(8) Every notification under sub-section (7), shall be laid before both Houses of the State Legislature.

Power of the State Government to issue directions on policy matters

56. The State Government may issue such directions from time to time to the University on policy matters not inconsistent with the provisions of this Act as it may deem necessary. Such directions shall be complied with by the University, failing which the State Government may take a reasoned action against the University in accordance with this Act.

Status of Assets / Liabilities on dissolution / de-recognition

57. All residual assets and properties including permanent endowment fund, general fund or any other fund and the liabilities of the University shall belong to the Sponsoring Body in case of dissolution of the University under any provision mentioned herein above in the Act.

Power to make rules

58. (1) The State Government may, by notification in the *Gazette*, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the manner of making proposal to establish a University and the application fees payable under sub-section (1) of section 4;

(b) other particulars to be contained in the Project Report under sub-section (2) of section 4;

(c) other matters which are required to be, or may be, prescribed by rules under this Act.

Power to remove difficulties

59. (1) The State Government may for the purposes of removing any difficulties, particularly in relation to the transition from the provisions of the individual Private University Acts to the provisions of this Act, direct that the provisions of this Act shall during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of State Legislature as soon as may be after it is made.

Disputes to be settled in a Court in Uttar Pradesh

60. All disputes arising as a result of the provisions made in this Act shall be settled by a Court of law in the State of Uttar Pradesh.

The Ordinance to have overriding effect

61. The provisions of this Act and the Statutes, Ordinances and Regulations made there under shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law, for the time being in force, made by the State Legislature relating to Universities.

Repeal and savings

62. (1) All the Acts enumerated in the Schedule-1 to this Act shall stand repealed on the commencement of this Act.

(2) Notwithstanding the repeal of the Acts enumerated in the Schedule-1 mentioned in sub-section (1), all the decisions made, Acts performed, rights and liabilities created and exhausted by the Universities established under the repealed Acts shall be deemed to be valid under this Act.

(3) The Universities incorporated into this Act shall modify their Statutes, Ordinances and Regulations applicable thereto under their respective repealed Acts, to bring them in conformity with the provisions of this Act within a period of one year from the date of commencement of this Act.

Minority Private Universities

63. Notwithstanding anything contained in this Act the University established by a religious or linguistic minority of the State of Uttar Pradesh, shall continue to have the privileges as guaranteed by Article 30 of the Constitution of India.

**SCHEDULE-1**

**(See Section-8)**

| Sl. | Details of the Act | Name of the University |
|---|---|---|
| 1 | The Integral University Act, 2004 (U.P. ACT NO. 9 OF 2004) Notification Dated 27-02-2004 | The Integral University, Lucknow |
| 2 | The Amity University Uttar Pradesh Act, 2005 (U.P. ACT NO. 11 OF 2005) Notification Dated 24-03-2005 | Amity University Gautambudh Nagar, Uttar Pradesh |
| 3 | The Mangalayatan University Uttar Pradesh Act, 2006 (U.P. ACT NO. 32 OF 2006) Notification Dated 30-10-2006 | Mangalayatan University Aligarh, Uttar Pradesh |
| 4 | The Swami Vivekanand Subharti University Uttar Pradesh Act, 2008 (U.P. ACT NO. 29 OF 2008) Notification Dated 05-09-2008 | Swami Vivekanand Subharti University, Merrut, Uttar Pradesh |
| 5 | The Teerthanker Mahaveer University Uttar Pradesh Act, 2008 (U.P. ACT NO. 30 OF 2008) Notification Dated 05-09-2008 | Teerthanker Mahaveer University, Moradabad, Uttar Pradesh |
| 6 | The Sharda University Uttar Pradesh Act, 2009 (U.P. ACT NO. 14 OF 2009) Notification Dated 24-03-2009 | Sharda University Greater Noida, Uttar Pradesh |
| 7 | The GLA University Uttar Pradesh Act, 2009 (U.P. ACT NO. 21 OF 2010) Notification Dated 01-09-2010 | GLA University Mathura, Uttar Pradesh |
| 8 | The Invertis University Uttar Pradesh Act, 2009 (U.P. ACT NO. 22 OF 2010) Notification Dated 01-09-2010 | Invertis University Bareilly, Uttar Pradesh |
| 9 | The Monad University Uttar Pradesh Act, 2010 (U.P. ACT NO. 23 OF 2010) Notification Dated 12-10-2010 | Monad University Gaziabad, Uttar Pradesh |
| 10 | The Noida International University Uttar Pradesh Act, 2010 (U.P. ACT NO. 27 OF 2010) Notification Dated 12-10-2010 | Noida International University Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh |
| 11 | The IFTM University Uttar Pradesh Act, 2010 (U.P. ACT NO. 24 OF 2010) Notification Dated 12-10-2010 | IFTM University, Omkar Dham Lodhipur Rajput, Delhi Road Moradabad |
| 12 | Shri Venkateshwara University Uttar Pradesh Act, 2010 (U.P. ACT NO. 26 OF 2010) Notification Dated 12-10-2010 | Shri Venkateshwara, Gajraula, J.P. Nagar |
| 13 | The Babu Banarasi Das University Uttar Pradesh Act, 2010 (U.P. ACT NO. 25 OF 2010) Notification Dated 12-10-2010 | Babu Banarasi Das University, Lucknow |

| | | |
|---|---|---|
| 14 | The Galgotias University Uttar Pradesh Act, 2011 (U.P. ACT NO. 14 OF 2011) Notification Dated 07-04-2011 | The Galgotias University, Gautambudh Nagar |
| 15 | The Shivnadar University Uttar Pradesh Act, 2011 (U.P. ACT NO. 12 OF 2011) Notification Dated 21-06-2011 | The Shivnadar University Dadri Gautambudh Nagar |
| 16 | The Ram Swaroop Memorial University Uttar Pradesh Act, 2011 (U.P. ACT NO. 1 OF 2012) Notification Dated 04-07-2012 | Shri Ram Swaroop Memorial University, Barabanki |
| 17 | The Mohammad Ali Jauhar University Uttar Pradesh Act, 2005 (U.P. ACT NO. 19 OF 2006) Notification Dated 19-06-2006 | The Mohammad Ali Jauhar University, Rampur |
| 18 | The Glocal University Uttar Pradesh Act, 2011 (U.P. ACT NO. 2 OF 2012) Notification Dated 05-07-2012 | The Glocal University Ali Akbarpur, Saharanpur |
| 19 | The Rama University Uttar Pradesh Act, 2013 (U.P. ACT NO. 1 OF 2014) Notification Dated 10-01-2014 | Rama University, Kanpur |
| 20 | The Shobit University Uttar Pradesh Act, 2011 (U.P. ACT NO. 3 OF 2012) Notification Dated 05-07-2012 | Shobit University, Gangoh, Saharanpur |
| 21 | The J.P. University Uttar Pradesh Act, 2014 (U.P. ACT NO. 8 OF 2014) Notification Dated 04-3-2014 | J.P. University Anoop Shahar, Uttar Pradesh |
| 22 | The J.S. University Shikohabad, Firozabad, Uttar Pradesh Act, 2015 (U.P. ACT NO. 7 OF 2015) Notification Dated 24-6-2015 | J.S. University Shikohabad, Firozabad |
| 23 | The IIMT University, Meerut, Uttar Pradesh Act, 2016 (U.P. ACT NO. 32 OF 2016) Notification Dated 03-10-2016 | IIMT University, Meerut, Uttar Pradesh |
| 24 | The Bennett University, Greater Noida, Uttar Pradesh, Act, 2016 (U.P. ACT NO. 24 OF 2016) Notification Dated 16-9-2016 | Bennett University, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar |
| 25 | The Bareilly International University, Uttar Pradesh Act, 2016 (U.P. ACT NO. 26 OF 2016) Notification Dated 16-9-2016 | Bareilly International University, Bareilly |
| 26 | The Sanskriti University, Chhata, Mathura, Uttar Pradesh Act, 2016 (U.P. ACT NO. 20 OF 2016) Notification Dated 16-9-2016 | Sanskriti University, Chhata, Mathura |
| 27 | The Era University, Lucknow, Uttar Pradesh Act, 2016 (U.P. ACT NO. 27 OF 2016) Notification Dated 16-9-2016 | Era University, Lucknow, Uttar Pradesh |

**SCHEDULE-2**

**(See Section-7)**

| Sl. | Details of the Act | Name of the University |
|---|---|---|
| 1 | The Integral University Act, 2004 (U.P. ACT NO. 9 OF 2004) Notification Dated 27-02-2004 | The Integral University, Lucknow |
| 2 | The Amity University Uttar Pradesh Act, 2005 (U.P. ACT NO. 11 OF 2005) Notification Dated 24-03-2005 | Amity University Uttar Gautambudh Nagar, Pradesh |
| 3 | The Mangalayatan University Uttar Pradesh Act, 2006 (U.P. ACT NO. 32 OF 2006) Notification Dated 30-10-2006 | Mangalayatan University Aligarh, Uttar Pradesh |
| 4 | The Swami Vivekanand Subharti University Uttar Pradesh Act, 2008 (U.P. ACT NO. 29 OF 2008) Notification Dated 05-09-2008 | Swami Vivekanand Subharti University, Merrut, Uttar Pradesh |
| 5 | The Teerthanker Mahaveer University Uttar Pradesh Act, 2008 (U.P. ACT NO. 30 OF 2008) Notification Dated 05-09-2008 | Teerthanker Mahaveer University, Moradabad, Uttar Pradesh |
| 6 | The Sharda University Uttar Pradesh Act, 2009 (U.P. ACT NO. 14 OF 2009) Notification Dated 24-03-2009 | Sharda University Greater Noida, Uttar Pradesh |
| 7 | The GLA University Uttar Pradesh Act, 2009 (U.P. ACT NO. 21 OF 2010) Notification Dated 01-09-2010 | GLA University Mathura, Uttar Pradesh |
| 8 | The Invertis University Uttar Pradesh Act, 2009 (U.P. ACT NO. 22 OF 2010) Notification Dated 01-09-2010 | Invertis University Bareilly, Uttar Pradesh |
| 9 | The Monad University Uttar Pradesh Act, 2010 (U.P. ACT NO. 23 OF 2010) Notification Dated 12-10-2010 | Monad University Gaziabad, Uttar Pradesh |
| 10 | The Noida International University Uttar Pradesh Act, 2010 (U.P. ACT NO. 27 OF 2010) Notification Dated 12-10-2010 | Noida International University Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh |
| 11 | The IFTM University Uttar Pradesh Act, 2010 (U.P. ACT NO. 24 OF 2010) Notification Dated 12-10-2010 | IFTM University, Omkar Dham Lodhipur Rajput, Delhi Road Moradabad |
| 12 | Shri Venkateshwara University Uttar Pradesh Act, 2010 (U.P. ACT NO. 26 OF 2010) Notification Dated 12-10-2010 | Shri Venkateshwara, Gajraula, J.P. Nagar |
| 13 | The Babu Banarasi Das University Uttar Pradesh Act, 2010 (U.P. ACT NO. 25 OF 2010) Notification Dated 12-10-2010 | Babu Banarasi Das University, Lucknow |
| 14 | The Galgotias University Uttar Pradesh Act, 2011 (U.P. ACT NO. 14 OF 2011) Notification Dated 07-04-2011 | The Galgotias University, Gautambudh Nagar |

| | | |
|---|---|---|
| 15 | The Shivnadar University Uttar Pradesh Act, 2011<br>(U.P. ACT NO. 12 OF 2011) Notification Dated 21-06-2011 | The Shivnadar University Dadri Gautambudh Nagar |
| 16 | The Ram Swaroop Memorial University Uttar Pradesh Act, 2011<br>(U.P. ACT NO. 1 OF 2012) Notification Dated 04-07-2012 | Shri Ram Swaroop Memorial University, Barabanki |
| 17 | The Mohammad Ali Jauhar University Uttar Pradesh Act, 2005<br>(U.P. ACT NO. 19 OF 2006)<br>Notification Dated 19-06-2006 | The Mohammad Ali Jauhar University, Rampur |
| 18 | The Glocal University Uttar Pradesh Act, 2011<br>(U.P. ACT NO. 2 OF 2012) Notification Dated 05-07-2012 | The Glocal University Ali Akbarpur, Saharanpur |
| 19 | The Rama University Uttar Pradesh Act, 2013<br>(U.P. ACT NO. 1 OF 2014) Notification Dated 10-01-2014 | Rama University, Kanpur |
| 20 | The Shobit University Uttar Pradesh Act, 2011<br>(U.P. ACT NO. 3 OF 2012) Notification Dated 05-07-2012 | Shobit University, Gangoh, Saharanpur |
| 21 | The J.P. University Uttar Pradesh Act, 2014<br>(U.P. ACT NO. 8 OF 2014) Notification Dated 04-3-2014 | J.P. University Anoop Shahar, Uttar Pradesh |
| 22 | The J.S. University Shikohabad, Firozabad, Uttar Pradesh Act, 2015<br>(U.P. ACT NO. 7 OF 2015) Notification Dated 24-6-2015 | J.S. University Shikohabad, Firozabad |
| 23 | The IIMT University, Meerut, Uttar Pradesh Act, 2016<br>(U.P. ACT NO. 32 OF 2016) Notification Dated 03-10-2016 | IIMT University, Meerut, Uttar Pradesh |
| 24 | The Bennett University, Greater Noida, Uttar Pradesh Act, 2016<br>(U.P. ACT NO. 24 OF 2016) Notification Dated 16-9-2016 | Bennett University, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar |
| 25 | The Bareilly International University, Uttar Pradesh Act, 2016<br>(U.P. ACT NO. 26 OF 2016) Notification Dated 16-9-2016 | Bareilly International University, Bareilly |
| 26 | The Sanskriti University, Chhata, Mathura, Uttar Pradesh Act, 2016<br>(U.P. ACT NO. 20 OF 2016) Notification Dated 16-9-2016 | Sanskriti University, Chhata, Mathura |
| 27 | The Era Univesity, Lucknow, Uttar Pradesh Act, 2016<br>(U.P. ACT NO. 27 OF 2016) Notification Dated 16-9-2016 | Era University, Lucknow, Uttar Pradesh |

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In accordance with the guidelines under the Government Order dated February 06, 2008, twenty seven private Universities have been established and incorporated by different State Acts. Since different Acts of different Universities contains different provisions and there is no uniform provision for monitoring of such Private Universities, it has become difficult to implement and enforce the policies of the State Government, to collect information and records and to implement the standards of quality in higher education.

It has, therefore, been decided to make an umbrella Act to govern all the Private Universities under a common law.

The Uttar Pradesh Private Universities Bill, 2019 is introduced accordingly.

By order,
J.P. SINGH-II,
*Pramukh Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 191 राजपत्र–(हिन्दी)–2019–(565)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 68 सा0 विधायी–2019–(566)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

क्रम-संख्या–145

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

### भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, मंगलवार, 24 अगस्त, 2021**

**भाद्रपद 2, 1943 शक सम्वत्**

उत्तर प्रदेश शासन

**विधायी अनुभाग–1**

संख्या 790/79-वि-1–21-1-क-17-21
लखनऊ, 24 अगस्त, 2021

अधिसूचना

**विविध**

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2021 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 24 अगस्त, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2021)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 12 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019, (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की अनुसूची 2, में क्रम संख्या 27 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भों को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा और क्रम संख्या 27 के पश्चात् नवस्थापित विश्वविद्यालयों के लिये निम्नलिखित क्रम संख्याएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात:—

| क्र0 सं0 | विश्वविद्यालय का नाम | प्रायोजक निकाय का नाम |
|---|---|---|
| 28 | यूनाईटेड विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश | शिवराम दास गुलाटी मेमोरियल ट्रस्ट, प्रयागराज |
| 29 | एफ0एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश | फूलन सिंह जन कल्यान ट्रस्ट, सीतानगर, नगलाभाऊ, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश |
| 30 | महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, उत्तर प्रदेश | गुरू श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय समिति, श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर, गोरखनाथ, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश |

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

3—(1) राज्य सरकार, यूनाईटेड विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, एफ0एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश देती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

4—(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2021

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

---

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने का उपबंध करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

तीन नये निजी विश्वविद्यालयों अर्थात् (एक) यूनाइटेड विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश (दो) एफ.एस. विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश और (तीन) महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की स्थापना का उपबंध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये तुरंत विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 2021 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2021) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 790 (2)/LXXIX-V-1–21-1(ka)-17-21
*Dated Lucknow, August* 24, 2021

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 17 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 24, 2021. The Uccha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

# THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2021

(U.P. Act no. 17 of 2021)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

*to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act,* 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy second Year of the Republic of India as follows:-

Short title and Commencement

1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from April 12, 2021.

Amendment of Schedule 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

2. In Schedule 2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter referred to as the "principal Act") *after* serial no. 27, the Columns of the said Schedule shall be amended as below and after serial no. 27 for the newly established Universities the following serial numbers shall be *inserted,* namely :-

| Sl. no. | Name of the University | Name of the Sponsoring Body |
|---|---|---|
| 28 | United University, Prayagraj, Uttar Pradesh | Shiv Ram Das Gulati Memorial Trust, Prayagraj |
| 29 | F.S. University, Shikohabad, Firozabad, Uttar Pradesh | Fulan Singh Jankalyan Trust, Sita Nagar, Nagla Bhau, Firozabad, Uttar Pradesh |
| 30 | Mahayogi Gorakhnath University Gorakhpur, Uttar Pradesh | Guru Shri Gorakshnath Chikaitsalay Samiti, Shri Gorakhnath Mandir Parisar, Gorakhnath, Gorakhpur, Uttar Pradesh |

Power to remove difficulties

3. (1) The State Government may for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of United University Prayagraj, Uttar Pradesh, F.S University Shikohabad, Firozabad, Uttar Pradesh and Mahayogi Gorakhnath University Gorakhpur, Uttar Pradesh by order published in the *Gazette* direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of State Legislature as soon as may be after it is made.

Repeal and saving

4. (1) The Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Ordinance, 2021 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 4 of 2021

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing private universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education in the State of Uttar Pradesh and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to provide for the establishment of three new private Universities, namely :–

(i) United University Prayagraj, Uttar Pradesh; (ii) F.S. University Shikohabad, Firozabad, Uttar Pradesh; and (iii) Mahayogi Gorakhnath University Gorakhpur, Uttar Pradesh, it was decided to amend Schedule 2 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Ordinance, 2021 (U.P. Ordinance no. 4 of 2021) was promulgated by the Governor on April 12, 2021.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
*Pramukh Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 254 राजपत्र–2021–(574)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 70 सा0 विधायी–2021–(575)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

254_RPH_vidhaika -21 Adhiniyam folder _(privete univercities )-2021 Data-4E

क्रम-संख्या–146

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

**भाग–1, खण्ड (क)**

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, मंगलवार, 24 अगस्त, 2021**

**भाद्रपद 2, 1943 शक सम्वत्**

उत्तर प्रदेश शासन

**विधायी अनुभाग–1**

संख्या 795/79-वि-1–21-1-क-27-21
लखनऊ, 24 अगस्त, 2021

अधिसूचना

**विविध**

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन), विधेयक, 2021 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 24 अगस्त, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2021

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2021)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1– यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) संक्षिप्त नाम अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में, धारा 2 में, –

(क) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"(गक) 'महाविद्यालय' का तात्पर्य राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय से 'सम्बद्ध' अथवा 'सहयुक्त' महाविद्यालय से है;"

(गख) 'परिषद्' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1995) के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् से है;"

(ख) खण्ड (न) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

(नक) "परिसर दूरस्थ केन्द्र" का तात्पर्य निजी विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परिसर के बाहर राज्य के भीतर स्थापित निजी विश्वविद्यालय के किसी केन्द्र से है जो उसके घटक इकाई के रूप में संचालित तथा अनुरक्षित है, जिसमें विश्वविद्यालय की पूरक सुविधाएं, संकाय तथा कर्मचारिवृंद हैं।"

धारा 3 का संशोधन

3–मूल अधिनियम में, धारा 3 के खण्ड (ख) में, प्रथम परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"**स्पष्टीकरण** : प्रायोजक निकाय द्वारा स्थापित किसी महाविद्यालय अथवा शैक्षिक संस्था के नाम की भूमि भी इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयोजनार्थ प्रायोजक निकाय द्वारा सम्यक रूप से धारित की गयी मानी जायेगी।"

नयी धारा 7(क) का बढ़ाया जाना

4–मूल अधिनियम में, धारा 7 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"7(क) कोई निजी विश्वविद्यालय ऐकिक विश्वविद्यालय होगा, जिसमें अध्यापन, अनुसंधान, परीक्षा और विस्तार सेवाओं के लिए पर्याप्त सुविधाएं होंगी तथापि आपवादिक परिस्थितियों में अपना मुख्य परिसर विकसित करने के पश्चात् और अपने अस्तित्व में आने के पाँच वर्ष के पश्चात् विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन परिसर दूरस्थ केन्द्र खोलने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है :–

(क) 'परिसर दूरस्थ केन्द्र' उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन से स्थापित किये जायेंगे। प्रायोजक निकाय, उच्च शैक्षिक संस्थान या राज्य में 'परिसर दूरस्थ केन्द्र' के लिये केन्द्र/राज्य सरकार अथवा केन्द्र/राज्य विनियामक निकायों द्वारा भूमि और अन्य अवसंरचनात्मक तथा शैक्षणिक सुविधाओं के प्रतिमानों के सम्यक् अनुरूप होगा।

(ख) परिसर दूरस्थ केन्द्र (केन्द्रों) के समग्र कार्य निष्पादन का वार्षिक अनुश्रवण, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा किया जायेगा। प्रबन्धन, शैक्षणिक विकास तथा समुन्नति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा उत्तर प्रदेश शासन के मार्गदर्शी सिद्धान्त बाध्यकारी होंगे।

(ग) उक्त केन्द्र/संस्थान निजी विश्वविद्यालय के घटक इकाई होंगे। तथापि निजी विश्वविद्यालय के पास उन्हें सम्बद्ध करने का अधिकार नहीं होगा।

(घ) यदि उक्त केन्द्र (केन्द्रों) की कार्यप्रणाली असंतोषजनक रहती है तो निजी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या राज्य सरकार द्वारा उक्त केन्द्र (केन्द्रों) को बन्द करने के लिये अनुदेश दिया जायेगा, जो विश्वविद्यालय के लिये बाध्यकारी होगा। ऐसी स्थिति में उसमें पहले से नामांकित छात्रों के हितों का संरक्षण किया जायेगा।

धारा 34 का संशोधन

5—मूल अधिनियम में, धारा 34 की उपधारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

(1) इस अधिनियम के अधीन स्थापित अथवा निगमित विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावली, कार्यपरिषद् द्वारा बनायी और अनुमोदित की जायेगी।

(2) यथोक्त प्रथम परिनियमावली, विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के छः माह के भीतर सूचनार्थ राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

6—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा बनाये गये उपबंधों के सम्बन्ध में, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबंध आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कृत प्रत्येक आदेश, उसके दिये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

---

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने तथा उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया था।

2—नयी शिक्षा नीति, 2020 में सकल नामांकन दर में वृद्धि करते हुये तथा उच्च शैक्षिक संस्थाओं के निमित्त संस्थागत स्वायत्तता का उपबंध करते हुये प्रत्येक जिला में या उसके निकट कम से कम एक उच्च शैक्षिक संस्था की स्थापना किया जाना सम्मिलित है। पूर्वोक्त नीति को क्रियान्वित करने और निजी विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की अभिवृद्धि करने के प्रयोजनार्थ निजी क्षेत्र में पाँच वर्षों के लिये स्थापित विश्वविद्यालयों का दक्ष संचालन पूरा करने के पश्चात् यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं के भीतर 'दूरस्थ परिसर केन्द्र' स्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिये उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाय।

3—निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रस्तावों का परीक्षण करने के पश्चात् यह पाया गया कि निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कतिपय प्रायोजक निकाय द्वारा प्रस्तावित राजस्व अभिलेखों का उल्लेख पहले से प्रायोजक निकाय द्वारा संचालित महाविद्यालयों के नाम से है। इस प्रकार यह स्पष्ट करने की आवश्यकता महसूस की गई कि महाविद्यालय या शैक्षिक संस्था के नाम की भूमि भी प्रायोजक निकाय द्वारा सम्यक् रूप से धारित की गई समझी जायेगी।

4—विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली राज्य सरकार के अनुमोदन से बनायी जाती है। राज्य सरकार द्वारा तीन माह के अन्तर्गत अनुमोदन न किये जाने की स्थिति में प्रथम परिनियमावली राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की गई समझी जायेगी। निजी विश्वविद्यालयों को पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान करने की दृष्टि से और उक्त अनुमोदन की प्रक्रिया में विलंब का निराकरण करने के उद्देश्य से प्रथम परिनियमावली बनाने की शक्ति कार्यपरिषद् में निहित करने का विनिश्चय किया गया है।

5—उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये पूर्वोक्त अधिनियम की सुसंगत धाराओं में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

6—तद्नुसार उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 795 (2)/LXXIX-V-1–21-1-ka-27-21
*Dated Lucknow, August* 24, 2021

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 24, 2021. The Uccha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

# THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 2021

(U.P. Act no. 18 of 2021)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act,* 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy second Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Second Amendment) Act, 2021.

Amendment of section 2 of U.P. Act No. 12 of 2019

2. In the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019, hereinafter referred to as the principal Act, in section 2,-

(a) after clause (c), the following clauses shall be *inserted*, namely :-

"(ca) 'College' means a college 'affiliated' or 'associated' to a University established under a State Act ;

(cb) 'Council' means the Uttar Pradesh State Council Of Higher Education established under the Uttar Pradesh State Council Of Higher Education Act, 1995 (U.P. Act no. 22 of 1995) ;"

(b) *after* clause (t), the following clause shall be *inserted*, namely :-

"(ta) 'Off-campus centre' means a centre of the private University established by it outside the main campus within the State operated and maintained as its constituent unit, having the University's compliment of facilities, faculty and staff. "

Amendment of section 3

3. In the principal Act, in clause (b) of section 3, before the first proviso the following explanation shall be *inserted*, namely:-

"*Explanation* :– The land in the name of a college or educational institution established by the sponsoring body shall also be deemed to be duly possessed by a sponsoring body for the purpose of establishing a University under this Act. "

Insertion of a new section 7(A)

4. In the principal Act, after section 7, the following section shall be inserted, namely:-

"7 (A) A private University shall be a unitary University having adequate facilities for teaching, research, examination and extension services. However, after the development of its main campus and after five years of its coming into the existence in exceptional circumstances, the University may be permitted to open off-campus centers, subject to the following conditions :-

(a) the off-campus centre(s) shall be set up with the prior approval of the Government of Uttar Pradesh and the UGC. The Sponsoring Body shall duly conform to the norms of the land and other infrastructural and academic facilities as determined by the Central/State Government or Central/State Regulatory Bodies for a higher education institute or off-campus centre in the State;

(b) the over-all performance of the off-campus centre(s) shall be monitored annually by the UGC and the Higher Education Council under the provisions of this Act. The directions of the UGC and the Government of Uttar Pradesh for management, academic development and improvement shall be binding ;

(c) the said centre(s)/institute(s) shall be the constituent unit(s) of the private University. However the private University shall not have the right to grant them affiliation;

(d) if the functioning of the said centre(s) remains unsatisfactory, the private University shall be instructed by the UGC or State Government to close down the said centre(s), which shall be binding upon the University. In such a situation, the interest of the students already enrolled therein shall be protected under the provisions of this Act. "

Amendment of section 34

5. In the principal Act, *for* sub-sections (1) and (2) of section 34 ,the following sub-sections shall be *substituted* ,namely:-

"(1) The first Statutes of the Universities established or incorporated under this Act shall be made and approved by the Executive Council.

(2) The first Statutes as above shall be submitted to the State Government for information within six months of establishment of a University. "

Power to remove difficulties

6. (1) The State Government may for the purposes of removing any difficulty in relation to the provisions made by this Act, by order published in the *Gazette*, direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of State Legislature as soon as may be after it is made.

---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) was enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing private universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education in the State of Uttar Pradesh and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

2. The New Education Policy, 2020 includes the establishment of at least one higher educational institution in or near each district, increasing the gross enrollment rate and providing institutional autonomy to higher educational institutions. For the purpose of implementing the aforesaid Policy and enhancement of quality higher education in private universities, after completing the efficient operation of the universities established in the private sector for five years, it has been decided to amend the aforesaid Act to grant permission for setting up of 'off-campus centers' within the limits of Uttar Pradesh.

3. After examining the proposals for the establishment of universities in the private sector, it was found that the land revenue records proposed by some sponsoring body for the establishment of universities in the private sector are mentioned in the names of the colleges already run by the sponsoring body. Thus, a need was felt to explain that the land in the name of the college or educational institution shall also be deemed to be duly possessed by the sponsoring body.

4. The first Statutes of the universities are made with the approval of the State Government. In case of non-approval by the State Government within three months, the first Statutes are deemed approved by the State Government. With a view to give adequate autonomy to private universities an order to eliminate the delay in the process of said approval, it has been decided to vest in the Executive Council the power to make the first Statutes.

5. In view of the above, it has been decided to amend the relevant sections of the aforesaid Act.

6. The Uttar Pradesh Private Universities (Second Amendment) Bill, 2021 is introduced accordingly.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
*Pramukh Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 255 राजपत्र–2021–(576)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 71 सा0 विधायी–2021–(577)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

255_RPH_vidhaika -21 Adhiniyam folder _(privete univercities )-2021_Data-4E

क्रम-संख्या–101

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

**भाग–1, खण्ड (क)**

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, शुक्रवार, 3 जून, 2022**

**ज्येष्ठ 13, 1944 शक सम्वत्**

उत्तर प्रदेश शासन

**विधायी अनुभाग–1**

संख्या 299 / 79-वि-1–2022-1-क-5-2022

लखनऊ, 3 जून, 2022

अधिसूचना

**विविध**

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2022 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 3 जून, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2022 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2022)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की अनुसूची 2 में, क्रम संख्या 29 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भों को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा और क्रम संख्या 29 के पश्चात् नव स्थापित विश्वविद्यालय के लिये निम्नलिखित क्रम संख्यायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :—

| क्र0 सं0 | विश्वविद्यालय का नाम | प्रायोजक निकाय का नाम |
|---|---|---|
| 30 | आई0आई0एल0एम0 विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश | राम कृष्ण एण्ड संस चैरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली |

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

3—(1) राज्य सरकार, आई0 आई0 एल0 एम0 विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश देती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा;

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

———

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने तथा विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने एवं उनके कृत्यों को विनियमित करने का उपबन्ध करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों की व्यवस्था करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

ग्रेटर नोएडा में एक नये निजी विश्वविद्यालय अर्थात् आई0 आई0 एल0 एम0 विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश की स्थापना का उपबन्ध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची—2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 299 (2)/LXXIX-V-1–2022-1(ka)-5-2022
*Dated Lucknow, June 3*, 2022

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidyalay (Sanshodhan) Adhiniyam, 2022 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 2022) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on June 3, 2022. The Uccha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

# THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2022

(U.P. Act no. 3 of 2022)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act,* 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy third Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Act, 2022.

Amendment of Schedule 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

2. In Schedule 2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter referred to as the "principal Act") *after* serial no. 29, the Columns of the said Schedule shall be amended as below and after serial no. 29 for the newly established University the following serial numbers shall be *inserted*, namely :–

| Sl. no. | Name of the University | Name of the Sponsoring Body |
|---|---|---|
| 30. | IILM University, Greater Noida, Uttar Pradesh | Ram Krishan and Sons Charitable Trust, New Delhi |

Power to remove difficulties

3. (1) The State Government may for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of IILM University, Greater Noida, Uttar Pradesh, by order published in the *Gazette*, direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient :

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both the Houses of State Legislature as soon as may be after it is made.

---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U. P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing private universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education in the State of Uttar Pradesh and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to provide for the establishment of a new private university at Greater Noida, namely IILM University, Greater Noida, Uttar Pradesh, it has been decided to amend Schedule-2 of the aforesaid Act.

The Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Bill, 2022 is introduced accordingly.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
*Pramukh Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 87 राजपत्र–2022–(220)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 30 सा0 विधायी–2022–(221)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

87_RPH_vidhaika -21 Adhiniyam folder _(privete univercities )-2022 Data-4E

क्रम-संख्या–102

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

**भाग–1, खण्ड (क)**

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, शुक्रवार, 3 जून, 2022**

**ज्येष्ठ 13, 1944 शक सम्वत्**

उत्तर प्रदेश शासन

**विधायी अनुभाग–1**

संख्या 298 / 79-वि-1–2022-1-क-4-2022
लखनऊ, 3 जून, 2022

अधिसूचना

**विविध**

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन), विधेयक, 2022 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 3 जून, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2022 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2022)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 8 जनवरी, 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में संशोधन

2—उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में, क्रम संख्या 15 पर, क्रम संख्या 15 की प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी और उक्त अनुसूचियां तद्नुसार पुनः संख्यांकित की जायेंगी :

परन्तु यह कि उक्त संशोधन यू0जी0सी0 (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) विनियम, 2017 के अधीन पूर्वोक्त अनुसूचियों में क्रम संख्या 15 पर "समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान" के रूप में सूचीबद्ध विश्वविद्यालय की अधिसूचना के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

निरसन और व्यावृत्ति

3—(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2022 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2022

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

———

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा प्रदान करने के निमित्त उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने तथा उनके कृत्यों को विनियमित करने एवं उनसे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों हेतु उपबन्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

तीस निजी विश्वविद्यालय, पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 1 और 2 में सम्मिलित है। यू0जी0सी0 (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) विनियम, 2017 में किसी निजी विश्वविद्यालय को समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्था के रूप में घोषित करने का उपबंध है। उक्त उपबंध के आलोक में राज्य सरकार द्वारा उक्त विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों को हटाकर पूर्वोक्त अनुसूचियों में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया ताकि पूर्वोक्त विश्वविद्यालय को उक्त प्रास्थिति प्रदान किया जा सके।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 8 जनवरी, 2022 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2022) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 298 (2)/LXXIX-V-1–2022-1(ka)-4-2022

*Dated Lucknow, June 3*, 2022

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2022 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 2022) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on June 3, 2022. The Uccha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

# THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 2022

(U.P. Act no. 4 of 2022)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act,* 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy third Year of the Republic of India as follows:-

Short title and Commencement

1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (second Amendment) Act, 2022.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from January 8, 2022.

Amendment of Schedule 1 and Schedule 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

2. At serial no. 15 in Schedule 1 and Schedule 2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019, the entries at serial no. 15, shall be deleted and the said Schedule shall be renumbered accordingly :

Provided that the said amendment shall come into effect from the date of notification of the University Scheduled at serial no. 15 in the aforesaid Schedules as 'Institution of Eminence Deemed to be University' under UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017.

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 4 of 2022

3. (1) The Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Ordinance, 2022 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for establishment of new Private Universities and incorporation of existing private Universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education in the State of Uttar Pradesh and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

Thirty private Universities are included in Schedule 1 and 2 of the aforesaid Act. UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017 provides for a private Universities to be declared as institution of eminence deemed to be Universities. In the light of the aforesaid provision, it was decided by the State Government to amend the aforesaid Schedules by deleting the entries related to the said University so that the aforesaid status can be conferred on the aforesaid University .

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Ordinance, 2022 (U.P. Ordinance no. 4 of 2022) was promulgated by the Governor on January 08, 2022.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
*Pramukh Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 88 राजपत्र–2022–(222)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 31 सा0 विधायी–2022–(223)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

88_RPH_vidhaika -21 Adhiniyam folder _(privete univercities )-2022 Data-4E

क्रम-संख्या–144(क–3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

**भाग–1, खण्ड (क)**

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, सोमवार, 21 अगस्त, 2023**

**श्रावण 30, 1945 शक सम्वत्**

उत्तर प्रदेश शासन

**विधायी अनुभाग–1**

संख्या 423/79-वि-1–2023-1-(क)-8-2023

लखनऊ, 21 अगस्त, 2023

अधिसूचना

**विविध**

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2023 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 17 अगस्त, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2023 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2023)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 27 जून, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की अनुसूची–2 में क्रम संख्या 30 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भों को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा और क्रम संख्या 30 के पश्चात् नव स्थापित विश्वविद्यालय के लिये निम्नलिखित क्रम संख्यायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

| क्र० सं० | विश्वविद्यालय का नाम | प्रायोजक निकाय का नाम |
|---|---|---|
| 31 | अग्रवन हेरीटेज विश्वविद्यालय, आगरा, उत्तर प्रदेश | श्री जगदीश जन कल्याण एजूकेशनल ट्रस्ट, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश |
| 32 | महावीर विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश | न्यू ट्यूप्लस एजूकेशनल सोसाइटी, मेरठ, उत्तर |
| 33 | एस०डी०जी०आई० ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश | सुन्दर दीप एजूकेशनल सोसाइटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश |

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

3–(1) राज्य सरकार अग्रवन हेरीटेज विश्वविद्यालय, आगरा, उत्तर प्रदेश अथवा महावीर विश्वविद्यालय, मेरठ उत्तर प्रदेश अथवा एस०डी०जी०आई० ग्लोबल, विश्वविद्यालय, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश देती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा;

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

4–(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2023 उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 तथा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2023, 7 सन् 2023 तथा 8 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

## उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने एवं उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 ) अधिनियमित किया गया है।

तीन नये निजी विश्वविद्यालयों, अर्थात (एक) अग्रवन हेरीटेज विश्वविद्यालय, आगरा, उत्तर प्रदेश (दो) महावीर विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश और (तीन) एस०डी०जी०आई० ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की स्थापना का उपबंध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कारवाई आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 जून, 2023 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2023), उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2023) एवं उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2023 ) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 423 (2)/LXXIX-V-1–2023-1(ka)-8-2023
*Dated Lucknow, August* 21, 2023

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 2023) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 17, 2023. The Uccha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

# THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2023

(U.P. Act No. 8 of 2023)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act,* 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy Fourth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and Commencement

1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from June 27, 2023.

Amendment of Schedule 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

2. In Schedule 2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter referred to as the "principal Act") *after* serial no. 30, the Columns of the said Schedule shall be amended as below and after serial no. 30 for the newly established Universities the following serial numbers shall be *inserted,* namely :-

| Sl. no. | Name of the University | Name of the Sponsoring Body |
|---|---|---|
| 31 | Agrawan Heritage University, Agra, Uttar Pradesh | Shri Jagdish Jankalyan Educational Trust, Shikohabad, Firozabad, Uttar Pradesh |
| 32 | Mahaveer University, Meerut, Uttar Pradesh | New Tuples Educational Society, Meerut, Uttar Pradesh |
| 33 | SDGI Global University, Ghaziabad, Uttar Pradesh | Sunder Deep Educational Society, Ghaziabad, Uttar Pradesh |

Power to remove difficulties

3. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of Agrawan Heritage University, Agra, Uttar Pradesh or Mahaveer University, Meerut, Uttar Pradesh or SDGI Global University, Ghaziabad, Uttar Pradesh by order published in the *Gazette* direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of State Legislature as soon as may be after it is made.

Repeal and Saving

U.P. Ordinance no. 6 of 2023, 7 of 2023 and 8 of 2023

4. (1) The Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Ordinance, 2023, The Uttar Pradesh Private Universities (Second Amendment) Ordinance, 2023 and the Uttar Pradesh Private Universities (Third Amendment) Ordinance, 2023 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing Private Universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to Provide for the establishment of three new Private Universities namely:- (i) Agrawan Heritage University, Agra, Uttar Pradesh ; (ii) Mahaveer University, Meerut, Uttar Pradesh; and (iii) SDGI Global University, Ghaziabad, Uttar Pradesh it was decided to amend Schedule-2 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 6 of 2023), the Uttar Pradesh Private Universities (Second Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 7 of 2023) and the Uttar Pradesh Private Universities (Third Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 8 of 2023) were promulgated by the Governor on June 27, 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
*Pramukh Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 512 राजपत्र–2023–(1645)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 81 सा0 विधायी–2023–(1646)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

512_RPH_ Adhiniyam folder _(privete univercities )-2023 Data-7E

क्रम-संख्या–144(क–2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

**भाग–1, खण्ड (क)**

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, सोमवार, 21 अगस्त, 2023**

**श्रावण 30, 1945 शक सम्वत्**

उत्तर प्रदेश शासन

**विधायी अनुभाग–1**

संख्या 424/79-वि-1–2023-1-(क)-9-2023
लखनऊ, 21 अगस्त, 2023

अधिसूचना

**विविध**

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन), विधेयक, 2023 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 17 अगस्त, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2023 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2023)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 28 जून, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की अनुसूची 2 में क्रम संख्या 33 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भों को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा और क्रम संख्या 33 के पश्चात् नव स्थापित विश्वविद्यालय के लिये निम्नलिखित क्रम संख्या बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

| क्रम संख्या | विश्वविद्यालय का नाम | प्रायोजक निकाय का नाम |
|---|---|---|
| 34 | के0 एम0 (कृष्ण मोहन) विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश | श्री मोहन सिंह शिक्षा संस्थान, पॉली डूंगरा, सौंख, मथुरा, उत्तर प्रदेश |
| 35 | मेजर एस0डी0 सिंह विश्वविद्यालय, फतेहगढ़ फर्रूखाबाद, उत्तर प्रदेश | श्री बाबू सिंह दद्दू जी एजूकेशनल ट्रस्ट, सिविल लाइन्स, फतेहगढ़, फर्रूखाबाद, उत्तर प्रदेश |

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

3–(1) राज्य सरकार के० एम० (कृष्ण मोहन) विश्वविद्यालय, मथुरा उत्तर प्रदेश अथवा मेजर एस० डी० सिंह विश्वविद्यालय, फतेहगढ़ फर्रूखाबाद, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा;

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

4–(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2023 तथा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( पांचवा संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2023, तथा 10 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे ।

## उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने एवं उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 ) अधिनियमित किया गया है।

दो नये निजी विश्वविद्यालयों, अर्थात (एक) के०एम० (कृष्ण मोहन ) विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश और (दो) मेजर एस० डी० सिंह विश्वविद्यालय, फतेहगढ़ फर्रूखाबाद, उत्तर प्रदेश की स्थापना का उपबंध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाई आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 28 जून, 2023 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2023) तथा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पांचवा संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 424 (2)/LXXIX-V-1–2023-1(ka)-9-2023
*Dated Lucknow, August* 21, 2023

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2023 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 2023) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 17, 2023. The Uccha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

# THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 2023

(U.P. Act No. 9 of 2023)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act,* 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy Fourth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and Commencement

1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Second Amendment) Act, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from June 28, 2023.

Amendment of Schedule 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

2. In Schedule 2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter referred to as the "principal Act") *after* serial no. 33, the Columns of the said Schedule shall be amended as below and after serial no. 33 for the newly established Universities the following serial numbers shall be *inserted,* namely :-

| Sl. no. | Name of the University | Name of the Sponsoring Body |
|---|---|---|
| 34 | K.M. (Krishna Mohan) University Mathura, Uttar Pradesh | Shri Mohan Singh Shiksha Sansthan, Pali Dungra, Saunkh, Mathura, Uttar Pradesh |
| 35 | Major S.D. Singh University, Fatehgarh, Farrukhabad, Uttar Pradesh | Shri Babu Singh Daddu Ji Educational Trust, Civil Lines Fatehgarh, Farrukhabad, Uttar Pradesh |

Power to remove difficulties

3. (1) The State Government may for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of K.M. (Krishna Mohan) University Mathura, Uttar Pradesh or Major S.D. Singh University, Fatehgarh, Farrukhabad, Uttar Pradesh by order published in the *Gazette* direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of State Legislature, as soon as may be, after it is made.

Repeal and saving

U.P.Ordinance no. 9 of 2023, and 10 of 2023

4.(1) The Uttar Pradesh Private Universities (Fourth Amendment) Ordinance, 2023 and The Uttar Pradesh Private Universities (Fifth Amendment) Ordinance, 2023 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing Private Universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to provide for the establishment of two new Private Universities namely:- (i) K.M. (Krishna Mohan) University, Mathura, Uttar Pradesh; and (ii) Major S. D. Singh University, Fatehgarh, Farrukhabad, Uttar Pradesh it was decided to amend Schedule-2 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Private Universities (Fourth Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 9 of 2023) and the Uttar Pradesh Private Universities (Fifth Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 10 of 2023) were promulgated by the Governor on June 28, 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
*Pramukh Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 511 राजपत्र–2023–(1643)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 80 सा0 विधायी–2023–(1644)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

511_RPH_ Adhiniyam folder _(privete univercities )-2023 Data-7E

क्रम-संख्या–144(क–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

**भाग–1, खण्ड (क)**

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, सोमवार, 21 अगस्त, 2023**

**श्रावण 30, 1945 शक सम्वत्**

उत्तर प्रदेश शासन

**विधायी अनुभाग–1**

संख्या 412/79-वि-1–2023-1-क-16-2023

लखनऊ, 21 अगस्त, 2023

अधिसूचना

**विविध**

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन), विधेयक, 2023 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 18 अगस्त, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2023 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2023

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2023)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की अनुसूची 2 में, क्रम संख्या 35 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भों को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा और क्रम संख्या 35 के पश्चात् नव स्थापित विश्वविद्यालयों के लिये निम्नलिखित क्रम संख्या एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात :—

| क्रम संख्या | विश्वविद्यालय का नाम | प्रायोजक निकाय का नाम |
|---|---|---|
| 36 | टी0 एस0 मिश्रा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश | वेदिक एण्ड फ्यूचरिस्टिक एजूटेक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश |

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

3—(1) राज्य सरकार, टी0 एस0 मिश्रा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा ;

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

---

## उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों के निगमन तथा उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

लखनऊ में एक नये निजी विश्वविद्यालय अर्थात् टी0 एस0 मिश्रा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की स्थापना का उपबंध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2023 पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 412 (2)/LXXIX-V-1–2023-1-ka-16-2023
*Dated Lucknow, August* 21, 2023

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidyalay (Tritiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2023 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 2023) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 17, 2023. The Uccha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

# THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (THIRD AMENDMENT) ACT, 2023

(U.P. Act no. 10 of 2023)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act,* 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Third Amendment) Act, 2023.

Amendment of Schedule 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

2. In Schedule-2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter referred to as the "Principal Act") *after* serial no. 35, the Columns of the said Schedule shall be amended as below and *after* serial no. 35 for the newly established Universities the following serial number and entries relating thereto shall column wise be *inserted*, namely:—

| S. No. | Name of the University | Name of the Sponsoring Body |
|---|---|---|
| 36 | T.S. Mishra University, Lucknow, Uttar Pradesh | Vedic and Futuristic Edutech, Lucknow, Uttar Pradesh |

Power to remove difficulties

3. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of T.S. Mishra University, Lucknow, Uttar Pradesh ,by order published in the *Gazette* direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both the Houses of State Legislature as soon as may be after it is made.

---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing Private Universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to provide for the establishment of a new Private University at Lucknow namely T.S. Mishra University, Lucknow, Uttar Pradesh, it has been decided to amend Schedule-2 of the aforesaid Act.

The Uttar Pradesh Private Universities (Third Amendment) Bill, 2023 is introduced accordingly.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
*Pramukh Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 510 राजपत्र–2023–(1641)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 79 सा0 विधायी–2023–(1642)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

510_RPH_vidhaika -23 Adhiniyam folder _(privete univercities )-2022 Data-4E

क्रम-संख्या–207

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

### भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, शुक्रवार, 8 दिसम्बर, 2023**
**अग्रहायण 17, 1945 शक सम्वत्**

**उत्तर प्रदेश शासन**
**विधायी अनुभाग–1**

संख्या 597/79-वि-1–2023-1-क-19-2023
लखनऊ, 8 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

**विविध**

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2023 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 7 दिसम्बर, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2023 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2023

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2023)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की अनुसूची 2 में, क्रम संख्या 36 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भों को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा और क्रम संख्या 36 के पश्चात् नवस्थापित विश्वविद्यालयों के लिये निम्नलिखित क्रम संख्या बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :—

| क्रम संख्या | विश्वविद्यालय का नाम | प्रायोजक निकाय का नाम |
|---|---|---|
| 37 | वरूण अर्जुन विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश। | वरूणार्जुन ट्रस्ट, केशलता हास्पिटल, डेलापार, बरेली, उत्तर प्रदेश। |

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

3—(1) राज्य सरकार, वरूण अर्जुन विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगेः

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

4—(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठवां संषोधन) अध्यादेष, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेष अध्यादेष संख्या 17 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेष द्वारा यथा संषोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संषोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

———————

## उद्देष्य और कारण

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेष राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने एवं उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

एक नया निजी विश्वविद्यालय अर्थात वरूण अर्जुन विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश की स्थापना का उपबंध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठवां संषोधन) अध्यादेष, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेष को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 597(2)/LXXIX-V-1–2023-1-ka-19-2023

*Dated Lucknow, December* 8, 2023

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidhyalay (Chaturth Sanshodhan) Adhiniyam, 2023 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 2023) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 7, 2023. The Uccha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

# THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (FOURTH AMENDMENT) ACT, 2023

(U.P. Act no. 20 of 2023)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.*

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Fourth Amendment) Act, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 20th October, 2023.

Amendment of schedule 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

2. In Schedule-2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter referred to as the "principal Act") *after* serial no. 36, the Columns of the said Schedule shall be amended as below and *after* serial no. 36 for the newly established Universities the following serial numbers shall be *inserted*, namely :-

| Sl. no. | Name of the University | Name of the Sponsoring Body |
|---|---|---|
| **37** | Varun Arjun University, Shahjahanpur, Uttar Pradesh | Varunarjun Trust, Keshlata Hospital, Delaper, Bareilly, Uttar Pradesh |

Power to remove difficulties

3. (1) The State Government may for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of Varun Arjun University, Shahjahanpur, Uttar Pradesh by order published in the *Gazette* direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature, as soon as may be, after it is made.

Repeal and Saving

U.P. Ordinance no. 17 of 2023

4. (1) The Uttar Pradesh Private Universities (Sixth Amendment) Ordinance, 2023 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U. P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing private universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to provide for the establishment of a new private university namely Varun Arjun University, Shahjahanpur, Uttar Pradesh, it was decided to amend Schedule-2 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Private Universities (Sixth Amendment) Ordinance, 2023 (U. P. Ordinance no. 17 of 2023) was promulgated by the Governor on October 20, 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
*Pramukh Sachiv*.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 793 राजपत्र–2023–(2268)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 144 सा0 विधायी–2023–(2269)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

क्रम-संख्या–24

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

**भाग–1, खण्ड (क)**

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, सोमवार, 26 फरवरी, 2024**

**फाल्गुन 7, 1945 शक सम्वत्**

**उत्तर प्रदेश शासन**

**विधायी अनुभाग–1**

संख्या 66/79-वि-1–2024-1-क-2-2024

लखनऊ, 26 फरवरी, 2024

अधिसूचना

**विविध**

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 26 फरवरी, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2024 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 2024

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची–2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की अनुसूची-2 में, क्रम संख्या 37 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भों को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा और क्रम–संख्या 37 के पश्चात् नवस्थापित विश्वविद्यालयों के लिये निम्नलिखित क्रम–संख्या बढ़ा दी जायेगी:–

| क्रम–संख्या | विश्वविद्यालय का नाम | प्रायोजक निकाय का नाम |
|---|---|---|
| 38 | एस0 के0 एस0 इंटरनेशनल विश्वविद्यालय मथुरा, उत्तर प्रदेश | बृजवासी एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, मथुरा, उत्तर प्रदेश |

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

3–(1) राज्य सरकार, एस0के0एस0 इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा;

(2) उप धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

4–(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवां संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

---

## उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने एवं उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

एक नया निजी विश्वविद्यालय अर्थात् एस0के0एस0 इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु उपबंध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरंत विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवां संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 66(2)/LXXIX-V-1–2024-1-ka-2-2024

*Dated Lucknow, February* 26, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidyalay (Sanshodhan) Adhiniyam, 2024 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 2024) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 26, 2024. The Uccha Shiksha Anubhag- 1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) Act, 2024

(U.P. Act No. 1 Of 2024)

*(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)*

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.*

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from December 31, 2023.

Amendment of Schedule 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

2. In Schedule-2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter referred to as the "principal Act") *after* serial no. 37, the Columns of the said Schedule shall be amended as below and after serial no. 37 for the newly established Universities the following serial number shall be *inserted*:—

| Sl. no. | Name of the University | Name of the Sponsoring Body |
|---|---|---|
| 38. | S.K.S. International University, Mathura, Uttar Pradesh | Brijbasi Education and Welfare Society, Mathura, Uttar Pradesh |

Power to remove difficulties

3. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of S.K.S. International University, Mathura, Uttar Pradesh, by order published in the *Gazette* direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature as soon as may be after it is made.

U.P. Ordinance no. 20 of 2023

Repeal and saving

4. (1) The Uttar Pradesh Private Universities (Seventh Amendment) Ordinance, 2023 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing Private Universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to provide for the establishment of a new private University namely, S.K.S. International University, Mathura, Uttar Pradesh, it was decided to amend Schedule 2 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Private Universities (Seventh Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 20 of 2023) was promulgated by the Governor on December 31, 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
*Pramukh Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 1137 राजपत्र—2024—(3155)—599 प्रतियां—(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 172 सा0 विधायी—2024—(3156)—300 प्रतियां—(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

क्रम-संख्या–136

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

### भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, मंगलवार, 13 अगस्त, 2024**

**श्रावण 22, 1946 शक सम्वत्**

**उत्तर प्रदेश शासन**

**विधायी अनुभाग–1**

———————

संख्या 341 / 79-वि-1–2024-1-क-6-2024
लखनऊ, 13 अगस्त, 2024

———————

अधिसूचना

**विविध**

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 12 अगस्त, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2024 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2024

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2024)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

### अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 6 मार्च, 2024 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की अनुसूची 2 में, क्रम संख्या 38 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भ निम्नानुसार

संशोधित किये जायेंगे और नव स्थापित विश्वविद्यालयों के लिये क्रम संख्या 38 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

| क्रम संख्या | विश्वविद्यालय का नाम | प्रायोजक संस्था का नाम |
|---|---|---|
| 39 | "शारदा विश्वविद्यालय आगरा" आगरा, उत्तर प्रदेश | श्री आनन्द स्वरूप एजुकेशनल ट्रस्ट, आगरा, उत्तर प्रदेश |
| 40 | सरोज इंटरनेशनल विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश | श्रीमती सरोज सिंह, शिक्षण संस्थान, 8 माल एवेन्यू, लखनऊ, उत्तर प्रदेश |
| 41 | जे0एस0एस0 विश्वविद्यालय, नोएडा, उत्तर प्रदेश | जे0एस0एस0 महाविद्यापीठ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश |

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

3–(1) राज्य सरकार, "शारदा विश्वविद्यालय आगरा'', आगरा, उत्तर प्रदेश अथवा सरोज इंटरनेशनल विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश अथवा जे0एस0एस0 विश्वविद्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश प्रदान कर सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा ;

(2) उप धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

4–(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2024, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 तथा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2024, 2 सन् 2024, 3 सन्, 2024

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उप–धारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

———

## उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने एवं उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

तीन नये निजी विश्वविद्यालय अर्थात् :– (एक) ''शारदा विश्वविद्यालय आगरा'', आगरा, उत्तर प्रदेश; (दो) सरोज इंटरनेशनल विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश ; तथा (तीन) जे0एस0एस0 विश्वविद्यालय, नोएडा, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु उपबन्ध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 6 मार्च, 2024 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2024), उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2024) तथा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2024) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 341(2)/LXXIX-V-1–2024-1-ka-6-2024

*Dated Lucknow, August* 13, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidyalay (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2024 (Uttar Pradesh Adihiniyam Sankhya 11 of 2024) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 12, 2024. The Uccha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

# THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 2024

(U.P. Act no. 11 of 2024)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act,* 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as followes :–

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Second Amendment) Act, 2024.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 6th day of March, 2024.

Amendment of Schedule 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

2. In Schedule 2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter referred to as the "principal Act") *after* serial no. 38, the Columns of the said Schedule shall be amended as below and *after* serial no. 38 for the newly established Universities the following serial numbers shall be *inserted*, namely :-

| Sl. no. | Name of the University | Name of the Sponsoring Body |
|---|---|---|
| 39 | "Sharda University Agra" Agra, Uttar Pradesh | Sri Anand Swroop Educational Trust, Agra, Uttar Pradesh |
| 40 | Saroj International University, Lucknow, Uttar Pradesh | Smt. Saroj Singh Shikshan Sansthan, 8 Mall Avenue, Lucknow, Uttar Pradesh |
| 41 | JSS University, Noida, Uttar Pradesh | JSS Mahavidyapeetha, Ghaziabad, Uttar Pradesh |

Power to remove difficulties

3. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of "Sharda University Agra" Agra, Uttar Pradesh, or Saroj International University, Lucknow, Uttar Pradesh or JSS University, Noida, Uttar Pradesh by order published in the *Gazette*, direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature, as soon as may be, after it is made.

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 1 of 2024, 2 of 2024, 3 of 2024

4. (1) The Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Ordinance, 2024, the Uttar Pradesh Private Universities (Second Amendment) Ordinance, 2024 and the Uttar Pradesh Private Universities (Third Amendment) Ordinance, 2024 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing Private Universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to provide for the establishment of three new Private Universities, namely :– (i) "Sharda University Agra", Agra, Uttar Pradesh; (ii) Saroj International University, Lucknow, Uttar Pradesh; and (iii) JSS University, Noida, Uttar Pradesh, it was decided to amend Schedule 2 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision,the Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no. 1 of 2024), the Uttar Pradesh Private Universities (Second Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no. 2 of 2024) and the Uttar Pradesh Private Universities (Third Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no. 3 of 2024) were promulgated by the Governor on March 6, 2024.

This Bill is introduced to replaced the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
*Pramukh Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 199 राजपत्र–2024–(560)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 79 सा0 विधायी–2024–(561)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

199 RPH Adhiniyam folder –niji univer. (vidhaika- 2021)-data 8

क्रम-संख्या–137

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

### भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, मंगलवार, 13 अगस्त, 2024**

**श्रावण 22, 1946 शक सम्वत्**

### उत्तर प्रदेश शासन

**विधायी अनुभाग–1**

———————

संख्या 342 / 79-वि-1–2024-1-क-13-2024

लखनऊ, 13 अगस्त, 2024

———————

अधिसूचना

**विविध**

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन, विधेयक, 2024 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 12 अगस्त, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2024 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2024

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2024)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 02 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की अनुसूची 2 में, क्रम संख्या 41 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भ निम्नानुसार संशोधित किये जायेंगे और नव स्थापित विश्वविद्यालयों के लिये क्रम संख्या 41 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम.संख्या और उससे सम्बंधित प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

| क्रम-संख्या | विश्वविद्यालय का नाम | प्रायोजक निकाय का नाम |
|---|---|---|
| 42 | फ्यूचर विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश। | श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश |

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

3–(1) राज्य सरकार, फ्यूचर विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश प्रदान कर सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

4–(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2024 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2024

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उप–धारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

---

## उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने एवं उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

एक नया निजी विश्वविद्यालय अर्थात् फ्यूचर विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु उपबंध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरंत विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 02 जुलाई, 2024 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2024) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 342(2)/LXXIX-V-1–2024-1-ka-13-2024

*Dated Lucknow, August* 13, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidyalay (Tritiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2024 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 2024) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 12, 2024. The Uccha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

# THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (THIRD AMENDMENT ) ACT, 2024

(U.P. ACT No. 12 Of 2024)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.*

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Third Amendment ) Act , 2024 .

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 2nd day of July, 2024.

Amendment of Schedule 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

2. In Schedule 2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter referred to as the "principal Act") *after* serial no. 41, the Columns of the said Schedule shall be amended as below and after serial no. 41 for the newly established Universities, the following serial number and entries relating thereto shall be *inserted*, namely :—

| Sl. no. | Name of the University | Name of the Sponsoring Body |
|---|---|---|
| 42. | Future University, Bareilly, Uttar Pradesh | Shree Rajendra Kumar Gupta Memorial Trust, Bareilly, Uttar Pradesh |

Power to remove difficulties

3. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of Future University, Bareilly, Uttar Pradesh, by order published in the *Gazette*, direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature as soon as may be after it is made.

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 9 of 2024

4. (1) The Uttar Pradesh Private Universities (Fourth Amendment) Ordinance, 2024 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing Private Universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to provide for the establishment of a new private University namely, Future University, Bareilly, Uttar Pradesh, it was decided to amend Schedule 2 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Private Universities (Fourth Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no. 9 of 2024) was promulgated by the Governor on July 2, 2024.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

ATUL SRIVASTAVA,

*Pramukh Sachiv*.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 200 राजपत्र–2024–(562)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 80 सा0 विधायी–2024–(563)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

क्रम-संख्या–138

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

**भाग–1, खण्ड (क)**

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, मंगलवार, 13 अगस्त, 2024**

**श्रावण 22, 1946 शक सम्वत्**

**उत्तर प्रदेश शासन**

**विधायी अनुभाग–1**

———————

संख्या 343 / 79-वि-1–2024-1-क-14-2024

लखनऊ, 13 अगस्त, 2024

———————

अधिसूचना

**विविध**

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2024 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 12 अगस्त, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2024 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2024

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2024)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 04 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की अनुसूची 2 में, क्रम संख्या 42 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भ निम्नानुसार संशोधित किये जायेंगे और क्रम संख्या 42 के पश्चात् नव स्थापित विश्वविद्यालयों के लिये निम्नलिखित क्रम संख्या बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

| क्रम संख्या | विश्वविद्यालय का नाम | प्रायोजक निकाय का नाम |
|---|---|---|
| 43 | जी0 एस0 विश्वविद्यालय, हापुड़, उत्तर प्रदेश | श्री जयपाल सिंह शर्मा, ट्रस्ट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश |
| 44 | एच0आर0आई0टी0 विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश | हरीश चन्द्र रामकली चैरिटेबल ट्रस्ट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश |

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

3—(1) राज्य सरकार, "जी0एस0 विश्वविद्यालय, हापुड़" उत्तर प्रदेश या एच0आर0आई0टी0 विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा;

(2) उप धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

4—(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पाँचवां संशोधन) अध्यादेश, 2024 और उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठा संशोधन) अध्यादेश, 2024 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2024, 11 सन् 2024

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

---

## उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने एवं उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

दो नये निजी विश्वविद्यालय अर्थात् (एक) जी0 एस0 विश्वविद्यालय, हापुड़, उत्तर प्रदेश; तथा (दो) एच0आर0आई0टी0 विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु उपबंध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरंत विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 04 जुलाई, 2024 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पाँचवां संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2024) तथा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठा संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2024) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 343(2)/LXXIX-V-1–2024-1-ka-14-2024

*Dated Lucknow, August* 13, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidyalay (Chaturth Sanshodhan) Adhiniyam, 2024 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 2024) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 12, 2024. The Uccha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

# THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (FOURTH AMENDMENT) ACT, 2024

(U.P. ACT No. 13 of 2024)

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.*

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Fourth Amendment) Act, 2024 .

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 4th day of July, 2024.

Amendment of Schedule 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

2. In Schedule 2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter referred to as the "principal Act") *after* serial no. 42, the Columns of the said Schedule shall be amended as below and after serial no. 42 for the newly established Universities the following serial numbers shall be *inserted* namely :—

| Sl. no. | Name of the University | Name of the Sponsoring Body |
|---|---|---|
| 43. | G.S. University, Hapur, Uttar Pradesh | Sri Jaipal Singh Sharma Trust, Ghaziabad, Uttar Pradesh |
| 44. | HRIT University, Ghaziabad, Uttar Pradesh | Harish Chandra Ram Kali Charitable Trust, Ghaziabad, Uttar Pradesh |

Power to remove difficulties

3. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of "G.S. University, Hapur" Uttar Pradesh or the HRIT University, Ghaziabad, Uttar Pradesh, by order published in the *Gazette* direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature as soon as may be after it is made.

Repeal and saving

4. (1) The Uttar Pradesh Private Universities (Fifth Amendment) Ordinance, 2024 and the Uttar Pradesh Private Universities (Sixth Amendment) Ordinance, 2024 are hereby repealed. U.P. Ordinance no. 10 of 2024, 11 of 2024

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing Private Universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to provide for the establishment of two new Private Universities, namely :–(i) G.S. University, Hapur, Uttar Pradesh; and (ii) HRIT University, Ghaziabad, Uttar Pradesh, it was decided to amend Schedule 2 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Private Universities (Fifth Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no. 10 of 2024) and the Uttar Pradesh Private Universities (Sixth Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no. 11 of 2024) were promulgated by the Governor on July 4, 2024.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

ATUL SRIVASTAVA,

*Pramukh Sachiv*.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 201 राजपत्र–2024–(564)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 81 सा0 विधायी–2024–(565)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

क्रम-संख्या–236

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

**भाग–1, खण्ड (क)**

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, बृहस्पतिवार, 26 दिसम्बर, 2024**

**पौष 5, 1946 शक सम्वत्**

**उत्तर प्रदेश शासन**

**विधायी अनुभाग–1**

———————

संख्या 496/79-वि-1–2024-1-क-22-2024

लखनऊ, 26 दिसम्बर, 2024

———————

अधिसूचना

**विविध**

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पाँचवाँ संशोधन) विधेयक, 2024 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2024 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पाँचवाँ संशोधन) अधिनियम, 2024

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2024)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

### अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पाँचवाँ संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 17 सितम्बर, 2024 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की अनुसूची 2 में, क्रम संख्या 44 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भ निम्नानुसार संशोधित किये जायेंगे और नव स्थापित विश्वविद्यालयों के लिये क्रम संख्या 44 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

| क्र0सं0 | विश्वविद्यालय का नाम | प्रायोजक निकाय का नाम |
|---|---|---|
| 45 | चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय, उन्नाव, उत्तर प्रदेश | सी0यू0 इंटरनेशनल एजुकेशनल ट्रस्ट, चण्डीगढ़ |

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

3—(1) राज्य सरकार, चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय, उन्नाव, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश प्रदान कर सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा ;

(2) उप धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

4—(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवाँ संशोधन) अध्यादेश, 2024 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2024)

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

———

## उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने तथा उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

एक नया निजी विश्वविद्यालय अर्थात् चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय, उन्नाव, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु उपबंध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरंत विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 17 सितम्बर, 2024 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवां संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2024) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 496(2)/LXXIX-V-1–2024-1-ka-22-2024

*Dated Lucknow, December* 26, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidyalay (Paachwaan Sanshodhan) Adhiniyam, 2024 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2024) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 26, 2024. The Uccha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

# THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (FIFTH AMENDMENT) ACT, 2024

(U.P. ACT No. 18 OF 2024)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act,* 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Fifth Amendment) Act, 2024.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 17th day of September, 2024.

Amendment of Schedule 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

2. In Schedule 2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter referred to as the "principal Act") *after* serial no. 44, the Columns of the said Schedule shall be amended as below and *after* serial no. 44 for the newly established Universities the following serial number shall be *inserted*, namely:-

| Sl. no. | Name of the University | Name of the Sponsoring Body |
|---|---|---|
| 45 | Chandigarh University, Unnao, Uttar Pradesh | CU International Educational Trust, Chandigarh |

Power to remove difficulties

3. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of Chandigarh University, Unnao, Uttar Pradesh, by order published in the *Gazette* direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature, as soon as may be, after it is made.

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 13 of 2024

4. (1) The Uttar Pradesh Private University (Seventh Amendment) Ordinance, 2024 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing Private Universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to provide for the establishment of a new Private University namely, Chandigarh University, Unnao, Uttar Pradesh, it was decided to amend Schedule 2 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Private Universities (Seventh Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no. 13 of 2024) was promulgated by the Governor on September 17, 2024.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

ATUL SRIVASTAVA,

*Pramukh Sachiv*.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 400 राजपत्र–2024–(1085)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 179 सा0 विधायी–2024–(1086)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

क्रम-संख्या–235

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

### भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, बृहस्पतिवार, 26 दिसम्बर, 2024**

**पौष 5, 1946 शक सम्वत्**

उत्तर प्रदेश शासन

**विधायी अनुभाग–1**

———————

संख्या 500 / 79-वि-1–2024-1-क-25-2024
लखनऊ, 26 दिसम्बर, 2024

———————

अधिसूचना

**विविध**

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठवाँ संशोधन) विधेयक, 2024 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2024 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठवाँ संशोधन) अधिनियम, 2024

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2024)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठवाँ संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की अनुसूची 2 में, क्रम-संख्या 45 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम-संख्या, उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के साथ स्तम्भवार बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

| क्र0सं0 | विश्वविद्यालय का नाम | प्रायोजक निकाय का नाम |
|---|---|---|
| 46 | विद्या विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश | विद्या बाल मण्डली सोसायटी, विद्या नॉलेज पार्क, बागपत रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश |

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

3—(1) राज्य सरकार, ''विद्या विश्वविद्यालय, मेरठ'' उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

4—(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (आठवाँ संशोधन) अध्यादेश, 2024 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 2024

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

———

## उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने तथा उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

एक नया निजी विश्वविद्यालय अर्थात् विद्या विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु उपबंध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (आठवाँ संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 2024) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 500 (2)/LXXIX-V-1–2024-1-ka-25-2024
*Dated Lucknow, December* 26, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidyalay (Chhathwaan Sanshodhan) Adhiniyam, 2024 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 2024) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 26, 2024. The Uchch Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

# THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (SIXTH AMENDMENT) ACT, 2024

(U.P. ACT No. 19 OF 2024)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act,* 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Sixth Amendment) Act, 2024.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 14th day of October, 2024.

Amendment of Schedule 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

2. In Schedule 2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter referred to as the "principal Act") *after* serial no. 45, the following serial number along with the entries relating thereto shall column-wise be *inserted*, namely:-

| Sl. no. | Name of the University | Name of the Sponsoring Body |
|---|---|---|
| 46 | Vidya University, Meerut, Uttar Pradesh | Vidya Bal Mandli Society, Vidya Knowledge Park, Baghpat Road, Meerut, Uttar Pradesh |

Power to remove difficulties

3. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of "Vidya University, Meerut", Uttar Pradesh by order published in the *Gazette*, direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient :

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature, as soon as may be after it is made.

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 16 of 2024

4. (1) The Uttar Pradesh Private Universities (Eighth Amendment) Ordinance, 2024 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U. P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing Private Universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to provide for the establishment of a new Private University namely, Vidya University, Meerut, Uttar Pradesh, it was decided to amend Schedule 2 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Private Universities (Eighth Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no.16 of 2024) was promulgated by the Governor on October 14, 2024.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
*Pramukh Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 399 राजपत्र–2024–(1083)–599 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 178 सा0 विधायी–2024–(1084)–300 प्रतियां–(डी0टी0पी0/ऑफसेट)।

399 RPH 2024( Adhiniyam) Data1e

क्रम-संख्या–234

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

### भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, बृहस्पतिवार, 26 दिसम्बर, 2024**

**पौष 5, 1946 शक सम्वत्**

उत्तर प्रदेश शासन

**विधायी अनुभाग–1**

———————

संख्या 503/79-वि-1–2024-1-क-27-2024
लखनऊ, 26 दिसम्बर, 2024

———————

अधिसूचना

**विविध**

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवाँ संशोधन), विधेयक, 2024 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2024 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 2024

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2024)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 14 नवम्बर, 2024 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में, धारा 2 के खण्ड (कक) में उप खण्ड (तीन) के पश्चात निम्नलिखित उप खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

''(चार) अन्य राज्यों के अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी अथवा सार्वजनिक न्यास अथवा किसी कम्पनी से है;''

धारा 7 (क) का संशोधन

3—मूल अधिनियम में, धारा 7 (क) में, अंत में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :

''परन्तु यह कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई करते हुए विदेशी उच्चतर शैक्षणिक संस्था, राज्य में 'परिसर' स्थापित कर सकेगी। विदेशी उच्चतर शैक्षणिक संस्था द्वारा ऊपर उल्लिखित विनियम के उपबंधों का अनुपालन किया जायेगा।''

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

4—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा बनाये गये उपबंधों के सम्बन्ध में, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबंध ऐसी अवधि के दौरान जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन, चाहे वे उपांतरण, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीनकृत प्रत्येक आदेश, उसके दिये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

5—(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (नौवां संशोधन) अध्यादेश, 2024 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2024

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह-प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

———

## उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने एवं उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

भारत में अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो अन्य राज्यों के विभिन्न अधिनियमों के अधीन सोसाइटी/न्यास/कम्पनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/अन्य शैक्षणिक संस्थाएं चलाती हैं। राज्य के जनसाधारण को ऐसी संस्थाओं की शैक्षणिक उपलब्धियों की प्रसुविधा प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 देश में विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं द्वारा परिसर की स्थापना करने का उपबंध करता है। राज्य में भी विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं को परिसर स्थापित करने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत ऐसी संस्थायें जो अन्य राज्यों में सोसाइटी/न्यास/कम्पनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं को राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने का अवसर प्रदान करने हेतु और राज्य में विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं का परिसर स्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2 और धारा 7 (क) में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 14 नवम्बर, 2024 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (नौवां संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2024) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वाक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

———————

No. 503 (2)/LXXIX-V-1–2024-1-ka-27-2024
*Dated Lucknow, December* 26, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidyalay (Saatwaan Sanshodhan) Adhiniyam, 2024 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 2024) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 26, 2024. The Uchch Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

## THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (SEVENTH AMENDMENT) ACT, 2024

(U.P. ACT No. 20 OF 2024)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act*, 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Seventh Amendment) Act, 2024.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 14th day of November, 2024.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

2. In the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (aa) of section 2, *after* sub-clause (iii), the following sub-clause shall be *inserted*, namely:-

"(iv) a society or public trust or company registered under an Act of other States."

Amendment of section 7(A)

3. In the principal Act, in section 7(A), the following proviso shall be *inserted* at the end, namely :

"Provided that, acting under the provisions of the University Grants Commission (Setting up and Operation of Campuses of Foreign Higher Educational Institutions in India) Regulations, 2023, the foreign higher educational institution may establish 'campus' in the State. The provisions of the above mentioned regulations shall be complied with by the foreign higher educational institution."

Power to remove difficulties

4. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty in respect of the provisions made by this Act, by order published in the *Gazette*, direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature as soon as may be after it is made.

Repeal and Saving

5. (1) The Uttar Pradesh Private Universities (Ninth Amendment) Ordinance, 2024 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 18 of 2024

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing Private Universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

There are many such institutions in India which are registered as societies/trusts/companies under various Acts of other States and operate schools/colleges/other educational institutions while working in the field of education. There is a need to provide the benefits of educational achievements of such institutions to the general public of the State.

The University Grants Commission (Setting up and Operation of Campuses of Foreign Higher Educational Institutions in India) Regulations, 2023 provides for the establishment of campuses by foreign higher educational institutions in the country. A need has also arisen to grant permission to foreign higher educational institutions to establish campuses in the State.

In view of the above, it was decided to amend section 2 and section 7 (A) of the aforesaid Act to provide opportunity to such institutions which are registered as Society/Trust/Company in other States to establish Private Universities in the State and to grant permission to foreign higher educational institutions to set up campuses in the State.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Private Universities (Ninth Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no. 18 of 2024) was promulgated by the Governor on November 14, 2024.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
*Pramukh Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 398 राजपत्र–2024–(1081)–599 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 177 सा0 विधायी–2024–(1082)–300 प्रतियां–(डी0टी0पी0/ऑफसेट)।

398 RPH 2024( Adhiniyam) Data1e

क्रम-संख्या–233

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

**भाग–1, खण्ड (क)**

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, बृहस्पतिवार, 26 दिसम्बर, 2024**

**पौष 5, 1946 शक सम्वत्**

**उत्तर प्रदेश शासन**

**विधायी अनुभाग–1**

———————

संख्या 499/79-वि-1–2024-1-क-29-2024

लखनऊ, 26 दिसम्बर, 2024

———————

अधिसूचना

**विविध**

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (आठवां संशोधन) विधेयक, 2024 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2024 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

### उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (आठवां संशोधन) अधिनियम, 2024

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2024)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (आठवां संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 6 दिसम्बर, 2024 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 जिसे आगे ''मूल अधिनियम'' कहा गया है, की अनुसूची 2 में, क्रम संख्या 46 के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के साथ स्तम्भवार बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

| क्र0सं0 | विश्वविद्यालय का नाम | प्रायोजक निकाय का नाम |
|---|---|---|
| 47 | विवेक विश्वविद्यालय, बिजनौर, उत्तर प्रदेश | शिविका एजुकेशनल सोसायटी, बिजनौर, उत्तर प्रदेश |

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

3—(1) राज्य सरकार, विवेक विश्वविद्यालय, बिजनौर, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश प्रदान कर सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

4—(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (दसवाँ संशोधन) अध्यादेश, 2024 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 2024

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

---

## उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने एवं उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 ) अधिनियमित किया गया है।

एक नया निजी विश्वविद्यालय अर्थात् विवेक विश्वविद्यालय, बिजनौर, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु उपबंध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरंत विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 6 दिसम्बर, 2024 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (दसवां संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 2024) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 499(2)/LXXIX-V-1–2024-1-ka-29-2024

*Dated Lucknow, December* 26, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidyalay (Aathwaan Sanshodhan) Adhiniyam, 2024 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 2024) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 26, 2024. The Uccha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

# THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (EIGHTH AMENDMENT) ACT, 2024

(U.P. ACT No. 21 OF 2024)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act,* 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-Fifth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Eighth Amendment) Act, 2024.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 6th day of December, 2024.

Amendment of Schedule 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

2. In Schedule-2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 hereinafter referred to as the "principal Act", *after* serial no. 46, the following serial number along with the entries relating thereto shall column-wise be *inserted*, namely :-

| Sl. no. | Name of the University | Name of the Sponsoring Body |
|---|---|---|
| 47 | Vivek University, Bijnor, Uttar Pradesh | Shivika Educational Society, Bijnor, Uttar Pradesh |

Power to remove difficulties

3. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of Vivek University, Bijnor, Uttar Pradesh by order published in the *Gazette,* direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient :

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature, as soon as may be, after it is made.

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 20 of 2024

4. (1) The Uttar Pradesh Private Universities (Tenth Amendment) Ordinance, 2024 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing Private Universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to provide for the establishment of a new private University namely, Vivek University, Bijnor, Uttar Pradesh, it was decided to amend Schedule-2 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Private Universities (Tenth Amendment ) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no. 20 of 2024) was promulgated by the Governor on December 6, 2024.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
*Pramukh Sachiv*.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 397 राजपत्र–2024–(1079)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 176 सा0 विधायी–2024–(1080)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

# STATUTES

# OF THE

# UNIVERSITY

(UNDER SECTION 34 OF THE U.P. PRIVATE UNIVERSITIES ACT, 2019)

AGRAWAN
HERITAGE
UNIVERSITY

## AGRAWAN HERITAGE UNIVERSITY

Bamrauli Katara, Fatehabad
Road, Agra 282006 (U.P.) INDIA

# CONTENT


| | | |
|---|---|---|
| **CHAPTER I (PRELIMINARY)** | | |
| 1. | Short title, Scope and Commencement | 1 |
| 2. | Definitions | 1 |
| 3. | Seal, Flag and Anthem of the University | 2 |
| 4. | Academic Calendar of the University | 2 |
| **CHAPTER II (OFFICERS OF THE UNIVERSITY)** | | |
| 5. | Chancellor: Appointment, Powers and Functions | 3 |
| 6. | Pro-Chancellor: Appointment, Powers and Functions | 5 |
| 7. | Vice-Chancellor: Appointment, Powers and Functions | 6 |
| 8. | Pro-Vice-Chancellor: Appointment, Powers and Functions | 7 |
| 9. | Registrar: Appointment, Powers and Functions | 8 |
| 10. | Dean of School: Appointment, Powers and Functions | 11 |
| 11. | Dean of Students' Welfares: Appointment, Powers and Functions | 12 |
| 12. | Director: Appointment, Powers and Functions | 13 |
| 13. | Controller of Examinations: Appointment, Powers and Functions | 14 |
| 14. | Chief Proctor: Appointment, Powers and Functions | 16 |
| 15. | Finance Officer: Appointment, Powers and Functions | 17 |
| 16. | Head of the Department: Appointment, Powers and Functions | 20 |
| 17. | The Dean, Academic Affairs: Appointment and Functions | 20 |
| 18. | The Dean, Research and Development: Appointment and Functions | 21 |
| 18A | University Librarian: Appointment, Role and Responsibilities | 22 |
| **CHAPTER III (BODIES OF THE UNIVERSITY)** | | |
| 19. | The Governing Body | 24 |
| 20. | The Executive Council | 26 |
| 21. | The Academic Council | 27 |
| 22. | The Finance Committee | 30 |
| 23. | The Planning Board | 31 |

| | | |
|---|---|---|
| 24. | The Research Advisory Board | 32 |
| 25. | The Faculty Board | 34 |
| 26. | The Board of Studies | 35 |
| 27. | The Admission Committee | 36 |
| 28. | The Examination Committee | 37 |
| 28A | University Library Committee | 38 |
| 29. | Internal Quality Assurance Cell | 39 |
| 30. | The Students' Council | 40 |
| **CHAPTER IV (TEACHERS AND EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY)** | | **42** |
| 31. | Minimum Qualifications of Teachers | 42 |
| 32. | The appointment of Teachers and other Academic and Administrative staff and their emoluments | 42 |
| 33. | The conditions of service of employees | 44 |
| 34. | Disciplinary Action against Teachers of the University | 44 |
| 35. | Disciplinary action against Non-Teaching Employees | 46 |
| **CHAPTER V (MISCELLANEOUS PROVISIONS)** | | **48** |
| 36. | Withdrawal of Degree, Diploma, certificate and other Academic Distinctions | 48 |
| 37. | Institution of Fellowships, Scholarships, Studentships, Medals and Prizes | 48 |
| 38. | Maintenance of Discipline among the Students | 48 |
| 39. | The Establishment and Abolition of Schools, Departments and Special Centres | 49 |
| 40. | The Delegation of Powers vested in the Authorities or Officers of the University | 49 |
| 41. | Quorum | 50 |
| 42. | Provision for Diversity in nomination on the various bodies of the University | 50 |
| 43. | Conferment of Honorary degrees and other distinctions. | 50 |

# STATUTES OF AGRAWAN HERITAGE UNIVERSITY

## CHAPTER I (PRELIMINARY)

**1. SHORT TITLE, SCOPE AND COMMENCEMENT**

i. These Statutes may be called First Statutes of the University framed under the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (UP Act No. 8 of 2023). (The Uttar Pradesh Private Universities Amendment Act, 2023);

ii. These Statutes shall come in force with effect from the date of their publication either by displaying it on University website or through newspapers or by both;

**2. DEFINITIONS:** Unless defined otherwise, the;

i. "Act" means the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act No. 8 of 2023);

ii. "Academic Council" means the Academic Council of the University;

iii. "Board" means the Faculty Board, the Board of Studies, the Planning Board, or any other Board of the University;

iv. "Board of Trustees" means the Board of Trustees, Jagdish Jan Kalyan Educational Trust, Shikohabad, Firozabad.

v. "Chancellor", "Pro-Chancellor", "Vice-Chancellor" and "Pro-Vice-Chancellor" means respectively the "Chancellor", the "Pro-Chancellor, the "Vice-Chancellor" and the "Pro-Vice-Chancellor" of the University;

vi. "Controller of Examinations", means a person appointed/ deputed for the conduct of University examination(s) and all related issues;

vii. "Department" means a Department of Studies and includes a Centre of Studies and Research;

viii. "State Government " means the Government of Uttar Pradesh;

vii. The "Statute" means a statute of the First Statutes of Agrawan Heritage University framed under section 34 of the Act;

ix. "Trust" means the Jagdish Jan Kalyan Educational Trust, Shikohabad, Firozabad;

viii. "University" means Agrawan Heritage University, Agra;

ix. The Words and expressions used but not defined in these Statutes shall have the meaning assigned to them in the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2023 and;

x. The powers conferred on the University under the Act shall be exercised by the Officers and the Authorities of the University, as laid down in the Act, the Statutes and the Ordinances of the university.

## 3. SEAL, FLAG AND ANTHEM OF THE UNIVERSITY

i. The University shall have a common seal to be used for the purposes of the University and the design of the seal shall be as approved by the Executive Council.

ii. The University may decide to make and use such Flag, Anthem, and other symbolic or graphic expression, abbreviations or likewise, for such purposes as deemed necessary from time to time, and which are not of such nature that are restricted or prohibited by the State or the Central Government.

## 4. ACADEMIC CALENDAR OF THE UNIVERSITY

i. The Academic Calendar of the University shall be approved by the Executive Council and shall be in conformity with the guidelines issued by the State Government and other Regulatory Bodies from time to time.

ii. The University shall publish its Academic Calendar on its website.

iii. In case of international students, the University may follow a different admission process and Academic Calendar as may be prescribed in the Ordinances.

## CHAPTER II (OFFICERS OF THE UNIVERSITY)

### 5. CHANCELLOR: Appointment, Powers and Functions

i. A person of eminence shall be appointed as the Chancellor by the Governing Body for a period of five years.

ii. The Chancellor shall by virtue of his office, be the head of the University and shall preside over the meetings of the Governing Body and the Annual Convocation.

iii. The Chancellor shall be appointed by the Governing Body, for a period of five years, on the recommendation of the Trust;

Provided that the trust may recommend to the Governing Body, the reappointment of the Chancellor for second or successive terms.

iv. Subject to the provisions of the Act, the Trust shall determine the salary of the Chancellor.

v. The Chancellor shall have power to call for any information or summon any document from the University for the purposes of exercising his powers and functions under the Act.

vi. The Chancellor shall have power to conduct inspection of a Department of Study, a Hostel, an Office or any other department of the University, on his own or direct any Officer or Authority of the University do so on his behalf. He also shall have powers to order an inquiry in respect of any of these establishments or in any other matter connected with University administration and financial management.

vii. The Chancellor may address the Vice-Chancellor with reference to the result of such an inspection/ inquiry, together with his views and advice to the Vice-Chancellor on the follow-up action. The Vice-Chancellor shall communicate forthwith to the authority concerned the result of the inspection/ inquiry, and the views/advice of the Chancellor thereon, and who shall take follow up action within a reasonable time.

viii. If Chancellor is of the opinion that the Vice-Chancellor willfully abuses the powers vested in him and/or refuses to carry out the business of the University in accordance with the provisions of the Act and Statutes or it appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interests of the

University, the Chancellor may place the Vice-Chancellor under suspension.

ix. In such a situation the Pro-Vice-Chancellor or any other Professor may be assigned the officiating charge of the office of Vice-Chancellor by the Chancellor.

x. The Chancellor may appoint a high-power enquiry committee and based on its recommendations and by an order in writing under his signatures, remove the Vice-Chancellor from his office;

Provided that the Vice-Chancellor will be given a chance to defend himself and his viewpoint will be duly considered by the Chancellor before arriving at a decision.

xi. If a vacancy arises in the office of the Vice Chancellor and it is not possible to appoint a regular Vice-Chancellor by following the prescribed procedure of appointment, the Chancellor shall have the power to appoint a person as officiating Vice-Chancellor for a period of six months, to be extended by another six months and any extension thereafter may be allowed only with the approval of the Governing Body.

xii. Notwithstanding anything contained in the Statutes, the Chancellor may discharge all or any of the functions of the University for the purposes of carrying out its business in accordance with the laid down in provisions of the Act and Statutes, when such Officer or Authority of the University is not available.

xiii. The Chancellor may delegate, subject to such terms and conditions as may be specified in writing, all or any of his powers to any Authority/Officer(s) at his discretion and may have the right to modify or recall his order of delegation of such power.

xiv. The decisions taken by the Chancellor may be placed before the Governing Body for information, in its next meeting.

xv. The Chancellor is authorized to issue such directions and/or advise to any Officer/ Authority of the University as deemed necessary, in the interest of the university.

xvi. The Chancellor may, by addressing in writing to the Pro-Chancellor, resign from his office. The Pro-Chancellor shall, within a period of ten days from the date of receipt of such resignation, place this resignation before the Governing Body for decision

xvii. If, at any point of time and upon receipt of a representation or otherwise, the Governing Body after making such inquiry as deemed necessary, comes to the conclusion that the *continuation of Chancellor* is not in the interest of University, it may, based on a majority decision and by an order in writing stating the reasons thereof, ask the Chancellor to relinquish his office before expiration of his term from such date as may be specified in the order. In such a case, the Pro-Chancellor shall preside over the meeting *of the Governing Body;*

Provided that before taking an action under this sub-section, the Chancellor shall be given an opportunity of being heard.

## 6. PRO-CHANCELLOR: Appointment, Powers and Functions

i. The Pro-Chancellor shall be appointed by the Chancellor for a period of five years and upon expiry of his term, shall be eligible for re-appointment.

ii. The Trust shall determine the salary of the Pro-Chancellor.

iii. The Pro-Chancellor shall assist the Chancellor in discharging his duties and he shall exercise such powers as may be delegated to him by the Chancellor.

iv. In the absence of the Chancellor, the Pro-Chancellor shall discharge the duties and responsibilities associated with the Office of the Chancellor.

v. If, at any point of time and upon receipt of a representation or otherwise and after making such inquiry as may be deemed necessary, the situation so warrants that the continuation of Pro- Chancellor is not in the interest of University, the Chancellor with the approval of Governing Body and by an order in writing stating the reasons thereof, may ask the Pro-Chancellor to relinquish his office before expiration of his term, from such date as may be specified in the order;

Provided that before taking an action under this sub-section, the Pro-Chancellor/Vice-Chancellor shall be given an opportunity of being heard.

## 7. VICE-CHANCELLOR: Appointment, Powers and Functions

i. The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried 'Officer of the University.

ii. The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor with the approval of the Governing Body, based on the recommendations of a Search Committee, for a term of five years or till the attainment of the age of 70 years;

Provided that the Governing Body may consider re-appointment of a Vice-Chancellor for further term(s) as may be decided.

iii. The Search Committee shall be constituted as under:

a. One member nominated by the Trust;

b. One serving or retired Professor from outside the University, nominated by the Governing Body; and

c. One member nominated by the Chancellor, who shall act as the Convenor of the Committee.

iv. The Search Committee shall recommend a panel of three names, in alphabetical order, to the Governing Body within the period stipulated by the Chancellor in his order constituting the Search Committee.

v. The Governing Body after receipt of recommendations of the Search Committee shall approve the panel of names and submit it to the Chancellor, along with its recommendations.

vi. In case, none of the names so recommended is found suitable, the Chancellor may advise the search committee to draw a fresh panel of names.

vii. The Vice- Chancellor shall be the Principal Executive and Academic officer of the University, shall exercise general superintendence and control over the affairs of the University and execute the decisions of the Executive Council, other competent authorities / bodies and the State Government.

viii. The Vice-Chancellor, in addition to the powers vested in him by the Act, shall have the following additional powers and responsibilities:

a. It shall be the duty of the Vice-Chancellor to see that the provisions of the Act, Statutes, Ordinances and Regulations of the University are duly followed.

b. The Vice-Chancellor shall be entitled to be present at and to address any meeting of an Authority or any Body of the University.

c. The Vice-Chancellor shall have the power to grant Sabbatical leave, Study leave and Duty leave to the eligible Officers and Teachers and any other kind of leave beyond a period of 30 days, to the Officers, teachers and other employees of the University at the level of Registrar, equivalent and above, other than the Chancellor and Pro-Chancellor;

provided that the Vice-Chancellor may delegate such powers to any other Officer of the University.

d. The Vice Chancellor shall have the power to convene or cause to convene the meetings of various committees and sub-committees not specified in these Statutes.

e. The Vice-Chancellor may resign from his office after giving a three months' notice and shall cease to hold his office on the acceptance of his resignation by the Chancellor, or on expiry of the notice period, whichever is earlier. The requirement of the notice period may be waived off by the Chancellor at his discretion.

## 8. PRO-VICE-CHANCELLOR: Appointment, Powers and Functions

i. The Pro-Vice-Chancellor shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of Vice-Chancellor, from amongst the Professors of the University and shall discharge his duties in addition to his duties as a Professor of the University.

Provided that in the interest of smooth discharge of the work assigned to the Vice-Chancellor, the Executive Council may consider appointing more than one Pro-Vice-chancellor.

ii. In the absence of the Vice-Chancellor, the Pro Vice-Chancellor nominated by the Vice-Chancellor shall discharge the day to day

duties of the office of the Vice-Chancellor, unless otherwise directed by the Chancellor.

iii. If the Vice-Chancellor is of the opinion that the Pro-Vice-Chancellor willfully abuses the powers delegated to him and/or refuses to carry out the business of the University in accordance with the provisions of the Act and Statutes or if it appears to the Vice-Chancellor that the continuance of the Pro-Vice-Chancellor in office is detrimental to the interests of the University, the Vice-Chancellor may revert him to his substantive position, and / or place him under suspension till completion of an inquiry.

iv. The matter shall be reported to the Executive Council in its next meeting and the Council, after due deliberations shall either confirm or revoke the action or take an action as deemed fit.

v. The Pro Vice-Chancellor may resign his office and service after giving a three-month notice and shall cease to hold his office on the acceptance of his resignation by the Vice-Chancellor or on expiry of the notice period, whichever is earlier. The requirement of the notice period may be waived off by the Vice-Chancellor at his discretion.

## 9. REGISTRAR: Appointment, Powers and Functions

i. The Registrar shall be a whole time salaried 'Officer of the University'.

ii. The Registrar shall be appointed by the Executive Council, on recommendations of a duly constituted Selection Committee.

iii. The qualifications for recruitment to the post of Registrar shall be as prescribed by the University Grants Commission from time to time.

iv. The Selection committee for the posts of Registrar shall be constituted as under:

a. The Vice-Chancellor - Chairman;
b. The Pro-Vice-Chancellor;
c. One nominee of the Chancellor;
d. One member of the Executive Council nominated by Chancellor;
e. One outside expert nominated by the Vice-Chancellor; and
f. The Director/Head, Human Resource Department shall be the convenor of the Committee.

v. The term of office of the Registrar shall be for a period of three years, renewable for additional term(s) till the attainment of the age of superannuation, i.e. 65 years;

Provided that in exceptional circumstances the Executive Council may extend the term of Registrar beyond 65 years and up to the age of 68 years.

vi. The Executive Council, in a case of misconduct, may place the Registrar under suspension *suo-moto*, or on the recommendations of the Vice-Chancellor, order an inquiry and take appropriate action in accordance with the findings of the inquiry committee.

vii. If the Executive Council, based upon the findings of the inquiry committee, arrives at a conclusion that the continuance of the Registrar is not in the interest of the University, it may, by an order in writing stating the reasons therefore, ask the Registrar to relinquish his office from such date as may be specified in the order;

Provided that before taking an action under this sub-clause, the Registrar shall be given an opportunity of being heard.

viii. When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is unable to perform his duties by reason of illness, or any other cause, the Vice-Chancellor may assign the work of the Office of Registrar to a Joint Registrar or an Officer equal in rank, to officiate as Registrar until the Registrar reports back;

Provided that such Officiating Registrar shall discharge only the routine duties and responsibilities of the post of Registrar and any decision on policy and other important matters shall be taken by the Vice-chancellor.

ix. The Registrar may resign his office after giving a three-months' notice. He shall cease to hold his office from the date of acceptance of his resignation by the Executive Council or on expiry of the notice period, whichever is earlier. The requirement of the notice period may be waived by the Executive Council.

x. The Registrar in addition to the duties and responsibilities laid down in the Act shall:

a. be the custodian of the records and the common seal and such other properties of the University, as placed by the Executive Council under his charge;

b. be the ex-officio member secretary of the Executive Council and the Planning Board and, non-member secretary of the Governing Body and the Academic Council;

c. be to issue notices for convening the meetings of the Governing Body, Executive Council, Academic Council and the Planning Board and prepare and *circulate their agenda and* also issue the minutes of the meetings and their record keeping;

d. be to conduct the official correspondences of the Governing Body, the Executive Council, the Academic Council and the Planning Board;

e. be to issue offers of appointment letters for appointment of the Teachers and employees;

f. be to exercise powers to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf *of the university;*

g. be to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the university; and

h. be to represent the University in legal suits or proceedings by or against the University, sign powers of attorney and verify pleadings;

Provided that the Registrar may delegate this authority to one of his immediate sub-ordinates or depute his representative for the purpose.

xi. The Registrar shall be assisted in his work by a number of other officials, including Joint Registrar, Deputy Registrar, Assistant Registrars and OSD level officers, whose work and conduct shall be supervised by him.

xii. The Registrar may also be assisted, in discharge of his duties and responsibilities, by such other officials as may be assigned to him by the Vice-Chancellor.

xiii. The Registrar shall be the custodian of all properties of the University unless otherwise provided for by the Executive Council.

xiv. The Registrar shall exercise such other powers as may be necessary or expedient for carrying out the decisions of university authorities or bodies of which he acts as a member or a non-member secretary.

## 10. DEAN OF FACULTIES: Appointment, Powers and Functions

i. The Dean of a faculties shall be appointed by the Executive Council from amongst the Professors of the faculties and as recommended by the Vice-Chancellor.

ii. The Dean shall hold his office for a period three years or for a period as specified;

Provided that when the office of the Dean is vacant or when the Dean, by reason of illness or absence or any other reason, is unable to perform his duties, the duties of the office of Dean may be performed by the Associate/Assistant Dean, and if there is no Associate/ Assistant Dean by such other Dean or Professor, as the Vice-Chancellor may decide;

Provided further that no person shall continue to be a Dean after he ceases to hold the post by virtue of which he was appointed to the office of Dean;

iii. The Executive Council may remove a Dean from his office, if he is found guilty of misconduct of any kind, or if he fails to perform the duties of his Office to the satisfaction of the Executive Council, and revert him to his substantive post and/ or place him under suspension till completion of an inquiry.

iv. The Dean shall have the right to be present and to speak at any of the meetings of the Board of Studies of a Department.

v. The Dean shall have the following powers, duties and responsibilities:

a. shall be the head of the Department;

b. shall be responsible for maintenance of the standard of the teaching and research undertaken by the Department;

c. shall preside over the meetings of Faculty Board and shall ensure that the decisions of the Board are implemented in letter and spirit, after their approval;

d. shall be responsible for bringing the academic, financial and other requirements of the Department to the notice of the Vice-Chancellor; and

e. shall take necessary measures for proper maintenance of libraries, laboratories and all other assets of the Departments.

***Note***: *In* Department *having substantially higher number of students/ administrative load, the Vice-Chancellor, in consultation with the Dean of the faculty, may appoint a Professor/ Associate Professor as Associate/ Assistant Dean, in addition to their existing duties as teacher of the University, to strengthen the academic administration of a faculty.*

vi. The Dean shall also exercise such other powers and perform such other functions as may be decided by the Executive Council or as laid down in the Ordinances or Regulations of the University.

vii. The Dean may resign his office and service after giving a three-month notice and shall cease to hold his office on the acceptance of his resignation by the Vice-Chancellor or on expiry of the notice period, whichever is earlier. The requirement of the notice period may be waived off by the Vice-Chancellor at his discretion.

## 11. DEAN STUDENTS' WELFARES: Appointment, Powers and Functions

i. Dean Students' Welfare shall be appointed by the Executive Council, from amongst the teachers of the University not below the rank of Assistant Professor and possessing teaching experience of not less than 10 years.

ii. The Vice-Chancellor may also appoint an Associate/Assistant Dean Students Welfare out of the Associate/Assistant Professors of the University to assist the Dean Students Welfare.

Provided that one such Associate/Assistant Dean Student Welfare shall be from amongst the women teachers of the University in case the Dean is a male teacher, to specially look after the welfare of the girl students.

iii. The Associate/Assistant Dean shall report to the Dean of Students' Welfare.

iv. The term of office of the Dean as well as Associate/Assistant Dean Students' Welfare shall be for a period three years or as specified.

v. The Dean Students' Welfare shall be responsible for:

a. organizing co-curricular, cultural, social, recreational and sports activities at the University;
b. development of leadership skills in the students;
c. arranging medical assistance in case of emergency;
d. securing monetary assistance for needy students;

$ *Amended/ included vide 26th EC dated 30.04.2024*

e. counselling and personality building;
f. maintenance of peace and harmony amongst various sections of students;
g. Any other activity related to students' welfare; and
h. Perform such other duties as may be assigned by the Vice-Chancellor.

vi. The Dean as well as the Associate/Assistant Dean Students Welfare may communicate with the parents and guardians, as and when necessary.

vii. The Executive Council may remove the Dean Students Welfare from his office, if he is found guilty of misconduct of any kind, or if he fails to perform the duties of his Office to the satisfaction of the Executive Council, and revert him to his substantive post and/ or place him under suspension till completion of an inquiry;

provided that the Vice-Chancellor shall be the competent to take similar action against an Associate/Assistant Dean Students Welfare.

viii. The Dean of Students' may resign his office and service after giving a three-month notice and shall cease to hold his office on the acceptance of his resignation by the Vice-Chancellor or on expiry of the notice period, whichever is earlier. The requirement of the notice period may be waived off by the Vice-Chancellor at his discretion.

## 12. DIRECTOR: Appointment, Powers and Functions[$]

To discharge diverse and specific functions at the University level, the Executive Council may appoint, on the recommendations of the Vice- Chancellor, a number of Director level senior academics/ administrators from amongst the Professors/ Associate Professors/ Administrators of the University;

Provided that such existing Directors, namely, Director, Internal Quality Assurance Cell (IQAC), Director, Teaching Learning Centre (TLC) and Director, Industry Integration & Knowledge Exchange Cell (IIKEC) is declared as Statutory Officers of the University, in terms of Section 14(12) of the University Act; and

Provided further that such Director(s) shall work under the direct supervision and guidance of the Vice-Chancellor.

i. The term and other conditions of appointment of such Director(s) shall be as determined by the Executive Council.

ii. The Director may resign his office and service after giving a three-month notice and shall cease to hold his office on the acceptance of his resignation by the Vice-Chancellor or on expiry of the notice period, whichever is earlier. The requirement of the notice period may be waived off by the Vice- Chancellor at his discretion.

## 13. CONTROLLER OF EXAMINATIONS: Appointment, Powers and Functions

i. The Controller of Examinations shall be a whole-time salaried officer of the University having a teaching experience of at least 10 years., at a University/ Institution of repute

ii. The Controller of Examinations shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of a duly constituted selection committee for a period of three years or as decided;

Provided that the Executive Council may appoint a teacher of the University not below the rank of Associate Professor to discharge the duties of the office of the Controller of Examination in addition to his own duties as a teacher of the University for a term of three years or as decided by the Executive Council.

iii. The Selection committee for the selection of Controller of Examinations shall be constituted as under:

a. The Vice-Chancellor – Chairman
b. The Pro-Vice-Chancellor;
c. A nominee of the Chancellor;
d. One member of the Executive Council nominated by the Chancellor;
e. One Dean/ Professor of the University nominated by the Vice-Chancellor; and
f. Registrar - *Ex-Officio* Secretary.

iv. The age of superannuation of the Controller of Examination shall be 65 years;

v. Provided that in exceptional circumstances the Executive Council may extend the term of the Controller of Examination beyond 65 years, up to the age of 68 years;

vi. The Controller of Examinations shall be the responsible for the smooth conduct of the examinations, declaration of results and its notification on time. He shall discharge his duties under the supervision, direction and guidance of the Vice-Chancellor.

vii. The Controller of Examinations shall be the Member Secretary of the Examinations Committee and may be invited to a meeting of the Executive Council and the Academic Council as and when a matter related to examinations is under consideration.

viii. The Controller of Examinations with prior approval of the Vice-chancellor shall:

a. prepare and announce the calendar the examinations;
b. get the examiners and moderators appointed by the Vice-chancellor from the list prepared by the Examination Committee and approved by the Academic Council;
c. be responsible for getting the paper set, printing of question papers and blank answer books and their safe custody, planning and conduct of examination, assessment of answer books, consolidation-preparation and timely declaration of results, verification, revaluation, issue of certificates / degrees/ diplomas and maintenance of examination records;
d. make available one set of question papers to the University library after the examinations are over;
e. get the committee constituted to find facts and settle the cases of unfair means, if any, and to take action as recommended;
f. recommend to the Vice-Chancellor postponement or cancellation of the examinations in the event of a malpractice, in part or in full, or if the circumstances so warrant, take disciplinary action or initiate a civil or criminal proceeding against a person or persons alleged to have committed the malpractice, in consultation with the Vice-Chancellor;
g. make suitable recommendations to the Vice-Chancellor for ensuring fairness, secrecy and confidentiality of examination;
h. make a performance analysis of results, within a period of one month, and report the outcome thereof to the Vice-Chancellor, the Dean and the Head of Department; and
i. submit a comprehensive report to the Academic Council on the examination conducted in each semester/term.

ix. The Controller of Examinations shall also exercise such other powers and perform such other duties as may be assigned to him by the Vice-Chancellor from time to time.

x. The Vice-Chancellor, in order to strengthen the Examination system, may appoint a Joint/Deputy/Assistant Controller of Examination(s), from amongst the employees of the University, on such terms and

conditions as a may be decided by the Vice-Chancellor.

xi. The Controller of Examinations may resign his office after giving a three-month notice and shall cease to hold his office on the acceptance of his resignation by the Vice-Chancellor or on expiry of the notice period, whichever is earlier. The requirement of the notice period may be waived off by the Vice-Chancellor at his discretion.

xii. If, at any point of time and based upon a complaint received by the Vice-Chancellor or on his own, the Vice-Chancellor arrives at a conclusion that continuance of the Controller of Examinations is detrimental to interest of the University, he may place the Controller of Examination under suspension, institute an inquiry and based on the finding of the inquiry committee recommend to the Executive Council the removal of the Controller of Examinations from his office from such date as may be specified;

provided that before taking such an action, the Controller of Examinations shall be given an opportunity of being heard.

## 14. CHIEF PROCTOR: Appointment, Powers and Functions

i. The Chief Proctor shall be appointed by the Executive Council, from amongst the teachers of the University not below the rank of Associate Professor for a term of three years or a term as specified.

ii. The Chief proctor shall exercise such powers and perform such duties with regards to maintenance of discipline amongst the students as may be prescribed in the Ordinances or as decided by the Vice-Chancellor from time to time.

iii. The Vice-Chancellor may appoint Associate/Assistant Proctor(s), to strengthen the proctorial system, from amongst the Associate/Assistant professors of the University;

Provided that at least one female teachers of the University is appointed as Associate/ Assistant Proctor, if the Proctor is a male teacher.

iv. There shall be a Proctorial Committee consisting of all the Proctors;

Provided that the Vice-Chancellor, in consultation with the Chief Proctor, may nominate a senior employee of the university to the proctorial committee for a period as may be specified.

v. Any violation of the Students Code of Conduct and Ethics shall be treated as a misconduct and shall attract penal action as decided by the Vice-Chancellor on the record of the Chief Proctor/ Proctorial Committee.

vi. Any student indulging in an act of misconduct or indiscipline is liable to be suspended from the University by the Vice-Chancellor on recommendations of the Chief Proctor pending an inquiry;
Provided in exigencies of the situation, the Dean may issue suspension order on specific recommendation of the Chief Proctor, subject to its ratification by the Vice-Chancellor.

vii. The Executive Council may remove the Chief Proctor from his office, if he is found guilty of misconduct of any kind, or if he fails to perform the duties of his Office to the satisfaction of the Executive Council, and revert him to his substantive post and/ or place him under suspension till completion of an inquiry;

Provided further that the Vice-Chancellor shall be the competent to take similar action against an Associate/Assistant Proctor.

viii. The Chief Proctor may resign his office and service after giving a three-months' notice and shall cease to hold his office on the acceptance of his resignation by the Vice-Chancellor or on expiry of the notice period, whichever is earlier. The requirement of the notice period may be waived off by the Vice-Chancellor at his discretion.

## 15. FINANCE OFFICER: Appointment, Powers and Functions

i. The Finance Officer shall be a whole time salaried 'Officer of the University.

ii. The Finance Officer shall be appointed by the Executive Council, on the recommendations of the Selection Committee;

Provided that the University may designate a Finance Officer, as Director Finance or Chief Finance Officer at its discretion.

iii. The qualifications for appointment to the post of Finance Officer shall be a Post-Graduate degree, preferably in Commerce, Economics or Financial Management or Chartered Accountant or equivalent, having a minimum of ten years of work experience at the level of Deputy/ Assistant Finance Officer preferably in a University or an Educational Institution of repute.

iv. The Selection committee for the post of Finance Officer shall be constituted as under;

a. The Vice-Chancellor- Chairman

b. The Pro-Vice-Chancellor;
c. One nominee of the Chancellor;
d. One member of the Executive Council nominated by Chancellor;
e. One outside expert nominated by the Vice-Chancellor; and
f. The Registrar - *Ex-officio* Secretary.

v. The term of the Finance Officer shall be for a period of three years, renewable for additional term(s), till the age of superannuation i.e. 65 years;

vi. Provided that in exceptional circumstances the Executive Council may extend the term of Finance Officer beyond 65 years of age, up to the age of 68 years.

vii. The emoluments and other terms and conditions of service of the Finance Officer shall be as decided by the University;

viii. If at any point of time and based on a complaint received against the Finance Officer, the Vice-Chancellor after thorough examination of the matter is satisfied of the veracity of the charges levelled, may place the finance Officer under suspension and appoint an inquiry committee to inquire into the alleged charges;

ix. The Executive Council, based on the findings of the inquiry committee and on the recommendations of the Vice-Chancellor may remove the Finance Officer from his office;

Provided that before taking such an action, the Finance Officer shall be given an opportunity of being heard.

x. The Finance Officer may resign his office and service after giving a three-months' notice and shall cease to hold his office on the acceptance of his resignation by the Vice-Chancellor or on expiry of the notice period, whichever is earlier. The requirement of the notice period may be waived off by the Vice-Chancellor at his discretion.

xi. When the office of the Finance Officer is vacant or if the Finance Officer on account of illness or any other reason is unable to perform the duties of his office, the duties of the office of Finance Officer shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may decide.

xii. Subject to the supervision and directions of the Finance Committee, the Finance Officer shall:

a. be responsible for general supervision over the funds of the University and advise the University with regards to its financial policy;

b. hold and manage the investments including those of the Trust and Endowments for furthering the objects of the University;

c. ensure that the limits fixed by the Finance Committee for recurring and non-recurring expenditure are not exceeded to and that the money is expended for the purposes to which it was granted/allotted.

d. be responsible for the preparation of annual accounts and the budget of the University for the next financial year and for their presentation to the Finance Committee;

e. keep a constant watch on the maintenance of the cash and bank balances and on the state of investments;

f. watch the progress of collection of revenue and advise on the methods of collection employed;

g. be responsible for the preparation of the financial statements and the conduct of Annual Statutory Audit by an independent statutory auditor appointed by the Trust;

h. maintain and update the registers of buildings, land and equipment and conduct of the Physical verification of the Stores and other facilities/departments and also the consumable materials;

i. call explanation for unauthorized expenditure or other financial irregularities and, after being satisfied that the expenditure incurred is unauthorized, bring the same to the notice of the Vice-Chancellor;

j. obtain from any School/Department/Centre any information or return that he may consider necessary to discharge his financial responsibilities; and

k. perform such other financial functions as may be assigned to him by the Executive Council or as may be prescribed by the Ordinances Rules and the Regulations.

## 16. HEAD OF THE DEPARTMENT: Appointment, Powers and Functions

i. The Head of a Department shall be appointed by the Vice-Chancellor, from a panel of three names of the senior teachers of the Department received from the Dean of the School, for a period two years or as may be specified.

ii. The Head of the Department shall preside over the meetings of the Board of Studies.

iii. The Head of the Department shall exercise such other powers and discharge such other functions as laid down in the Ordinances and Regulations.

iv. The Vice-Chancellor may remove the Head of the Department, if he is found guilty of misconduct of any kind, or fails to perform his duties to the satisfaction of the Vice-Chancellor and revert him to his substantive post and/ or place him under suspension till completion of an inquiry;

Provided that the Head of the Department will be heard before taking such a decision.

v. The Head of Department may resign his office and service after giving a three-months' notice and shall cease to hold his office on the acceptance of his resignation by the Vice-Chancellor or on expiry of the notice period, whichever is earlier. The requirement of the notice period may be waived off by the Vice-Chancellor at his discretion.

## 17. THE DEAN, ACADEMIC AFFAIRS: Appointment and Functions

i. The Dean, Academic Affairs shall be appointed by the Executive Council, on the recommendations of a committee constituted under the chairmanship of the Vice-Chancellor and consisting of a Chancellor's nominee and three experts nominated by the Executive Council, from within or outside the University, for a period of three years or a period as may be specified;
Provided that the Dean, Academic Affairs may be re-appointed for further term(s) as decided by the Executive Council.

ii. A teacher having a minimum of 10-year experience as a Professor and having sound Academic credentials, publications in indexed Journals and having at least 5-year Administrative *experience at the level of* Dean/Director or above, will be eligible for appointment as Dean, Academic Affairs.

iii. The Dean, Academic Affairs shall:

a. assist the Vice-Chancellor in keeping a close watch on academic activities undertaken by the Schools of the University;
b. ensure that the decisions of the Academic Council are followed in letter and spirit
c. advise the Vice-Chancellor on the updation of curriculum, in accordance with the demand of industry and at par with the one being followed by institutions of repute; and
d. scrutinize the academic proposals emanating from the schools before these are forwarded for consideration of the Vice- Chancellor or the Academic Council.

iv. The Dean, Academic Affairs may resign his office and service after giving a three- m o n t h s' notice and shall cease to hold his office on the acceptance of his resignation by the Vice-Chancellor or on expiry of the notice period, whichever is earlier. The requirement of the notice period may be waived off by the Vice-Chancellor at his discretion.

v. The Vice-Chancellor, based upon a complaint received against the Dean Academic Affairs or on his own, if arrives at a conclusion that continuance of the Dean Academic Affairs is detrimental to the interests of the University, may recommend to the Executive Council the removal of the Dean Academic Affairs from his office from such date as may be specified and after giving the Dean Academic Affairs an opportunity of being heard.

## 18. THE DEAN, RESEARCH AND DEVELOPMENT: Appointment and Functions

i. The Dean, Research and Development shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of a committee appointed under the chairmanship of the Vice-Chancellor and consisting of a Chancellor's nominee and three experts nominated by the Executive Council from within or outside the University, for a period of three years or a period as may be specified;

Provided that the Dean, Research and Development shall be eligible for re-appointment for another term(s) as may be specified.

ii. A teacher with requisite institutional commitment and having a minimum of 10 year experience as a Professor in a reputed University/Institute with sound Academic credentials, publications in indexed Journals and having at least 5 year Administrative experience at the level of Dean/Director, will be eligible for as Dean, Research and Development.

iii. The Dean, Research and Development shall:

a. be the ex-officio secretary of the Research Advisory Board and as such will give effect to its decisions;
b. be overall in-charge of the Ph.D. programme and shall ensure that the topic of research selected has relevance to the present day requirement;
c. ensure quality of research work done by the students admitted to Ph.D. programme and shall guide the younger faculty members in undertaking their own research;
d. help the faculty members in formulation of research projects and submission of proposal for research grants to the Government as well as the Industry; and
e. mobilise funds for research.

iv. The Dean, Research & Development may resign his office and service after giving a three month notice and shall cease to hold his office on the acceptance of his resignation by the Vice-Chancellor or on expiry of the notice period, whichever is earlier. The requirement of the notice period may be waived off by the Vice-Chancellor at his discretion.

v. If the Vice-Chancellor, based upon a complaint received against the Dean Research and Development or on his own, arrives at a conclusion that continuance of the Dean research and Development is detrimental to the interests of the University, may recommend to the Executive Council the removal of the Dean research and Development from his office from such date as may be specified and after giving the Dean research and Development an opportunity of being heard.

**18A. University Librarian: Appointment, Role and Responsibilities**

i. The University Librarian shall be a whole time salaried employee of the University having professional qualification and experience at par with that prescribed by the University Grants Commission.

ii. The University Librarian shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of a duly constituted selection committee for a period of three years or as may be prescribed;

Provided that the Executive Council may appoint a teacher of the University not below the rank of Associate Professor to discharge the duties of the office of the University Librarian, in addition to his own duties as a teacher of the University, for a term as decided by the Executive Council;

iii. The Selection Committee for the selection of University Librarian shall be constituted as under:
   a. The Vice-Chancellor – Chairman
   b. A nominee of the Chancellor;
   c. One member of the Executive Council nominated by the Vice-Chancellor;
   d. One Dean/ Professor of the University nominated by the Vice-Chancellor; and
   e. Registrar - Ex-Officio Secretary.

iv. The age of superannuation of the University Librarian shall be 65 years; provided that in exceptional circumstances the Executive Council may extend the term of the University Librarian beyond 65 years, up to the age of 68 years;

v. The University Librarian may resign his office and service after giving a three - months' notice and shall cease to hold his office on the acceptance of his resignation by the Vice-Chancellor or on expiry of the notice period, whichever is earlier. The requirement of the notice period may be waived off by the Vice-Chancellor at his discretion.

**Role and Responsibilities:**

The University Librarian shall be the executive head of the library management and as such shall perform the following duties and responsibilities:

a. He shall be the convener of the Library Committee and shall prepare the budget of the University Library and other libraries for consideration of the Library Committee.
b. He shall monitor and control the utilization of library budget.
c. He shall supervise and guide the library staffs, including individual librarians who shall work under his direct superintendence and control.
d. He shall interact regularly with Deans and Head of Departments to identify their teaching and research requirements for facilitating acquisition of physical and digital resources.
e. The University Librarian shall subscribe and disseminate information regarding online databases, books and journals available, to the academic community.
f. He will interact with the publishers for conducting book-exhibitions, usually in the beginning of academic year, as also to plan book acquisition.
g. He will conduct orientation programs for the first year students and newly inducted faculty members, besides providing bibliographical guidance to faculty and research scholars.
h. He will also monitor the usage of the digital library, footfalls in the Central Library and other libraries and will submit a semester-wise report, or as and when required, to the Vice Chancellor.

## CHAPTER III (AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY)

### 19. THE GOVERNING BODY

i. The Governing Body shall be constituted as under

a. The Chancellor – Chairman;
b. The Pro-Chancellor;
c. The Vice-Chancellor;
d. One member nominated by the Trust – Member;
e. One eminent educationist nominated by the trust – Member;
f. One member from industry/ corporates nominated by the Trust – Member;
g. One legal expert nominated by the Trust –Member;
h. One financial expert nominated by the Trust – Member;
i. The Trust, may nominate up to six additional subject matter specialists as members of the governing body;
j. The Chancellor may also co-opt up to three eminent persons as members of the Governing Body; and
k. Registrar – Secretary.

ii. The term of nominated members shall be three years or as decided.

iii. The ex-officio members shall continue to be the members of the Governing Body so long as they hold the office by virtue of which they are the members of the Governing Body.

iv. The trust shall have powers to remove a member of the Governing Body.

v. A member nominated/co-opted member of the Governing Body not attending three consecutive meetings without prior notice shall cease to be a member of the Governing Body and the vacancy will be duly filled in.

vi. The other terms and conditions of nomination of the members to the Governing Body, including remuneration, if any, shall be determined by the Chancellor from time to time and the decision thereon shall be final. The Governing Body shall have the right to review and modify any of the nominations made by it.

vii. Meetings of the Governing Body shall be convened by the Chancellor either on his own initiative or on a requisition from a minimum one fourth of the members of the Governing Body.

viii. The quorum of the meeting shall be one third of the total membership of the Governing Body.

ix. Decisions on all the matters considered in the meetings shall be made through majority votes of the members present and voting and in case of a tie, the matter shall be decided by the casting vote of the Chairman.

x. The Chancellor shall preside over the meetings of the Governing Body and in his absence; the Pro Chancellor shall preside over the meeting.

Provided that in case both the Chancellor and the Pro-Chancellor are not available, the Vice-Chancellor shall preside the meeting of the Governing Body.

xi. The written notice of the meeting shall be issued by the Registrar at least two weeks before the date of the meeting;

Provided that the Chairman may call a special meeting of the Governing Body at short notice to consider any urgent matter.

xii. The notice of the meeting may be sent through email or delivered by hand or sent by registered post at the address of each member as recorded in the office of the Registrar and the same shall be deemed to have been duly delivered within the time.

xiii. The agenda shall be circulated by the Registrar at least one week before the date of the meeting.

xiv. Notices of motions for inclusion of any item on the agenda must reach the Registrar at least fifteen days before the meeting. The Chairman may, however, permit inclusion of any item for which due notice has not been received.

xv. The ruling of the Chairman in regard to all the questions of procedure shall be final.

xvi. The minutes of the meetings drawn up by the Registrar and approved by the Chancellor, shall be circulated by the registrar. The minutes along with amendments, if any, shall be placed for confirmation at the next meeting of the Governing Body. After the minutes are confirmed, the same shall be recorded in the book of minutes which shall be kept open for inspection during office hours by the members of the Governing Body.

xvii. The Governing Body shall have powers to nominate members/ its representatives on the Councils of various Statutory Bodies, Government, Semi-Government or Private Bodies for a period as may be specified.

## 20. THE EXECUTIVE COUNCIL

i. The Executive Council shall be the principal Executive Authority of the University and shall meet at least twice in each Academic year

ii. The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Executive Council, which shall consist of the following other members, namely: -

a. Three members to be nominated by the Governing Body;
b. Two eminent educationists nominated by the Chancellor;
c. One officer of the State Government not below the rank of Joint Secretary to the Government of Uttar Pradesh;
d. One Professor and one Associate Professor of the University in order of seniority on rotation basis for a period of one year;
e. One educationist not below the rank of Associate Professor from a panel of three names to be approved by the State Government, for which the University shall submit a list of three names of eminent educationists;
f. The Registrar who shall be ex-officio Member Secretary; and
g. The Finance Officer shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Executive Council but shall not be entitled to vote;

iii. The ex-officio members shall continue to be the members as long as they hold the office by virtue of which they are the members of the Executive Council.
However, the members, other than the ex-officio members, shall have a term of 3 years.

iv. A member of the Executive Council, other than the state nominees, may be removed by the Governing Body.

v. A nominated member, other than the state nominees, not attending three consecutive meetings without prior notice, shall cease to be a member of the Executive Council and the vacancy will be filled for the remaining period in accordance with the laid down procedure.

vi. Meetings of the Executive Council may be convened by the Vice-Chancellor suo moto or on a requisition signed by not less than one third of the total members. The quorum of the meeting shall be not less than six members of the Executive Council.

vii. Decision on all the matters placed for consideration of the Executive Council shall be made through simple majority, in case of a tie the matter shall be decided by the casting vote of the Chairman.

viii. Notice of the meeting shall be issued by the Registrar and sent to the members through email or delivered by hand or sent by the

registered post, at least two week prior to the date of the meeting, stating clearly the venue, date and time of the meeting;

provided that the Vice-Chancellor may call an emergent meeting of the Executive Council at short notice.

ix. The agenda of the meeting shall be circulated by the Registrar at least one week before the meeting. Requests for inclusion of any item on the agenda must reach the Registrar at least two weeks before the meeting. The Vice-Chancellor may, however, permit inclusion of any item for which due notice has not been received.

x. The ruling of the Chairman in regard to all questions of procedure shall be final

xi. The minutes of the meetings drawn up by the Registrar and approved by the Vice-Chancellor shall be circulated to the members of the Executive Council. The minutes along with amendments, if any, shall be placed for confirmation at the next meeting of the Executive Council. After the minutes are confirmed, the same shall be recorded in the book of minutes shall be kept open during office hours for inspection by the members of the Executive Council

xii. The decisions taken by the Executive Council shall be placed before the Governing Body for information.

xiii. The Executive Council, may authorize the Vice-Chancellor to make such decisions and exercise such powers as deemed necessary for timely discharge of the matters placed under its charge;

Provided that, the decisions taken shall be placed before in the next meeting of the Executive Council for ratification.

## 21. THE ACADEMIC COUNCIL

i. The Academic Council shall be the principal Academic Authority of the University and shall meet at least twice in each academic year.

ii. The Academic Council shall be constituted as under:

a. The Vice-Chancellor - Chairman;
b. All Deans of the Schools of Studies;
c. Dean Academic Affairs;
d. Dean Research and Development;
e. All Heads of Department;

Provided that the Departments having less than 250 students shall be represented in Academic Council by Dean of the School or a Head of the Department, *nominated by the Dean;* Provided further that the Departments with more than 750 students shall have another Professor/Associate Professor nominated as a member of Academic Council;

f. Five members nominated by the Vice-Chancellor, other than Heads of the Departments, at the *level of Professors, Associate* Professors or Assistant Professors;

g. Three distinguished professionals representing academia, trade, industry, science and technology, nominated by the Chancellor;

h. The Vice-Chancellor may co-opt up to three students as members in each Academic year; and

i. The Registrar- ex-officio Secretary.

iii. The term of office of the ex-officio members shall be co-terminus with the term of their offices. While members of the Academic Council, other than the ex-officio members, shall hold office for a term of two years, the nominated students shall have a term of one year only.

a. The meetings of the Academic Council shall be convened by the Vice-Chancellor *suo moto* or on a requisition signed by not less than 25% members of the Academic Council.

b. The quorum of the meeting shall be one third of the total strength of the Academic Council.

c. The written notice of meetings shall be issued by the Registrar and sent through email or delivered by hand or through registered post to every member at least two weeks before the date of the meeting;

Provided that the Vice-Chancellor may call a special meeting of the Academic Council at short notice.

d. The agenda of the meeting shall be issued by the Registrar at least one week before the meeting.

e. All questions considered at the meetings of the Academic Council shall be decided by a majority vote of the members present and voting;

Provided that the Chairman shall have a casting vote in case of a tie.

iv. The Academic Council may authorize the Vice-Chancellor to exercise the powers vested in the Academic Council in an emergent situation;

Provided that the emergency decision(s) taken shall be placed in the next meeting of the Academic Council for ratification.

v. The minutes of the meetings drawn up by the Registrar and approved by the Vice-Chancellor shall be circulated to the member. The minutes along with amendments, if any, shall be placed for confirmation at the next meeting of the Academic Council and shall be recorded in the book of minutes which shall be kept open during the office hours for inspection by the members of the Academic Council.

vi. The recommendations of the Academic Council in matters falling under the jurisdiction of the Executive Council shall be placed before the Executive Council for approval, in the next meeting.

vii. Subject to the provisions as laid down in the University Act, the Academic Council shall have the following powers and perform the following functions:

a. consider and approve the proposals received from the Departments of Studies with respect to the course structures, credit details and syllabi and the programmes proposed to be offered by the Departments;

b. exercise general control over the academic policies of the University, issue direction on methods of instruction, quality of question paper, co-ordination of teaching amongst various schools, maintenance and improvement of academic standards and evaluation of research undertaken at the Departments of Studies.;

c. make proposals to Executive Council for establishment of new Departments, Specialized Centres and Laboratories;

d. recommend to the Executive Council institution of the Degrees, Diploma, Certificates and other academic distinctions, to be awarded by the University; and

e. recommend to the Executive Council the recognition of degrees and diplomas of other Universities and institutions and

to determine their equivalence with degree and diplomas offered by the University;

## 22. THE FINANCE COMMITTEE

i. The Finance Committee shall be the principal financial body of the University.

ii. The Finance Committee shall be constituted as under:

a. The Vice-Chancellor: Chairman

b. The Registrar;

c. A Professor of the University nominated by the Executive Council;

d. One financial expert nominated by the Trust;

e. A nominee of the Chancellor; and

f. The Finance Officer- Member Secretary.

iii. The Vice-Chancellor shall be authorised to invite an expert in financial matters, to any meeting of the Finance Committee as a special invitees.

iv. The term of the ex-officio members shall be coterminous with the office they hold and by virtue of which they are members of the Finance Committee. The term of office of a nominated member shall be two years.

v. In the absence of the Vice-Chancellor, the Pro Vice-Chancellor shall preside over the meetings. In case the Pro Vice-Chancellor is also not available, a member from amongst the members present may preside over the meeting.

vi. The Finance Committee shall meet at least twice in an academic year and shall be convened by the Chairman either on his own initiative or on a requisition signed by at least one third of the members of the Finance Committee;

Provided that the Vice-Chancellor shall be authorised to call a special meeting of the Finance Committee at short notice.

vii. The quorum of the meeting shall be one third of the total strength of the Finance Committee.

viii. Decisions on all the matters considered in the meetings shall be made through majority votes of the members present and voting and in case of a tie, the matter shall be decided by the casting vote of the Chairman.

ix. The notice of the meeting shall be sent by the Finance Officer at least two weeks before the date of the meeting, through email or delivered by hand or sent by registered post.

x. The agenda of the meeting shall be circulated to the members at least one week before the date of the meeting.

xi. The Vice-Chancellor shall be authorised to exercise the powers vested in the Finance Committee in case of an emergency. The emergency decision taken shall be placed before the next meeting of Finance Committee for ratification.

xii. The Finance Committee shall have the following powers and functions:

a. The Annual Accounts and Annual Budgets prepared by the Finance Officer shall be considered by the Finance Committee for its recommendations to the Executive Council for approval.

b. The Finance Committee may, after scrutiny of the proposal for expenditure, recommend limits on total recurring and non-recurring expenditure for the year, based on income and resources of the University.

c. To give its views on any financial matter solicited by an 'Authority' or an 'Officer' of the University.

xiii. The recommendations of the Finance Committee shall be implemented with the approval of the Executive Council.

## 23. THE PLANNING BOARD

i. The Planning Board shall consist of the following:

a. The Vice-Chancellor- Chairman;
b. The Pro-Vice-Chancellor(s);
c. Two nominees of the Trust;
d. Dean, School of Architecture and Planning;
e. University Engineer;
f. Dean of Students' Welfare;

g. One Architect and two other persons to be nominated by the Chancellor;
h. Two Officers of the University *nominated* by the Vice-Chancellor;
i. The Finance Officer;
j. The Vice-Chancellor may co-opt such other persons as may be considered necessary; and
k. The Registrar- Member Secretary.

ii. The term of office of ex-officio members shall be coterminous with their term in office they hold and by virtue of which they are members of the Planning Board.The term of office of nominated members shall be for a period of two years.

iii. The quorum of the meeting shall be one third of the total strength of the Planning Board.

iv. The decisions on all the matters considered by the Planning Board shall be made through majority votes of the members present and voting and in case of a tie, the matter shall be decided by the casting vote of the Chairman.

v. The Planning Board may advise the Executive Council on necessary infrastructure and academic support systems required as per the norms of the State Government/ UGC/ or a Regulatory authority;

Provided that the Planning Board shall provide the estimate of the expenditure likely to be incurred for such Infrastructure/ the academic support system.

vi. The Planning Board shall have at least two meetings in a year and the minutes thereof shall be reported to the Executive Council in its next meeting.

## 24. THE RESEARCH ADVISORY BOARD

i. The Research Advisory Board shall be constituted as under: [$]

i. The Vice-Chancellor- Chairman
ii. The Pro-Vice-Chancellor;
iii. Dean, Academic Affairs;
iv. Two Deans of Schools nominated by the Vice-Chancellor;
v. Out-side experts, not exceeding five, nominated by the Chancellor;

[$] *Amended vide 21st EC dated 29.12.2021*

vi. The Vice-Chancellor may co-opt one distinguished Scientist/ Professor from within or outside to any meeting of the Research Advisory Board, as and when necessary; and

vii. Dean, Research and Development - *Member Secretary*.

ii. All the members of the Research Advisory Board, other than the ex-officio members, shall hold membership for a term of two years.

iii. The Research Advisory Board shall meet as often as may be necessary but not less than two times during an academic year. The Board may devise its own procedure for the conduct of the meetings.

iv. The Research Advisory Board shall be the principal research body of the University and shall provide the larger holistic vision, the research to be undertaken, including prioritization of the research areas.

v. The Board will develop and house other knowledge capabilities that may include referral and participatory networks of scholars and industry experts.

vi. The Board may select e-resources such as e-journals, e-books, on-line lectures reference material and reference websites for students and faculty.

vii. The Board, shall develop, sustain and manage:

a. incubation/Innovation Centre, basic workshop for entrepreneurs;
b. develop business models and field test products and services; and
c. development of start-up ventures.

viii. The Board shall advise the Deans of Schools in matters relating to industry sponsored research and consultancy, as also in facilitating the faculty in procuring equipment necessary to conduct research / consultancy work, recruitment of project staff.

ix. The Board shall suggest necessary steps to improve the quality benchmark in the matter of research; as also filing of research patents and registration of designs. It will also work towards protection of IPRs and its awareness.

x. The Board shall monitor the quality of research publications as also shall provide guidance for submission of research proposals for funding by external agencies.

xi. The Board shall oversee all the issues related to bio-safety and ethics and help the Deans develop necessary safeguards against scientific misconduct and plagiarism.

xii. The Deans shall report every matter relating to plagiarism and scientific misconduct to the Board which will, after due consideration, make necessary recommendations to the competent authorities for appropriate penal action.

xiii. The recommendations made by the Research Advisory Board shall be reported to the Executive Council.

## 25. THE FACULTY BOARD

i. The Faculty Board of each of the School of study shall be constituted as under:

a. The Dean of School- Chairman;
b. All the Heads of the Departments;
c. All the Professors of the School;

Provided that if there is no Professor in a Department, the senior most Associate Professor shall be the member of the Faculty Board;

Provided further that the Department having no Associate professor as well, an Assistant Professor may represent the Department till appointment of a Professor/Associate Professor;

d. Two outside experts nominated by the Vice-Chancellor;

e. Special Invitees may be invited to the Faculty Board meetings, with the prior approval of the Vice-Chancellor. However the Special invitee shall not have any voting right.

ii. Powers & Functions of the Faculty Board:

a. The Faculty Board shall control and guide the Academic, Research and other activities of the various Departments of the School and shall:

(i) consider and approve the decisions taken by the Board of Studies of a Department;

(ii) approve the names of the examiners in each subject recommended by the Board of Studies of a Department; *and*

(iii) consider and approve the research proposals received from the Department before their submission to the Research Advisory Board.

b. In case it is not possible to convene the meeting of the Faculty Board for any reason, the Dean *of the School shall have* emergency powers to take a decision on behalf of the Faculty Board.

c. All the emergent decisions taken by the Dean shall be placed before the next meeting of the Faculty Board for ratification.

## 26. THE BOARD OF STUDIES

i. The Board of Studies shall normally be constituted for each of the Departments of a School;

Provided the Dean of the School, with the approval of the Vice-Chancellor may club one or more than one Department to constitute their Board of Study.

ii. The Board of Studies shall comprise as under:

a. The Head of Department- Chairman;

Provided that if the Board has been constituted by clubbing more than one Department, the senior-most Head of the Department or the senior-most Professor/Associate Professor/Assistant Professor shall be nominated as Chairman *of the Board of Studies* by the Dean of the School.

b. Three members of the faculty, one each from the categories of Professor, Associate Professor and Assistant Professor of the Department;

provided that the teachers involved in designing a particular course shall also be the special invitee to the meeting;

Provided further that if the number of teachers in a Department or the departments clubbed together to form the Board of Studies is less than nine (9), *the Vice-Chancellor may*

nominate all the teachers of such Departments to the Board of Studies.

c. Two experts from another University/Institution, nominated by Vice-Chancellor.

d. Two Experts with more than ten years of experience in Industry/ Research Organizations/ NGOs, etc. nominated by the Vice-Chancellor.

e. Two students nominated by the Dean on the recommendation of the Head of the Department.

iii. The Board of Studies shall be authorised to:-

a. examine and approve the course structure, credit details and the syllabi of each and every course proposed to be offered by the Department;

b. propose names of the examiners both internal and external;

c. ensure quality of teaching and research undertaken by the Department; and

d. make suitable recommendations on any other matter referred to it by an Authorities or Officer of the University.

iv. All the decisions of the Board of Studies shall be placed before the Faculty Board of the School for approval/ recommendations to the Academic Council,

## 27. THE ADMISSION COMMITTEE

i. The Admission Committee shall be constituted as under:

a. The Vice -Chancellor - Chairman;
b. The Pro-Vice-Chancellor(s);
c. The Registrar;
d. Dean Academic Affairs;
e. All the Deans of Schools;
f. Finance Officer;
g. Head, International Relations Division;
h. Three faculty members nominated by the Vice-Chancellor;
i. Any other official of the University co-opted by the Vice-Chancellor; and
j. Head of the Admission Cell - Member Secretary.

ii. The Admission Committee may appoint such other sub-committee(s) as it may deem necessary.

iii. Subject to the superintendence of the Academic Council, the Admission Committee shall lay down the minimum qualification, number of seats and the Fees to be charged for each of the programme of study and also the date(s) of the commencement and conclusion of the admission process;

Provided that in Council based courses, the decision of the Council concerned shall be final and binding.

iv. The admission made each academic year shall be reported to the Academic Council.

## 28. THE EXAMINATION COMMITTEE

i. The Examination Committee shall be constituted as under:

a. The Vice Chancellor – Chairman
b. The Pro-Vice-Chancellor(s);
c. The Registrar;
d. All the Deans of Schools;
e. Dean Academic affairs;
f. Three members nominated by the Vice-Chancellor;
g. The Controller of Examinations - Member-Secretary;

Provided that any Deputy Controller or an Assistant Controller of examinations appointed by the University shall have the right to attend the meetings and express their opinion, however they will not be eligible to vote.

ii. The Committee shall ensure smooth and fair conduct of all examinations of the University, including moderation and tabulation of the results.

iii. It shall scrutinize and recommend to the Academic Council the names of examiners received from School, for approval.

iv. It shall also ensure maintenance of high quality of the question bank and its availability to the students.

v. The Committee shall be authorised to take action, including debarment, in case any student found guilty of using unfair means at any examination; it may also take action against any paper setter, examiner, moderator or any other person connected with the conduct of an examination, found indulging in any malpractice.

vi. The Examination Committee shall review and analyse the results of examinations and submit its report to the Academic Council with its recommendations, if any, with regard to the improvement in the examination system.

vii. The Committee shall also get an audit conducted and make suitable recommendations to the Academic Council on the action proposed to be taken on the findings of such audit.

viii. The Examination Committee may appoint such other sub-committee(s) as it may deems fit, and may delegate to any one or more persons or sub-committees the powers for fair conduct of examination(s).

ix. The quorum of the meeting shall be one third of the total strength of the Examination Committee.

x. The Committee shall have at least two meetings, in an Academic Year.

## 28A UNIVERSITY LIBRARY COMMITTEE**

To ensure that the University Library functions in a robust manner, in the best interest of student community and the other stakeholders, it is important that a University Library Committee is duly constituted as under:

i. There shall be a University Library Committee consisting of the following Members, namely:

   a. Vice-Chancellor, who shall be the Chairman
   b. Pro-Vice-Chancellor, if any
   c. Deans of the Schools and Dean of Students' Welfare
   d. Registrar
   e. Finance Officer
   f. The senior most professor from each of the Schools to be appointed by the Vice-Chancellor by rotation in order of seniority
   g. University Librarian, who shall be the Convener

ii. The term of the Members of the Committee, other than the ex-officio, members, shall be a calendar year.

iii. The Committee shall:
   a. exercise general supervision over the University Central Library, and all the other libraries of the University;
   b. frame policy for the management and use of the libraries subject to the approval of the Academic Council;
   c. assess the requirements of the Library and other Libraries, and allocate funds to various Departments for submission to and approval by the Authorities concerned;

** *Amended - added vide 25th EC dated 22.12.2023*

d. submit to the Academic Council an Annual Report in respect of the working of all the libraries of the University;
e. formulate and administer proposals concerning the development of libraries of the University; and
f. recommend to the Executive Council the creation of any new post in the Libraries.

iv. The Committee shall meet at least twice in a year.

v. One-third of the total number of members shall constitute the quorum for a meeting.

The Convener, University Librarian, shall issue a Notice convening the meeting and a copy of the Agenda at least seven days before each Meeting. In case of the Extra- Ordinary Meetings, the notice and agenda has to be sent at least 24 hours in advance.

## 29. INTERNAL QUALITY ASSURANCE CELL

i. The University shall constitute an Internal Quality Assurance Cell consisting of the following members:

a. The Vice-Chancellor- Chairman
b. The Pro-Vice-Chancellor(s);
c. The Registrar;
d. Dean, Academic Affairs;
e. Deans of all the Schools;
f. Dean of Students' Welfare;
g. Controller of Examinations;
h. One member from industry/ employers to be nominated by the Chancellor;
i. Five experts nominated by the Chancellor;
j. Up to five faculty members to be nominated by the Vice-Chancellor;
k. Three students/ alumni nominated by the Vice-Chancellor;
l. Senior Administrative Official(s) nominated by the Vice-Chancellor; and
m. Director, IQAC - Convener

ii. It shall be ensured that there are at least five woman members nominated under various categories.

iii. Role and functions of the IQAC:

a. Development and application of quality benchmarks/parameters for various academic and administrative activities of the University.

b. Facilitating the creation of a learner-centric environment conducive to quality education and faculty maturation to adopt required knowledge and technology for participatory teaching and learning process.

c. Arrangement for feedback response *from students, parents and* other stakeholders on quality-related institutional processes and analysis thereof.

d. Dissemination of information on various quality parameters of higher education.

e. Organization of inter and intra *institutional workshops, seminars* on quality related themes and promotion of quality circles.

f. Documentation of the various programmes/activities leading to quality improvement.

g. Acting as a nodal agency of the University for quality-related activities, including adoption and *dissemination of best practices.*

h. Development and maintenance of institutional database through MIS for the purpose of maintaining/enhancing the institutional quality.

i. Development of Quality Culture in the University.

j. Preparation of the Annual Quality *Assurance Report for* submission to NAAC.

iv. The IQAC shall develop a mechanism for its robust functioning by optimising on the strength and contribution by the members.

v. The IQAC shall meet quarterly in a year *and shall periodically report* the progress made to the Chancellor for his information and guidance.

vi. Each member of the IQAC, except the *ex-officio* members, shall have a term of one year;

Provided the membership may be extended by another year to a maximum of total three years.

## 30. THE STUDENTS' COUNCIL

i. The Students Council shall be constituted each Academic year as below:

a. The Dean of Students' Welfare - Chairperson;

b. Associate/ Assistant Dean Students Welfare;

c. One student representative from each of the School of Studies nominated by the Dean on merit provided that the Schools having more than 500 students, may nominate one additional student for every block of 500 students or a fraction thereof;

d. five students to be nominated by the Vice-Chancellor on the recommendations of the Dean of Students' Welfare, keeping in view their participation and involvement in sports, co-curricular and extra-curricular activities;

provided that no student shall be nominated more than twice during the entire period of his studies in the university.

e. Associate Dean Students' Welfare - Member Secretary;

ii. A student shall be nominated to the Students' Council only if:

a. he has a minimum of 75 per cent attendance in all courses taken by him during the previous semester(s), except those who are in the first semester;

b. he must not have any academic arrear, i.e., he must have successfully completed all the courses in the previous semester;

*c.* he must not have any fee arrears; *and*

d. his conduct in the University must have been exemplary and he must not have been subjected to any disciplinary action.

iii. The Council shall meet at least twice in an academic year and shall recommend to the appropriate authorities on matters related with students' welfare and other matters of importance to them with regards to the cultural, social and recreational interests of students.

iv. Any student of the University may bring up any matter concerning the students welfare before the Students' Council, however he will be required to submit his proposal to the Chairman of the Council at least two weeks before the date of the meeting and if permitted by the Chairman, shall have the right to participate in discussions in the meeting when the said matter is taken up for consideration.

## CHAPTER IV (TEACHERS AND EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY)

### 31. MINIMUM QUALIFICATIONS OF TEACHERS

i. The minimum eligibility for Appointment and Career advancement of teachers in the University shall be as decided by the Executive Council and in line with the guidelines of the UGC/relevant Regulatory Authorities/Councils.

ii. The minimum qualification of teachers shall be those as may be prescribed by UGC regulations on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education, 2018, as amended form time to time.

### 32. THE APPOINTMENT OF TEACHERS AND OTHER ACADEMIC AND ADMINISTRATIVE STAFF

(1) The provision regarding appointment of teachers and other academics, including the composition of the Selection Committee would be as under:

**Teachers and other Academics:**

i. All regular/contractual appointments of teachers and other academic staff shall be made on the recommendation of a duly constituted selection committee.

ii. The Selection Committee for the posts of *Professors, Associate* Professors, Assistant Professors and other equivalent academics shall be constituted as below:

a. The Vice-Chancellor — *Chairman*;
b. One nominee of the Chancellor;
c. One outside subject expert nominated by the Vice-Chancellor;
d. Dean of the School;
e. One subject matter expert from within the University to be nominated by the Vice-Chancellor;
Provide if no subject expert is available within the University; the Vice-Chancellor may nominate experts from any other University;

f. Head of the Department;
Provided that a Head not holding the rank of a Professor shall not be a member of the selection committee for selection of a Professor; and
g. The Registrar — *ex-officio secretary*.

iii. Recommendations of Selection Committees will be placed before the Executive Council for its approval;

provided that in case the Executive Council disagrees with the recommendations of the selection committee the matter shall be referred to the Chancellor for decision; *and*
provided further that the Executive Council may authorise the Vice-Chancellor to approve the minutes of the Selection Committees and place them before the Executive Council in its next meeting.

iv. The University shall advertise its vacancies on the University website and as per the norms prescribed by the UGC or other competent authority.

v. The University is authorised to appoint a selected person for a fixed tenure on such terms and conditions as it may determine.

(2) The selection process of non-teaching positions, not included in these Statutes, shall be governed by the detailed Recruitment Rules/ Regulations for the non-teaching employees framed by the University and approved by the Executive Council. However, the composition of the Selection Committees for certain level of non-teaching employees is prescribed as under:

**Non-Teaching Positions, including Technical Staff in Teaching Departments:**

i. The composition of the Selection Committee for the Deputy Registrar and above shall be as under:
   a. Vice-Chancellor – *Chairperson;*
   b. Pro-Vice-Chancellor;
   c. A nominee of the Vice-Chancellor having expertise in administrative or financial matters;
   d. A Dean or Senior Professor nominated by the Vice-Chancellor;
   e. Registrar; and
   f. Deputy Registrar (HR) & equivalent – *Non-member Secretary*

ii. The Selection Committee of other non-teaching positions below the rank of Deputy Registrar may comprise of the following:
   a. Registrar or his nominee – *Chairperson;*
   b. A nominee of the Vice-Chancellor;
   c. An expert in Administration or Finance, nominated by the Vice-Chancellor;
   d. Deputy Registrar (HR) & equivalent – *Secretary*

iii. The Selection Committee in respect of Senior Technical Assistant/Technical Assistant/Laboratory Assistant in a School/Department shall consist of:
   a. Dean – *Chairperson;*
   b. Head of the concerned Department;
   c. Expert in the area, nominated by the Vice-Chancellor and
   d. Deputy Registrar of the School – *Secretary*

## 33. THE CONDITIONS OF SERVICE OF EMPLOYEES

i. Every salaried officer, teacher and other employees shall be appointed under a written contract on such terms and conditions as may be agreed to between the parties which shall be lodged with the University and a copy thereof shall be made available to the officer, teacher or the employee concerned

ii. The terms and conditions of service of all the employees of the University shall be provided in the Regulations as approved by the Executive Council. The Regulations may specify the conditions service as would be applicable to an employee and would generally include, but not be restricted to following:

a. Recruitment Rules
b. Faculty Development Policy
c. Consultancy Policy
d. Employee Welfare Policy
e. Employee Benefits
f. Career Progression Policy
g. SOP for creating New positions
h. Staff Development Policy
i. Performance Management
j. Pay & Allowances
k. Vacation, leave and holidays
l. Code of Conduct
m. Code of ethics
n. Exit Policy and Procedure
o. Superannuation Policy
p. Grievance Redressal Committee
q. Medical & Accidental Insurance
r. Entitlement to the Class of Travel
s. Policy relating to sexual harassment at workplace

## 34. DISCIPLINARY ACTION AGAINST TEACHERS OF THE UNIVERSITY

i. A teacher of the University shall at all times maintain absolute integrity and devotion to duty and shall observe the Code of Professional Ethics, which shall form part of the agreement to be signed by the teacher at the time of appointment.

ii. The breach of any of the provisions of the Code of Professional Ethics

prescribed by the University and/ or University Grants Commission or a regulatory authority/ body shall be deemed to be misconduct.

iii. A teacher of the University may be removed or his services terminated on one or more of the following grounds: -

a. willful neglect of duty;
b. misconduct;
c. breach of any of the terms of contract of service;
d. dishonestly connected with University Examination;
e. scandalous conduct or conviction for an offence involving moral turpitude;
f. physical or mental unfitness;
g. incompetence;
h. abolition of the post;

iv. No order of Dismissal, Removal or Termination of the services of a teacher, except on the ground of a conviction for an offence involving moral turpitude or on abolition of the post held by such teacher, shall be made until a charge sheet has been served upon him, clearly stating the grounds on which the action is proposed to be taken and after giving him an opportunity to;

a. submit a written statement in his defence;
b. present his case in person; and
c. producing a witness or witnesses in his defence as he may wish; provided that the Executive Council or an Officer authorized by it to conduct the inquiry, may, for sufficient reasons to be recorded in writing, refuse to call a witness(s);
provided further that the inquiry process shall be completed within a period of three weeks.

v. The Vice-Chancellor in his capacity as the Chairman of the Executive Council may, at any time from the date of receipt of the Inquiry report, pass an order dismissing or removing the teacher concerned from service or terminate his services mentioning *the ground of such dismissal*, removal or termination.

vi. The decision shall forthwith be communicated to the teacher concerned.

vii. The Vice-Chancellor may, instead of Dismissing, Removing or Terminating the services of a teacher, pass an order inflicting a lesser punishment such as reduction in rank and pay scale, reduction of pay for a specified period not exceeding three years and/ or stoppage of increments with cumulative or non-cumulative effect for a specified period or depriving the teacher of his pay during the period of his

suspension.

viii. The disciplinary action taken by the Vice-Chancellor, in his capacity as the Chairman of the Executive Council, shall be reported to the Executive Council in its next meeting for ratification.

ix. A teacher of the University shall be deemed to have been placed under suspension with effect from the date of his conviction;

a. when sentenced for a term exceeding forty-eight hours of imprisonment and if he has not yet been removed/dismissed from service;

b. if detained in custody, whether the detention is for any criminal charge or otherwise.

## 35. DISCIPLINARY ACTION AGAINST NON-TEACHING EMPLOYEES

i. In case of an allegation of misconduct against an employee of the University below the rank of Deputy Registrar, if deemed necessary, the registrar may place the employee under suspension by an order in writing and institute an Inquiry to inquire into the alleged charge(s).

ii. Based on the report of inquiry committee and severity of the misconduct, the Registrar may take disciplinary action, including removal/termination of services of the employee concerned.

iii. No disciplinary action shall be taken and penalties imposed, until the employee has been given a reasonable opportunity to show cause against the action proposed to be taken against him.

iv. The removal or termination of an employee shall take effect from the date on which the order of removal or termination is made.

v. An appeal against the order of the Registrar shall lie with the Vice-Chancellor

vi. Before initiating disciplinary action against the employees at the rank of Deputy Registrar and above, such as Directors, Joint Registrars, OSDs and OSD level Officers, the approval of the Vice-Chancellor will be necessary before taking an action;

provided that an appeal against the order of the Vice-Chancellor shall lie with the Executive Council.

vii. Notwithstanding anything contained in the terms of his contract of appointment, a non-teaching employee of the University below the

rank of Deputy Registrar may be removed from his services by the Registrar if the employee;

a. is of unsound mind and is an undercharged insolvent;
b. has been convicted by a court of law of any criminal offence or an offence involving moral turpitude and;
c. is otherwise guilty of misconduct;

Provided that for action against the employees at the level of Deputy Registrar and above, prior approval of the Vice-Chancellor will be needed;

Provided further that no employee of the University shall be removed or terminated from his service unless the employee has been given a reasonable opportunity to defend himself.

## CHAPTER V (MISCELLANEOUS PROVISIONS)

### 36. WITHDRAWAL OF DEGREE, DIPLOMA, CERTIFICATE AND OTHER ACADEMIC DISTINCTIONS

i. The Executive Council, on the recommendation of the Academic Council and by a special resolution passed by not less than two-third of the members present and voting, may consider withdrawal of a Degree or an Academic distinction conferred by the University, or any Certificate, Diploma or a Degree awarded by it;

Provided that the Academic Council shall not make such a recommendation until a show cause notice has been issued calling upon the charged person to show cause, within such time as may be specified in the notice, and until his reply and the evidence produced by him in his defence have been duly considered by the Academic Council;

Provided further that in case no reply is received within the time specified, the Academic Council may make its recommendations, based on the available material.

ii. The decision stating the reasons there for shall be communicated to the person concerned.

iii. Any person aggrieved by the decision taken by the Executive Council may appeal to the Chancellor within thirty days from the date of such decision.

### 37. INSTITUTION OF FELLOWSHIPS, SCHOLARSHIPS, STUDENTSHIPS, MEDALS AND PRIZES

Fellowships, Scholarships and Studentships, Medals and Prizes shall be instituted by the University in accordance with the Ordinances framed for the purpose.

### 38. MAINTENANCE OF DISCIPLINE AMONG THE STUDENTS

i. All powers relating to discipline and disciplinary action in relation to the students shall vest in the Vice-Chancellor.

ii. Without prejudice to the generality of his powers relating to the maintaining of discipline amongst the students of the University and taking desired action in the interest of maintaining discipline, the Vice- Chancellor shall be guided by the recommendations of the Chief Proctor or the Proctorial Committee and the provisions as laid down in the 'Students Code of Conduct and Ethics'.

iii. The Vice-Chancellor may delegate all or such of his powers, as he deems proper, except that of expulsion of a student from the University, to the Chief Proctor, and to such other persons as he may specify in this behalf.

## 39. THE ESTABLISHMENT AND ABOLITION OF SCHOOLS, DEPARTMENTS AND SPECIAL CENTRES

i. The Executive Council based on the recommendations of the Academic Council may approve establishment of a School, Department or a Special Centres of the University

ii. The University shall be authorized to offer such programmes, through its Schools and Departments, as the Executive Council may decide from time to time and as recommended by the Academic Council;

Provided that the programmes offered have no conflict with the guidelines issued by UGC;

Provided further that in Council-based Courses, the decision of the relevant Councils shall prevail.

iii. The Executive Council shall be authorized to reconstitute a School, a Department or a Special Centre on the recommendations of the Academic Council.

iv. The Executive Council, based on the recommendations of the Academic Council, may discontinue a Schools, a Department or a Special Centre when;

a. the programmes offered become obsolete;
b. the programmes offered become untenable to continue; or
c. alternate and better programmes become available.

Provided that while approving such discontinuation, the Executive Council shall ensure that the existing registered students in the programme are allowed to completion of the requirements of award of a degree.

## 40. THE DELEGATION OF POWERS VESTED IN AUTHORITIES OR OFFICERS OF THE UNIVERSITY

Subject to the provisions of the Act, any officer or authority of the University, may delegate his or its powers to any other officer or authority or person under his or its respective control and subject to the condition that overall

responsibility for the exercise of the power so delegated shall continue to vest in the Officer or Authority delegating such powers.

## 41. QUORUM

i. The quorum for holding the meetings of various authorities of the University shall be as laid down in these Statutes.

ii. The quorum for other committees and sub-committees appointed by any 'Authority' or the 'Officer' of the University shall be one third of their total strength;

Provided that fraction of a number shall be rounded off to the next whole number.

## 42. PROVISION FOR DIVERSITY IN NOMINATION ON THE VARIOUS BODIES OF THE UNIVERSITY

While nominating or co-opting members on various Statutory bodies, Committees and Sub- committees of the University, due regard shall be given to the gender and diverse socio-economic background, of the members proposed to be nominated co-opted;

## 43. CONFERMENT OF HONORARY DEGREES AND OTHER DISTINCTIONS

The Executive Council may, on the recommendations of the Academic Council, recommend the conferment of Honorary degrees or distinctions on eminent personalities for the exemplary contributions made by them in their respective field of specializations, to the State Government for approval before granting such honorary degrees and distinctions;

provided that in case no approval is received from the State Government within a period of one month from the date of submission of the proposal, the Executive Council may, on its own motion, recommend to the Chancellor the grant of such Honorary Degree/Distinction.

---